चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 14 मई–20 मई 2012 | मूल्य 5 रुपये

अपनी माटी से जुड़ते बिहारी कारोबारी

पेज-4

हर एक रक्षा सौदे के पीछे दलाल है

पेज-5

स्टिंग ऑपरेशन का षड्यंत्र

पेज-7

आप सांसद हैं देवता नहीं

पेज-9

नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद

प्रधानमंत्री की अग्नि परीक्षा

कश्मीर से जुड़े दस्तावेज़

मनीष कुमार

चौथी दुनिया को कुछ ऐसे दस्तावेज़ हाथ लगे हैं, जिनसे हैरान करने वाली सच्चाई का पता चलता है. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए. याचिकाकर्ताओं ने यह सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ दो-दो संगीन मामले कोर्ट में चल रहे हैं, क्या उसे सेनाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है. सरकार की तरफ़ से कोर्ट को यह बताया गया कि इन आरोपों की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो ने की है और इन्हें बेबुनियाद पाया है. हैरानी की बात यह है कि जब दोनों मामलों की जांच चल रही है, मामले अदालत में हैं, तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लीन चिट देने का अधिकार कैसे मिल गया, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो कोर्ट के फ़ैसले से पहले ही यह तय करती है कि किसी पर लगे आरोप सही हैं या ग़लत. हमारी तहक़ीक़ात से यह पता चलता है कि जो आरोप देश के होने वाले सेनाध्यक्ष पर लगे हैं, वे संगीन हैं और जो दलील सरकारी वकीलों ने दी है, उसमें कई राज छिपे हुए हैं.

इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय सेना की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. एक तरफ़ सरकारी कमेटी यह मान रही है कि हमारी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. दूसरी तरफ़ सेना में घोटालों की ख़बरें सामने आ रही हैं. इस बीच सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को सेनाध्यक्ष के लिए चुना है, जिसके ख़िलाफ़ दो-दो मामले चल रहे हैं. देश की जनता असमंजस में है. ऐसे ही आरोपों को लेकर देश के वरिष्ठ और ज़िम्मेदार नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिनमें पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास एवं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी आदि शामिल थे. कोर्ट में ज़बरदस्त बहस हुई (पढ़िए पेज 3), लेकिन सरकार की तरफ़ से जो दलील दी गई, वह और भी चौंकाने वाली थी. सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का काम अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का है, इसलिए कोर्ट ने यह पूछना उचित समझा कि क्या इस कमेटी को इन आरोपों के बारे में जानकारी थी या नहीं. सरकारी वकीलों ने कोर्ट को सारी जानकारी दे दी कि इन सभी आरोपों को कमेटी ने देखा और परखा है, उसके बाद यह फ़ैसला लिया गया है. इसलिए कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ़ से जो दलील पेश की गई, उससे कई गंभीर सवाल उठते हैं. पहला सवाल यह है कि रक्षा मंत्रालय ने किस आधार पर यह हलफ़नामा दिया कि मार्च 2001 का एनकाउंटर फर्ज़ी नहीं था. कश्मीर में सेना के सिवाय और कोई दूसरा दख़ल नहीं. फिर जब सेना की ही जांच पूरी नहीं हुई तो फिर यह हलफ़नामा क्यों दिया गया. दूसरा सवाल यह उठता है, जो वाकई गंभीर है कि यह हलफ़नामा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी. क्या जम्मू-कश्मीर की अदालत ने रक्षा मंत्रालय से उसका पक्ष जानना चाहा था या फिर रक्षा मंत्रालय ने ख़ुद ही यह हलफ़नामा दिया. क्या कश्मीर में हुए एनकाउंटर का फ़ैसला हो गया है. आई बी या रक्षा मंत्रालय किस आधार पर उस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, उसका सबूत क्या है.

एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि 15-ए नंबर का पेज अप्वाइंटमेंट कमेटी में कैसे जुड़ा. यह पेज नंबर 16 की जगह 15-ए कैसे बन गया. अप्वाइंटमेंट कमेटी की फाइल में जिन आरोपों की बात कही गई है, उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लीन चिट देने का क्या अधिकार है. जब मामलों की जांच हो रही है, मामले अदालत में हैं तो अप्वाइंटमेंट कमेटी द्वारा उन्हें नज़रअंदाज करने के पीछे क्या तर्क है. 13 अप्रैल को सेना ने रक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी संख्या-एमओडी आईडी नंबर-17(20)/2010-डी (जी.एस.आई) लिखी थी, जिसमें यह साफ़-साफ़ बताया गया था कि डिवीजन कमांडर और डिप्टी फोर्स कमांडर के रोल क्या हैं. फिर एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में इससे अलग बातें क्यों कहीं. सरकार ने यह बात क्यों छुपाई कि कांगो की घटना के बाद उप सेनाध्यक्ष को कांगो भेजा गया था. यह माना जा रहा है कि सैन्य टुकड़ियों की तैनाती में कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से वह कांड हुआ. तो भारतीय सैनिकों की तैनाती की ज़िम्मेदारी किसकी थी. क्या यह तय हो गया है कि किस अधिकारी की वजह से भारतीय सैनिकों की तैनाती गलत जगहों पर हुई. अगर तय हो गया है तो सरकार को बताना चाहिए और अगर नहीं हुआ है तो आई बी और अप्वाइंटमेंट कमेटी ने इस मिशन में शामिल लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को क्लीन चिट कैसे दे दी. ग़ौर करने वाली

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कांगो से जुड़े दस्तावेज़

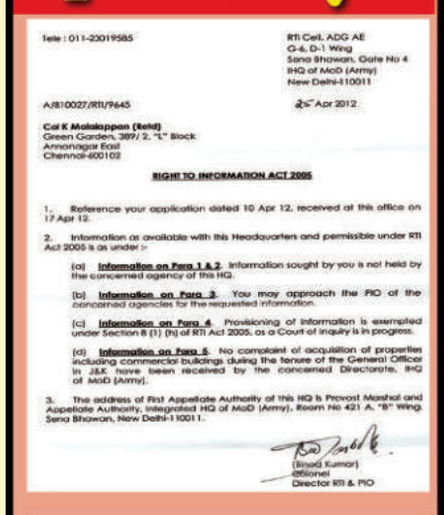

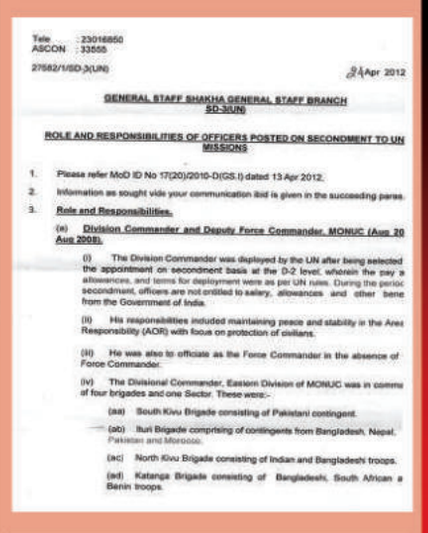

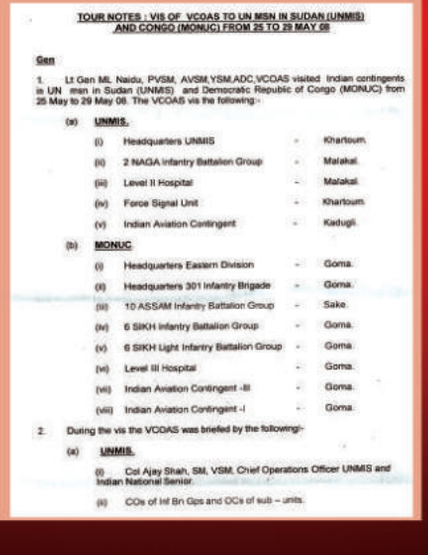

कोर्ट में क्या हुआ

बीते 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका में सरकार और भारतीय सेना के रिश्ते को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी. यह याचिका पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एल रामदास एवं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी सहित देश के छह वरिष्ठ लोगों ने दायर की थी. हमें यह मानना चाहिए कि इतने ज़िम्मेदार लोग अगर किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो मामला ज़रूर गंभीर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया. कोर्ट का फ़ैसला आ गया, मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, सरकार की फिर से जीत हो गई और एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह सभी लोगों ने कोर्ट के फ़ैसले का आदर किया. हम भी कोर्ट के फ़ैसले का आदर करते हैं, लेकिन यह फ़ैसला कई सवालों को जन्म देता है.

इस फ़ैसले का मतलब तो यही है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी संस्थानों के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो सकता है, भले ही उसके ख़िलाफ़ कितने भी गंभीर आरोप क्यों न हों. इस याचिका का मुख्य बिंदु यही था कि अगर किसी व्यक्ति, जिसके ख़िलाफ़ गंभीर आरोप हैं, जिसकी जांच हो रही हो, अदालत में सुनवाई हो रही हो, क्या उसकी शीर्ष पदों पर नियुक्ति जायज़ है. कोर्ट के फ़ैसले से पूर्व सीवीसी को झटका लगा होगा, क्योंकि उन पर भी घोटाले के आरोप लगे, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था. इस फ़ैसले के आधार पर पी जे थॉमस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यही फ़ैसला दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर लगे गंभीर आरोपों की जांच और सुनवाई जारी रहेगी और साथ ही साथ वह अगले सेनाध्यक्ष भी बन सकते हैं. एक सवाल उठता है कि अगर जांच या कोर्ट से यह पता चलता है कि जनरल बिक्रम सिंह पर लगे आरोप सही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 21 मुख्य संसदीय सचिव बनाने का अनोखा फ़ैसला लिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि विधानसभा सचिवालय में जगह की कमी हो गई है.

दिल्ली का बाबू

सीआईसी की परेशानी

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की व्यस्तता है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है. आरटीआई कार्यकर्ता इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले सूचना आयुक्तों की कमी के कारण निपटाए नहीं जा सके हैं. हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त सत्येंद्र मिश्रा एवं उनके सहयोगी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की कमी का खामियाज़ा तो विभाग को भुगतना ही पड़ रहा है. सूचना आयोग को दस सूचना आयुक्त दिए गए हैं, जिनमें तीन सूचना आयुक्तों राजीव माथुर, विजय शर्मा एवं वसंत सेठ की नियुक्ति दो महीने पहले हुई है. अगर दो और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है तो फिर सूचना आयोग के पास पर्याप्त आयुक्त हो जाएंगे. अब देखना यह है कि सरकार कब इस ओर ध्यान देती है. आरटीआई कार्यकर्ता इस बात से काफ़ी खफ़ा हैं कि सूचना आयोग में आयुक्तों की कमी के कारण मामले लंबित पड़े हैं. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई में सूचना का अधिकार कानून एक कारगर हथियार साबित हुआ है. ऐसे में अगर आयुक्तों की कमी के कारण यह विभाग मामलों का निपटारा सही समय पर नहीं कर पाया तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए. राजनीतिक नेतृत्व क्यों इतना सुस्त हो गया है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग की इस तरह अवहेलना की जा रही है.■

हरियाणा के नए मुख्य सचिव

पी के चौधरी को हरियाणा का मुख्य सचिव बनाया गया है. उन्होंने उर्वशी गुलाटी की जगह ली है, जो बीते 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुईं. पी के चौधरी ने केंद्र में कई ज़िम्मेदारियां निभाई हैं. वह वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रहे. हरियाणा को इसका फ़ायदा होगा. पी के चौधरी के मुख्य सचिव बनने से हरियाणा प्रशासन में कुछ परिवर्तन आएगा. चौधरी ने सरकार के सभी विभागों के लिए नागरिक चार्टर बनाना शुरू कर दिया है साथ ही सभी विभागों के लिए परफॉर्मेंस मॉनीटरिंग सिस्टम का इंतजाम किया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि चौधरी ने जिन विभागों में परिवर्तन की बात कही है, उनमें भूमि उपयोग बोर्ड, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग भी शामिल हैं. अब देखना यह है कि चौधरी कितना परिवर्तन कर पाते हैं. इन परिवर्तनों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा. ■

पंजाब के बाबुओं की नई परेशानी

पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों से यहां के कुछ बाबुओं को आश्चर्य हुआ था, लेकिन इसके अलावा चुनाव के बाद एक और समस्या कुछ बाबुओं के सामने आ गई है, जिससे वे परेशान हैं. मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 21 मुख्य संसदीय सचिव बनाने का अनोखा फ़ैसला लिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि विधानसभा सचिवालय में जगह की कमी हो गई है. इस समस्या से निपटने के लिए केवल एक उपाय है कि पहले के अधिकारियों को जो कमरे दिए गए हैं, उनमें नए लोगों को भी एडजस्ट किया जाए. ऐसा कहा भी गया है. जिन अधिकारियों को अपना कमरा शेयर करना है, उनमें अतिरिक्त सचिव एम आर अग्रवाल, वित्त सचिव जे एम बालामुरुगन और गृह एवं न्याय सचिव जी के गंथा भी शामिल हैं. इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति आयोग को भी कहा गया है कि उसे दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी. वैसे पंजाब के बाबुओं को पहले से ही सरकारी गाड़ी की समस्या से जूझना पड़ रहा है. अब देखना यह है कि बादल कितनी जल्दी बाबुओं की समस्या को निपटाते हैं.■

dilipcherian@gmail..com

दिलीप चेरियन

साउथ ब्लॉक

नरेंद्र भूषण संयुक्त सचिव बनेंगे

1992 बैच के आईएएस अधिकारी नरेंद्र भूषण को कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है. वह सुभाष चंद्र गर्ग की जगह लेंगे.

प्रेमचंद वलेटी और अंकिता मिश्रा निदेशक बनेंगे

1994 बैच के आईडीईसी अधिकारी प्रेमचंद वलेटी को वाणिज्य विभाग में निदेशक बनाया जा सकता है. वह श्रवण कुमार की जगह लेंगे. इसी तरह 2001 बैच की आईएएस अधिकारी अंकिता मिश्रा को उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक बनाया जा सकता है. वह रश्मि चौधरी की जगह लेंगी

आमोल भीमराव उप महानिदेशक बने

2002 बैच के आईआरएस (आईटी) अधिकारी आमोल भीमराव किरताने को जहाज रानी मंत्रालय में उप महानिदेशक बनाया गया है. वह सैमुएल डार्से की जगह लेंगे.

शशि शेखर राजस्व विभाग में गए

1981 बैच के आईएएस अधिकारी शशि शेखर को राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह अमिताभ राजन की जगह लेंगे.

संजय कुमार कार्यकारी निदेशक बने

1992 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार खाद्य एवं जन वितरण विभाग के अंतर्गत नोएडा एफसीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं. वह प्रदीप कुमार पुजारी की जगह लेंगे.

विक्रम सिंह राणा जीएम बने

1999 बैच के आईआरटीएस अधिकारी विक्रम सिंह राणा खाद्य एवं जन वितरण विभाग के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बनाए गए हैं.

बलविंदर कुमार एएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी बलविंदर कुमार को कृषि एवं सहकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह अमरजीत सिंह लांबा की जगह लेंगे. ■

प्रधानमंत्री की अग्नि परीक्षा

पृष्ठ एक का शेष

बात यह है कि इस मामले की जांच मेरठ में चल रही है.

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह से संबंधित दो मामले चल रहे हैं. सबसे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में चल रहे मामले की बात करते हैं. यह एनकाउंटर एक मार्च, 2001 को अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाक़े में हुआ. इसमें कर्नल जे पी जानू और पांच अन्य लोगों की मौत हुई थी. साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह घायल हुए थे. सेना के सूत्रों के मुताबिक़, यह इलाक़ा 15 कोर की विक्टर फोर्स के अंतर्गत आता है और यह जंगलात मंडी अनंतनाग 1 आरआर सेक्टर में आता है. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह उस वक़्त ब्रिगेडियर हुआ करते थे और 1 आरआर सेक्टर के कमांडर थे. जंगलात मंडी काफ़ी मशहूर जगह है और इसलिए, क्योंकि किसी जमाने में वहां आतंक का साया था और बाद में बड़ी संख्या में इखवानी जमा हो गए. इखवानी ऐसे लोगों को कहा जाता है, जो पहले कभी आतंकवादी होते थे और जो सरेंडर करके टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन गए. जिन इलाक़ों में इखवानियों की संख्या ज़्यादा होती है, वे सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें आतंकवादियों की सारी गतिविधियों का पता रहता है. जंगलात मंडी पूरी तरह से इखवानियों की वजह से सुरक्षित इलाक़ा माना जाता था. सेना के सूत्रों के मुताबिक़, ताहिर शेख नाम का स्थानीय आतंकवादी सेना के सामने सरेंडर करके टेरिटोरियल आर्मी के साथ काम करने लगा था. ताहिर शेख का उस इलाक़े में ऐसा दबदबा था कि कोई आतंकी वहां घुसने की जुर्रत नहीं कर सकता था. सूत्रों के मुताबिक़, बिक्रम सिंह ने इसी ताहिर शेख की मदद से एक योजना बनाई कि एक मार्च को वह बिना प्रोटेक्शन के बाज़ार जाएंगे और फर्नीचर की दुकान के पास जब वह पहुंचेंगे तो कुछ लोग हवाई फायर करेंगे और वह भी हवाई फायर करेंगे और फिर दोनों तरफ़ के लोग वापस हो जाएंगे. योजना के मुताबिक़, बिक्रम सिंह बाज़ार में उस फर्नीचर की दुकान के सामने पहुंचे. दरवाजा खोला और बाहर खड़े हो गए. दुकान की छत पर कुछ लोग बैठे थे, जिन्हें ताहिर शेख ने भेज रखा था. सब कुछ योजना के मुताबिक़ चल रहा था, तभी एक चूक हो गई. पास में ही बिहार रेजीमेंट की 120 इफेंट्री बटालियन के कर्नल जय प्रकाश जानू को किसी ने बताया कि ब्रिगेडियर बिक्रम सिंह बाज़ार में आए हुए हैं तो वह वहां पहुंच गए. इधर योजना के मुताबिक़, दोनों तरफ़ से हवाई फायरिंग होनी थी, लेकिन जब कर्नल जानू ने देखा कि छत से गोलियां चल रही हैं तो उन्होंने अपना हथियार उठाया और गोलियां चलानी शुरू कर दी. ताहिर शेख के आदमियों को लगा कि गोलियां सीधे उनकी तरफ़ आ रही हैं तो हवाई फायर करने के बजाय उन्होंने अपनी बंदूक की दिशा बदल दी और नाल को नीचे झुका दिया. दोनों तरफ़ से गोलियां चलीं. छत से निशाना साधना आसान था, इसलिए कर्नल जे पी जानू वहीं पर शहीद हो गए. बिक्रम सिंह अपनी गाड़ी से कूद पड़े, लेकिन उन्हें गोली लग गई और वह घायल हो गए. इस फायरिंग में एक दुकानदार और एक सत्तर वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई. पुलिस आई, सेना आई, उस वृद्ध को मतीन चाचा बताया गया और उसे एक पाकिस्तानी आतंकी क़रार दिया गया. मीडिया में इस एनकाउंटर को लेकर कई ख़बरें पहले भी आ चुकी हैं. सेना आज इस तरह से पोलराइज हो चुकी है कि हर बात पर

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर दूसरा आरोप कांगो में महिलाओं पर हुए अत्याचार का है. यह मामला 2008 का है, जब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को कांगो भेजा गया था. एक भारतीय ब्रिगेड पर महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप लगा. इस मामले की जांच मेरठ में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में चल रही है.

मोटिव डाल दिया जाता है. वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि सेना के सूत्रों ने जो जानकारी दी, वह सही नहीं हो सकती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि क्या सत्तर साल का बूढ़ा आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी आतंकवादियों को पकड़ा गया है, वे ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल के होते हैं. पहाड़ पर रहने वाले लोगों के घुटने तो वैसे भी 45 साल के बाद कमज़ोर हो जाते हैं. इस घटना के बाद उस वृद्ध की मां और बहन उसे ढूंढते हुए पहुंचीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें भगा दिया. लाश तक नहीं दिखाई और उसे दफ़ना दिया. कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि जब तक मामला सिर के ऊपर नहीं जाता है, हमारे देश में अपने लोगों के ख़िलाफ़ जांच करने की परंपरा नहीं है. वे दोनों महिलाएं न्याय के लिए भटकती रहीं. उन्होंने कुछ लोगों की मदद ली और अक्टूबर 2011 में जैतूना बेगम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. उस याचिका में बताया गया कि पुलिस जिसे मतीन चाचा बता रही है, वह दरअसल उसका बेटा अब्दुल्ला है. कोर्ट से यह गुहार लगाई गई कि उसकी लाश का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ताकि यह तय हो सके कि वह पाकिस्तानी नहीं, उनका बेटा अब्दुल्ला है. हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि यह एनकाउंटर फर्ज़ी नहीं था. वैसे रक्षा मंत्रालय इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, यह सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब सेना ने कोई जांच ही पूरी नहीं की है, कोई रिपोर्ट नहीं दी है, तब रक्षा मंत्रालय ने किस आधार पर यह हलफ़नामा दिया. अगर सरकार इस मामले में सच्चाई का पता लगाना चाहती है तो वह फौरन मतीन चाचा की लाश का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि जब तक यह तय नहीं होता कि वह 70 वर्षीय व्यक्ति कौन है, वह हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, तब तक इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान बने रहेंगे.

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर दूसरा आरोप कांगो में महिलाओं पर हुए अत्याचार का है. यह मामला 2008 का है, जब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को कांगो भेजा गया था. एक भारतीय ब्रिगेड पर महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप लगा. इस मामले की जांच मेरठ में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में चल रही है. सरकार की तरफ़ से यह दलील दी जा रही है कि वह सेना के इंचार्ज नहीं थे, जबकि सेना के दस्तावेज़ साफ़ -साफ़ बताते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या थी. दस्तावेज़ यह भी बताते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक़, सिर्फ़ 16 प्वाइंट्स पर सैनिकों की तैनाती करनी थी, लेकिन 39 प्वाइंट्स पर सैनिकों को तैनात किया गया. कहने का मतलब यह है कि सेना को उन जगहों पर तैनात किया गया, जहां तैनात नहीं करना चाहिए था. यह एक चूक थी. अब सवाल यह है कि इस चूक के लिए ज़िम्मेदार कौन है. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह मामला चल रहा है और जब तक यह मामला चल रहा है तो सरकार ने किसी भी अधिकारी को क्लीन चिट क्यों और कैसे दे सकती है.

रामायण में राजा के कर्तव्यों के बारे में एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है. भगवान राम ने सिर्फ़ एक अफ़वाह के चलते अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया था. अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी एक अफ़वाह फैली हुई है. जनरल वी के सिंह के उम्र विवाद और लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह की नियुक्ति से जुड़े विवादों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम घसीटा जा रहा है. वह इसलिए, क्योंकि अप्वाइंटमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं. देश के वरिष्ठ और ज़िम्मेदार नागरिक इसे साज़िश के रूप में देख रहे हैं. इन अफ़वाहों को रोकना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ज़िम्मेदारी है. इसके लिए उन्हें भगवान राम की तरह अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है. वह संसद में इस मामले पर सरकार के फ़ैसले पर पूरी सफाई दे दें, ताकि इन अफ़वाहों को विराम दिया जा सके. इससे अफ़वाहों का बाज़ार ठंडा पड़ जाएगा और सेना एवं सरकार की प्रतिष्ठा भी बच जाएगी. ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 10
दिल्ली, 14 मई–20 मई 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888, 6452888, 011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कोर्ट का फ़ैसला चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुनाने के बजाय मध्यस्थ का रोल अदा किया.

कोर्ट में क्या हुआ

पृष्ठ एक का शेष

क्या सरकार सेना जैसी संस्था पर इस तरह का जोखिम ले सकती है या फिर सरकार ने कोर्ट के फ़ैसले से पहले ही यह मान लिया है कि जनरल बिक्रम सिंह बेकसूर हैं. सरकार की यह कैसी ज़िद है. सरकार क्यों बिक्रम सिंह पर लगे आरोपों को नज़रअंदाज़ कर रही है. जबकि हमारी तहकीकात यह बताती है कि जनरल बिक्रम सिंह पर लगे आरोप गंभीर हैं और भविष्य में ये मामले सरकार की किरकिरी का कारण बन सकते हैं.

कोर्ट का फ़ैसला चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुनाने के बजाय मध्यस्थ का रोल अदा किया. इस बार भी वही बेंच इस याचिका की सुनवाई कर रही थी, इसलिए याचिका की सुनवाई के दौरान जब भी कोई मामला जनरल वी के सिंह से जोड़ा गया तो कोर्ट ने उस दलील को यह कहकर दरकिनार कर दिया कि यह मामला अब सरकार के हाथों में है. इस याचिका में भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे जे सिंह पर साज़िश रचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी. इसके अलावा इस याचिका में लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर कश्मीर में एक फर्ज़ी एनकाउंटर का आरोप है और दूसरा कांगो में भारतीय सेना द्वारा महिलाओं के शारीरिक शोषण का मामला है. अब सवाल तो यही है कि अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इन दोनों आरोपों को क्यों नज़रअंदाज़ कर दिया. यही सवाल इस याचिका में भी पूछा गया था. ऐसा ही कुछ मामला पूर्व सीवीसी पी जे थॉमस का था, फिर वही मापदंड जनरल बिक्रम सिंह की नियुक्ति में क्यों लागू नहीं हुआ.

जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने पी जे थॉमस को सीवीसी नियुक्त किया और जब कोर्ट में इसे चुनौती दी गई, तब चीफ जस्टिस एस एच कपाड़िया, जस्टिस के एस राधाकृष्णन एवं जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने न सिर्फ़ नियुक्ति रद्द की, बल्कि संस्थान की शुद्धता और पूर्णता को लेकर सरकार को फटकारा भी था. कोर्ट ने कहा कि सरकार को ऐसी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्र हित को सामने रखना चाहिए. याचिकाकर्ता सैम राजप्पा के मुताबिक, पी जे थॉमस के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक मामला केरल की अदालत में चल रहा है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के ख़िलाफ़ दो-दो मामले चल रहे हैं. कश्मीर में फर्ज़ी एनकाउंटर का मामला जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में चल रहा है और कांगो में महिलाओं के शारीरिक शोषण की जांच मेरठ में लंबित है, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज़ कर दिया. सैम राजप्पा का आरोप है कि राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए दोनों ही मामलों में देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी.

सुनवाई की शुरुआत में कामिनी जायसवाल ने अपनी बातों को रखा और सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती एवं सॉलिसिटर जनरल आर एफ नरीमन दलील रख रहे थे. सरकारी वकीलों की तरफ़ से पहली दलील यह दी गई कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद को फिर से हवा देने के लिए इस याचिका का सहारा लिया गया है. कोर्ट ने शुरुआत में ही यह कह दिया कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि से जुड़ी कोई बात नहीं होगी, 10 फरवरी को जन्मतिथि विवाद का निपटारा किया गया था. सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब तक सरकार ने स्टैचूरी कंप्लेन का जवाब क्यों नहीं

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

कांगो के मामले पर भी कामिनी जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि बिक्रम सिंह वहां बतौर डिप्टी फोर्स कमांडर तैनात थे और वह ईस्टर्न डिवीजन के कमांडर थे और तीन ब्रिगेड सीधे तौर पर उनकी निगरानी एवं अधिकार क्षेत्र के अंदर थीं. जबकि एटॉर्नी जनरल यह कहते रहे कि वह डेप्यूटेशन पर एक सिविल सर्वेंट के तौर पर गए थे और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के दूसरे स्थान के अधिकारी थे, इसलिए शारीरिक शोषण मामले की ज़िम्मेदारी ब्रिगेड कमांडर पर है. एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर लगे सारे आरोपों की जांच की है और उसके मुताबिक़, ये सारे आरोप झूठे हैं.

दिया और इस ख़बर के लिखे जाने तक सरकार ने जनरल वी के सिंह के लिए लीगल रिटायरमेंट ऑर्डर क्यों जारी नहीं किया. सरकार ने यह मामला अब तक क्यों लटका रखा है. बहस के दौरान एक और बात सरकारी वकील ने दलील के रूप में पेश की कि यह याचिका सांप्रदायिक है. यह दलील मीडिया में पहले से आ चुकी थी. जब यह याचिका लीक कर दी गई, तब इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे सांप्रदायिक बताया था. याचिकाकर्ता सैम राजप्पा के मुताबिक़, इस याचिका में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर याचिका पर गौर करें तो इसमें यह लिखा है कि ऐसे सबूत हैं, जिनसे लगता है कि जनरल जे जे सिंह की नियुक्ति में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन याचिका की अगली लाइन में यह लिखा हुआ है कि अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ. सवाल यह है कि सिर्फ़ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम आ जाने से कोई याचिका सांप्रदायिक कैसे हो सकती है.

कामिनी जायसवाल के आग्रह पर कोर्ट ने एसीसी की फाइल मंगवाई. कोर्ट ने सिर्फ़ यह सवाल पूछा कि नियुक्ति के वक़्त अप्वाइंटमेंट कमेटी ने क्या इन मामलों को संज्ञान में लिया अथवा नहीं. कोर्ट में एटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेना ने स्वयं एक हलफ़नामा दिया है, जिसमें यह लिखा है कि वह एनकाउंटर फर्ज़ी नहीं था. वाहनवती ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उस एनकाउंटर में लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को भी गोली लगी थी. हालांकि ग़ौर करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता इस केस की डिटेल नहीं, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस एनकाउंटर के मुख्य किरदार लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह हैं और मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि इस मामले पर जस्टिस गोखले ने कहा कि इस एनकाउंटर का फ़ैसला इस बात से होगा कि 70 साल का बूढ़ा, जो इस दौरान मारा गया, वह हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी. अगर वह पाकिस्तानी निकला तो इस एनकाउंटर को सही माना जाएगा और अगर हिंदुस्तानी निकला तो इसका मतलब है कि एनकाउंटर फर्ज़ी है. जब अप्वाइंटमेंट कमेटी की फाइल कोर्ट में पेश की गई, तब कामिनी जायसवाल ने यह सवाल खड़ा किया कि पिछले सप्ताह जो हलफ़नामा भारत सरकार द्वारा दायर किया गया है, वह सेना की तरफ़ से नहीं, बल्कि रक्षा मंत्रालय की तरफ़ से दिया गया है. सेना ने इस मामले में अब तक कोई जांच पूरी नहीं की है. इस पर एटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हलफ़नामे पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के दस्तख़त हैं, इसलिए इसे सेना का हलफ़नामा माना जाए. हक़ीक़त यह है कि रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालय को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह पूछा गया था कि एनकाउंटर की जांच की स्थिति क्या है. इस पर सेना मुख्यालय ने यह जवाब दिया था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इस मामले की जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिक्रम सिंह को दोषमुक्त नहीं माना जा सकता है.

कांगो के मामले पर भी कामिनी जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि बिक्रम सिंह वहां बतौर डिप्टी फोर्स कमांडर तैनात थे और वह ईस्टर्न डिवीजन के कमांडर थे और तीन ब्रिगेड सीधे तौर पर उनकी निगरानी एवं अधिकार क्षेत्र के अंदर थीं. जबकि एटॉर्नी जनरल यह कहते रहे कि वह डेप्यूटेशन पर एक सिविल सर्वेंट के तौर पर गए थे और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के दूसरे स्थान के अधिकारी थे, इसलिए शारीरिक शोषण मामले की ज़िम्मेदारी ब्रिगेड कमांडर पर है. एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर लगे सारे आरोपों की जांच की है और उसके मुताबिक, ये सारे आरोप झूठे हैं. अप्वाइंटमेंट कमेटी की फाइल में यह पेज नंबर 15-ए पर दिया गया है. इस बात पर कामिनी जायसवाल एवं प्रशांत भूषण उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह अधिकार ही नहीं है कि वह इस तरह का निर्णय सुना सके और अगर ऐसा होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. लेकिन कोर्ट में इस बात पर बहस नहीं हुई और बेंच ने कहा कि ये मामले अप्वाइंटमेंट कमेटी के सामने आए और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह की नियुक्ति हुई है, इसलिए इस याचिका को खारिज़ किया जाता है. ■

हंस चुनेगा दाना-तिनका कौआ मोती खाएगा

अजीब इत्तेफ़ाक़ है. कामिनी जायसवाल ने इस पीआईएल को रजिस्ट्रार के पास जमा किया और अपने केबिन में लौट आईं, इतनी ही देर में यह पीआईएल मीडिया में लीक हो गई. उन्हें किसी ने बताया कि इसमें क्या है, यह मीडिया के लोगों को पता चल चुका है. जब इस पीआईएल की सुनवाई शुरु हुई तो जज ने पहला सवाल कामिनी जायसवाल से पूछा कि किसने लीक की. जबकि तब तक यह बात आम हो चुकी थी कि यह लीक सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ के दफ्तर से हुई थी. इसे दो अख़बारों को दिया गया था. कामिनी जायसवाल ने जज से यह भी कहा कि उन्हें जब इसका पता चला, तब उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन जज ने कामिनी जायसवाल की बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया. इस लीक से पीआईएल दायर करने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा. लीक होने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने इस पीआईएल के बारे में ख़बर छापी. दोनों ही अख़बारों ने लिखा कि यह पीआईएल कम्युनल है. अजीब इत्तेफ़ाक़ यह भी है कि कोर्ट में सरकार के एटॉर्नी जनरल ने भी यही दलील दी कि वरिष्ठ और ज़िम्मेदार नागरिकों, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की याचिका कम्युनल है. हालांकि यह याचिका पढ़कर लगता तो नहीं है, लेकिन अगर याचिकाकर्ता यह कहें कि पूर्व सेनाध्यक्ष जे जे सिंह ने उत्तराधिकारियों की सूची बनाने की साज़िश रची, जिसमें राजनीतिक नेता, पूर्व सेनाध्यक्ष और लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह शामिल हैं, तब सवाल यह उठता है कि साज़िश रचने वालों में कोई तमिल, कोई बंगाली, कोई राजस्थानी, कोई मणिपुरी भी हो सकता था, लेकिन ये सब एक ही बिरादरी के हैं तो याचिकाकर्ताओं की इसमें क्या ग़लती है और यह बात किस हिसाब से सांप्रदायिक हो जाती है. मज़ेदार बात यह है कि लगातार मीडिया में जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ एक कैंपेन सा चल रहा है. इंडियन एक्सप्रेस ने तो हद कर दी थी. मित्रता निभाने के चक्कर में इस अख़बार के संपादक ने भारतीय सेना के माथे पर ऐसा कलंक लगा दिया, जिसे हरगिज नहीं मिटाया जा सकता है. जब सभी ज़िम्मेदार लोगों ने इस रिपोर्ट को बकवास बताया, तब भी अख़बार अपनी ज़िद पर अड़ा रहा. अगले दिन उसने यहां तक लिखा कि रक्षा मंत्री ने सेना के मूवमेंट की बात मानी, लेकिन वह रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल पर चुप रहा. बाद में (5 अप्रैल को) उसने यहां तक लिखा कि सरकार सेना की टुकड़ियों के मूवमेंट पर स्टैंडिंग कमेटी को भरोसे में नहीं ले सकी, जबकि 30 अप्रैल को जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट आई तो उसमें शेखर गुप्ता की रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया गया. माफ़ी मांगने के बजाय शेखर गुप्ता अपने अख़बार का इस्तेमाल जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ कैंपेन में करते रहे. कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी उनका हमला जारी है. टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक इंदर मल्होत्रा, जो आजकल द ट्रिब्यून में लिखते हैं और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक शेखर गुप्ता ने इस मामले पर लेख लिखे. दोनों के लेखों को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि दोनों ने एक ही बात लिख दी कि यह पीआईएल सिखों के ख़िलाफ़ है, यह एक कम्युनल पीआईएल है. इनके लेखों देखकर लगता है कि जैसे दोनों महान पत्रकारों ने आपस में बातचीत करने के बाद लिखा हो. यह भी हो सकता है कि इन्होंने खुद न लिखा हो, बल्कि किसी ने इन दोनों से लिखवाया हो. इस पूरे मामले को सांप्रदायिकता की तरफ़ मोड़ने का उद्देश्य तो साफ़ है कि याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल बना दिया जाए कि कोई मीडिया उनकी बात न छापे, न दिखाए और वे बैकफुट पर चले जाएं. इस तरह की ख़बरें आते ही कई सिख सैन्य अधिकारी नाराज़ हो गए. उन्होंने इन ख़बरों को सच मान लिया. कुछ लोगों ने याचिकाकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर नाराज़गी व्यक्त की. दरअसल, इस याचिका में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में यह लिखा था कि उसने जनरल जे जे सिंह की नियुक्ति में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी. साथ ही यह लिखा हुआ था कि इसका असर सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर नहीं हुआ. शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लंगर के बारे में काफ़ी ज़िक्र किया. जो लोग सेना को जानते हैं, उन्हें यह भी पता है कि सेना में किचन यानी रसोई को लंगर कहा जाता है. याचिका में दिए गए इस शब्द का मतलब सिखों के लंगर से कतई नहीं था, इसका मतलब किचन टॉक है. देश के जाने-माने वरिष्ठ एवं ज़िम्मेदार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के एक मुद्दा उठाया था, ताकि हिंदुस्तान की सेना का सिर गर्व से ऊंचा हो सके. उन लोगों ने सेना और सरकार के बीच के रिश्ते को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह कलयुग है. इस युग में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने वाले लोगों की कद्र होती है. जिन लोगों ने देश को सुधारने की कोशिश की, वे हार गए और जिन्होंने एक याचिका को सांप्रदायिक बताया, वे जीत गए. लगता है, देश को सुधारने के लिए सतयुग का इंतज़ार करना पड़ेगा. ■

इंडियन एक्सप्रेस ने तो हद कर दी थी. मित्रता निभाने के चक्कर में इस अख़बार के संपादक शेखर गुप्ता ने भारतीय सेना के माथे पर ऐसा कलंक लगा दिया, जिसे हरगिज नहीं मिटाया जा सकता है. माफ़ी मांगने के बजाय शेखर गुप्ता अपने अख़बार का इस्तेमाल जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ कैंपेन में करते रहे. कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी उनका हमला जारी है.

राहुल गांधी ने अमेठी दौरे के तीसरे और आख़िरी दिन कहा कि तीन महीने के अंदर वह अमेठी की तस्वीर बदल देंगे. कांग्रेस संगठन में नीचे से ऊपर तक बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की बात भी उन्होंने कही.

अपनी माटी से जुड़ते बिहारी कारोबारी

अभिषेक रंजन सिंह arsingh@chauthiduniya.com

कुछ साल पहले देश में यह धारणा बन चुकी थी कि बिहार में उद्योग-धंधे लगाना किसी भी क़ीमत पर संभव नहीं है. ऐसा मानने वालों का तर्क था कि राज्य में कोई औद्योगिक माहौल ही नहीं है, क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाओं से लेकर आधारभूत संरचनाओं की घोर कमी है. साथ ही कोई उद्योग और उद्योगपति इस माहौल में सुरक्षित रहकर अपनी पूंजी बचा ले तो बड़ी बात होगी. जो लोग ऐसा सोचते और कहते थे, उनकी बातों को सिरे से ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक समय बिहार में वाक़ई ऐसा वातावरण बन चुका था. आम आदमी हो या कारोबारी, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी. यही वजह थी कि अराजकता भरे माहौल से ऊब कर हज़ारों व्यवसायी बिहार से पलायन कर गए और उन्होंने दूसरे राज्यों में कारोबार खड़े किए, लेकिन समय और सत्ता परिवर्तन के बाद ये लोग अब अपने गृह राज्य में वापस आने लगे हैं. इसे राज्य के भविष्य के लिए एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है.

प्राचीन काल से ही बिहार कारोबारियों के लिए पसंदीदा स्थान रहा है. बौद्ध काल हो या मध्य काल या फिर ब्रिटिश काल, इन सभी कालखंडों में बिहार और वहां बहने वाली नदियां देशी-विदेशी कारोबारियों के लिए सहज और सुगम मार्ग रही हैं. आज़ादी के बाद सरकारी उदासीनता और ख़ुद बिहार के नेताओं द्वारा राज्य के प्रति दिलचस्पी न लेने की वजह से यहां के कारोबारी दूसरे प्रदेशों में अपने उद्योग-धंधे लगाने को मजबूर हो गए. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई समेत कई महानगरों और शहरों में बिहार के उद्यमियों ने कठिन परिस्थितियों में ख़ुद को स्थापित किया. कोलकाता की बात करें तो यह बिहार का सबसे नज़दीकी महानगर है. यही वजह है कि बिहार के लोग काफ़ी तादाद में यहां कई तरह के उद्योग-धंधों से जुड़े हैं. उल्लेखनीय है कि कोलकाता में स्टेशनरी का थोक कारोबार होता है. यहां काम करने वाले या इस धंधे के संचालक मूलत: बिहार के हैं. एक अनुमान के मुताबिक़, स्टेशनरी का यह कारोबार करोड़ों रुपये का है. यहीं से तैयार माल देश के दूसरे राज्यों में जाता है. चूंकि यह धंधा पश्चिम बंगाल में स्थापित है. अत: इससे वहां की सरकार को राजस्व मिल रहा है. अगर यही कारोबार बिहार में होता तो उससे यहां के लोगों को रोज़गार के साथ-साथ सरकारी ख़ज़ाने को भी लाभ मिलता. उसी तरह अहमदाबाद और सूरत में भी हज़ारों लोग कपड़े, ज़ेवरात और जरदोज़ी के कारोबार से जुड़े हैं. वैसे तो कहा यह जाता है कि गुजरात में कपड़े की मिलों और ज्वैलरी निर्माण में स्थानीय लोगों का ही वर्चस्व है, लेकिन यह सच नहीं है. आपको जानकर ख़ुशी होगी कि गुजरात में बिहार मूल के उद्यमियों ने हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति की है. वैसे इस मामले में गुजरात सरकार की तारीफ़ करनी होगी कि उसने राज्य के विकास के लिए सभी छोटे-बड़े कारोबारियों को प्रोत्साहन दिया. उन्हें हर सरकारी मदद और सुविधाएं मुहैया कराईं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत के चारों ओर जब बिहार मूल के कारोबारी अपनी मेहनत से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं, तो यही माहौल बिहार में क्यों नहीं बन रहा है?

कहते हैं कि सपने एक दिन हक़ीक़त में ज़रूर बदलते हैं. कुछ ऐसी ही सकारात्मक पहल मुंबई में रहने वाले सैकड़ों चमड़ा कारोबारियों ने की है. एक कारोबारी के रूप में मुंबई में सफल हुए, लेकिन फ़ुर्सत के लम्हों में जब उन्हें अपने गृह राज्य की याद आती है, तो उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि अपना घर-बार और अपने परिचितों को छोड़कर गए इन लोगों के मन में कहीं न कहीं यह दमित इच्छा ज़रूर थी कि वे अपनी मिट्टी से जुड़कर काम करें. पिछले महीने राजधानी पटना के नज़दीक फतुहा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चमड़ा फैक्ट्री की आधारशिला रखी. इसके भूमि पूजन समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिन्हें इस बात की ख़ुशी थी कि वर्षों बाद अपने लोगों और अपनी माटी से जुड़ने का मौक़ा मिल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार अब चमड़ा उद्योग का हब बनेगा, जिसके तहत फतुहा में लेदर बैग बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियां खुलेंगी. इसके लिए तक़रीबन छह सौ उद्यमियों ने 400 करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छा जताई है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहां उद्योग स्थापित होने से लगभग 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा. फतुहा के ज़रिए बिहार में निवेश और उद्योग का वातावरण बनाने में अपर्णा इंडस्ट्रियल प्रमोशन काउंसिल ने अहम भूमिका निभाई. इस मौक़े पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों में काम कर रहे बिहारी उद्यमियों को बिहार में पूंजी निवेश करने का न्योता दिया. उन्होंने निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही बिजनेस मीट करने का भरोसा दिलाया. उनके मुताबिक़, सरकार इंडस्ट्रियल प्रमोशन काउंसिल गठित करने जा रही है. इससे न सिर्फ़ महाराष्ट्र, बल्कि देश के कोने-कोने से लोग बिहार में निवेश करने आएंगे.

नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद से ही बिहार में औद्योगिक विकास करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी दूसरी पारी में भी अपर्णा इंडस्ट्रियल प्रमोशन काउंसिल को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा पूंजी निवेश नहीं हुआ. अपर्णा इंडस्ट्रियल प्रमोशन काउंसिल की इस मामले में तारीफ़ करनी होगी कि उसने उद्योग-धंधों में एक तरह से नए सामुदायिक प्रयास को जन्म दिया. ग़ौरतलब है कि चीन और जापान में इस तरह का चलन देखा जाता है, जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विकेंद्रीकरण है. मिसाल के तौर पर अगर चीन में कोई कंपनी साइकिल बनाती है तो उसे साइकिल में लगने वाले सभी पार्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती. वहां स्थापित कई छोटी इकाइयां अपने स्तर पर चैन, रिम, टायर, मडगार्ड, पैडल इत्यादि बनाती हैं. साइकिल बनाने वाली कंपनियां उन्हें ख़रीद कर अपना ब्रांड नेम देती हैं और फिर बाज़ार में बेचती हैं. इससे बड़ी मात्रा में लगने वाली पूंजी की बचत भी होती है और काफ़ी संख्या में रोज़गार भी सृजित होते हैं. अगर बिहार में भी सामुदायिक स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को चीन के मॉडल पर प्रोत्साहित किया जाए तो यहां हर ज़िले में उद्योग स्थापित हो जाएंगे. उद्योग का मतलब सिर्फ़ बड़े उद्योग लगाना नहीं होता, कुटीर और लघु उद्योग भी इसी श्रेणी में आते हैं. सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर भी राज्य में विकास को एक नई दिशा दे सकती है.■

यहां भी उद्योग की असीम संभावनाएं हैं

बिहार में भारी उद्योग के अलावा कृषि आधारित उद्योगों में भी बेहतर संभावनाएं हैं. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां मक्का, गेहूं और धान की अच्छी पैदावार होती है. मक्का रबी फ़सल का महत्वपूर्ण खाद्यान्न है. वर्षों पहले इसकी पहचान ग़रीबों के अनाज के रूप में की जाती थी, लेकिन जबसे देश में व्यवसायिक रूप से मुर्ग़ीपालन और पशुपालन का धंधा शुरू हुआ, तबसे इसकी खपत चौगुनी हो गई. राज्य का कोशी-गंगा क्षेत्र यानी खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया ज़िलों में मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन होता है. मई-जून के महीने में इन इलाक़ों में इसकी पैदावार देखने लायक़ होती है. इस दौरान प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारी यहां से मक्का दूसरे राज्यों में ले जाते हैं. मक्का का निर्यात पड़ोसी देशों में भी होता है, लेकिन इसे किसानों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहां मक्का आधारित एक भी उद्योग नहीं है, जबकि दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी मक्के की अच्छी पैदावार होती है. वहां की सरकार ने अपने राज्य में मक्का आधारित कई उद्योग लगाए हैं, जिसका फ़ायदा वहां के किसानों को हो रहा है. बिहार में मक्का आधारित उद्योग लगाना तो दूर की बात है, उन क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है, वहां किसान जगह के अभाव में सड़क और खुले मैदान में अपनी फ़सल सुखाते हैं. यह परंपरागत तरीक़ा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बारिश होने से मक्का भीग जाता है. इससे मक्का की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और किसानों को नुक़सान होता है. उसी तरह बिहार के कोशी-गंगा इलाक़ों के अलावा कई क्षेत्रों में दुग्ध व्यवसाय भी होता है, लेकिन दुग्ध आधारित उद्योग की यहां घोर कमी है. बात अगर फल उत्पादन की करें, तो बिहार में लीची और आम का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, लेकिन आम और लीची आधारित उद्योग और उसके प्रसंस्करण की दिशा में काम बेहद धीमी गति से हो रहा है. ■

राहुल को हार का डर सताने लगा है

अजय कुमार feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद राहुल ने अपना दायरा सीमित कर लिया है. राहुल गांधी बात भले ही पूरे प्रदेश की करते दिखते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका सारा ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पर लगा है. उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा. हार के बादल मंडराते देख राहुल तीन महीने में अमेठी की सूरत बदलने की बात कहने लगे हैं. विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का यह उत्तर प्रदेश का पहला दौरा था. राहुल गांधी दिल्ली से सीधे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे. उनकी मनोदशा किसी से छिपी नहीं थी. वह काफ़ी बदले हुए थे. वह जनता की बेरुख़ी का कारण जानने को बेचैन दिखे. साथ ही वह जनता से सीधा संवाद बनाने की कोशिश भी करते रहे. कई जगह राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की. उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए अमेठी में नेशनल पेपर मिल खुलवाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अमेठी के हज़ारों युवाओं को इससे रोज़गार मिलेगा. मिल लगाने का ख़ाका केंद्र सरकार ने तैयार कर लिया है. इसका शिलान्यास तीन महीने में कर दिया जाएगा. इसके बाद युवाओं को रोज़गार की तलाश में परदेस नहीं जाना पड़ेगा. उनका कहना था कि अमेठी में बेरोज़गारी को जड़ से मिटाने के लिए कई और उद्योग लगाए जाने की योजना है. इसके लिए बड़े उद्योग-धंधे चलाने वालों से बातचीत की जा रही है. कई कंपनियां यहां उद्योग स्थापित करना चाहती हैं. मसला ज़मीन को लेकर फंसा हुआ है. उनका कहना है कि ज़मीन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है.

राहुल गांधी ने अमेठी दौरे के तीसरे और आख़िरी दिन कहा कि तीन महीने के अंदर वह अमेठी की तस्वीर बदल देंगे. कांग्रेस संगठन में नीचे से ऊपर तक बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की बात भी उन्होंने कही. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में अमेठी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से कई सवाल किए. एक कार्यकर्ता ने कहा कि आप दस सालों से अमेठी के सांसद हैं, लिहाज़ा क्षेत्र के किन्हीं चार कार्यकर्ताओं के नाम बता दें. इस पर राहुल गांधी चुप्पी साध गए. इससे कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है. कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने और उन्हें ख़ुश करने के लिए राहुल गांधी ने कई अन्य योजनाओं का पिटारा खोला. एक तरफ़ राहुल अपनी चालें चल रहे थे तो दूसरी तरफ़ उपेक्षित कांग्रेसियों ने राहुल पर जमकर भड़ास निकाली. शायद यह पहला अवसर था, जब कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ज़ुबान खोली थी. वे पिछले कई दशकों से गांधी परिवार की हां में हां मिलाते रहे हैं. अमेठी, रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में निराशाजनक परिणाम आने के बाद राहुल गांधी पहली बार यहां आए थे. हार से दु:खी राहुल के सामने जनता को बोलने का पूरा मौक़ा मिला. राहुल ने अमेठी के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव समीक्षा की. जनता की अदालत में राहुल गांधी कठघरे में थे. चुनावी हार का ठीकरा भी जनता ने उन्हीं के सिर फोड़ा. राहुल ने अमेठी के क़रीब तीन हज़ार लोगों से सीधे बातचीत की. राहुल की नज़र उन बूथों पर रही, जिन पर कांग्रेस को हार मिली थी. हार के कारणों की तलाश में राहुल कभी शिक्षक की तरह तो कभी छात्र की तरह नज़र आए.

राहुल के सवालों पर कार्यकर्ताओं ने बेबाकी से कहा कि आपके यहां दलालों का बोलबाला है. आम जनता का कोई काम नहीं होता है. क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता बिना थाना-कचहरी के किसी की मदद नहीं कर पाते. कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में यहां बहुत घोटाला हो रहा है. जिन सड़कों का निर्माण हुआ, वे जल्दी उखड़ गईं. इंडिया मार्का नल का अभाव है. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पर मात्र काग़ज़ी काम किया गया. जनता चिल्लाती रहती है, पर किसी की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होती. क्षेत्र के क़रीब तीन लाख घरों में आज भी अंधेरा है, जबकि विद्युतीकरण के नाम पर 87 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए गए. अमेठी की फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता. इस वजह से लोग रोज़ी-रोटी की तलाश में पलायन कर रहे हैं. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनसे ग़लती हो गई, माफ़ कर दीजिए, तीन महीने के अंदर सभी ख़ामियां दूर हो जाएंगी. इस मौक़े पर कई घोषणाएं की गईं. राहुल गांधी की पहल पर जनता से सीधा रिश्ता जोड़ने के लिए एक टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की जा रही है. इस नंबर पर यहां की जनता राहुल गांधी से सीधा संवाद करेगी. सांसद निधि का सौ फ़ीसदी इस्तेमाल किया जाएगा. प्रत्येक 15 घरों पर एक इंडिया मार्का हैंडपंप लगेगा. राहुल गांधी हर महीने यहां आकर जनता से मिलेंगे. राहुल ने कहा कि तीन महीने के अंदर पूरा संगठन बदल जाएगा. दलाल कांग्रेसी बाहर होंगे, जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी. ■

राहुल के सवालों पर कार्यकर्ताओं ने बेबाकी से कहा कि आपके यहां दलालों का बोलबाला है. आम जनता का कोई काम नहीं होता है. क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता बिना थाना-कचहरी के किसी की मदद नहीं कर पाते. कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में यहां बहुत घोटाला हो रहा है.

टीम अन्ना के मुताबिक़, स्कॉर्पियन सौदे में जो दस्तावेज़ सामने आए हैं, उनसे साफ होता है कि अभिषेक वर्मा 4 प्रतिशत दलाली की मांग कर रहा था.

टीम अन्ना ने दिया सबूत

हर एक रक्षा सौदे के पीछे दलाल है

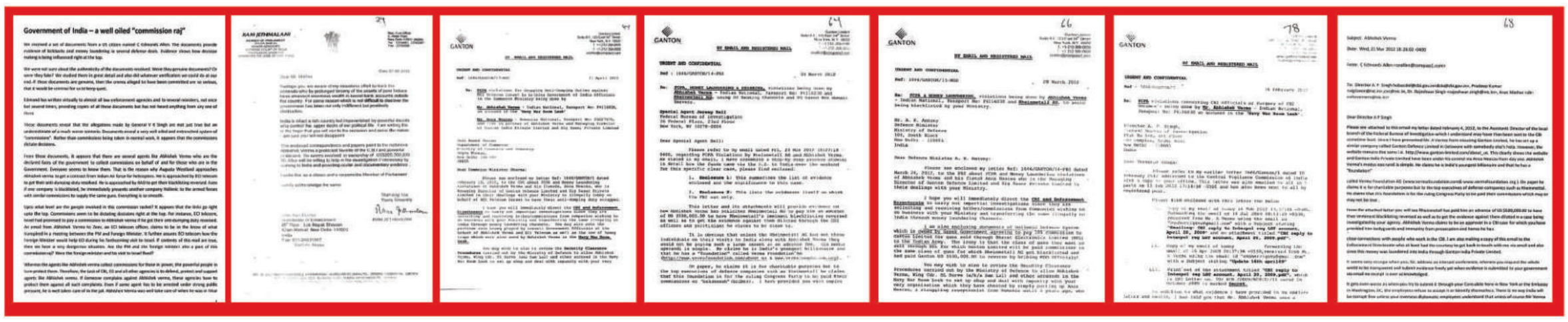

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

हथियारों के दलाल ऐसे लोग हैं, जो होते तो हैं, लेकिन दिखते नहीं. अभी कुछ समय पहले ही एक अंग्रेजी पत्रिका ने इसी विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें हथियार दलालों के नाम तो नहीं बताए गए थे, लेकिन इशारों–इशारों में ही बहुत कुछ कहानी कहने की कोशिश की गई थी. इस रिपोर्ट से इतना तो साफ हो गया था कि भारतीय हथियार दलालों के न सिर्फ़ हौसले बुलंद हैं, बल्कि उनके रिश्ते भी बहुत ऊपर तक है. आम तौर पर उनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत शायद इस देश की सबसे पावरफुल (कथित तौर पर) जांच एजेंसियां भी नहीं कर सकती हैं. ऐसे हालत में जब टीम अन्ना 118 पृष्ठों का सबूत लेकर जनता के सामने आती है, एक हथियार दलाल के ख़िलाफ़ सीधे आरोप लगाती है और कार्रवाई की मांग करती है तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चल रही लड़ाई से एक उम्मीद जगती है. यह उम्मीद तब धूमिल पड़ने लगती है, जब यह पता चलता है कि ये सारे दस्तावेज़ पहले से ही इस देश की जांच एजेंसियों के पास भी हैं, लेकिन अब तक उन जांच एजेंसियों ने उस पर कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा. आख़िर क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री का नाम मनमोहन सिंह है. यह एक ऐसा सच है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता. कुछ इसी तरह का सच यह भी है कि इस देश में जितने भी रक्षा सौदे होते हैं, वे बिना किसी दलाल के नहीं होते यानी हर सौदे में एक बिचौलिया ज़रूर होता है. हाल के दिनों में जो सूचनाएं सामने आईं, वे इस सच को और पुख्ता कर रही हैं. अभी हाल–फ़िलहाल बोफोर्स का प्रेत एक बार फिर से सामने आया और उसके कुछ ही दिनों बाद 118 पेज का एक पुलिंदा लेकर टीम अन्ना सामने आई. इन दस्तावेज़ों से साबित होता है कि रक्षा सौदों में बिचौलियों का बहुत बड़ा दख़ल होता है. उनकी पहुंच काफी बड़ी होती है. टीम अन्ना जो दस्तावेज़ सामने लाई है, उनसे भारत के ही एक नागरिक अभिषेक वर्मा का नाम सामने आया है. यह वही अभिषेक वर्मा है, जिसका नाम नेवी वार रूम लीक मामले में आया था और वह इस मामले में आरोपी भी है. टीम अन्ना ने इन दस्तावेज़ों के आधार पर अभिषेक वर्मा पर आरोप लगाया और कहा कि रक्षा सौदों में दलालों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है. टीम अन्ना ने जितने दस्तावेज़ (118 पेज) सार्वजनिक किए हैं, वे सारे के सारे अभिषेक वर्मा के ख़िलाफ़ हैं.

टीम अन्ना का कहना है कि अभिषेक वर्मा ख़ुद को कांग्रेस और सरकार का प्रतिनिधि बताकर रक्षा सौदों में दलाली कर रहा है. दरअसल, टीम अन्ना को ये सारे दस्तावेज अभिषेक वर्मा के ही एक पूर्व साथी ने मुहैया कराए हैं. अभिषेक वर्मा के इस पूर्व साथी का नाम सी एडमंड्स एलन है, जो एक अमेरिकी नागरिक है और अभिषेक वर्मा के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करता था. इन दोनों के बीच बिजनेस के ही संदर्भ में हज़ारों करोड़ रुपये का लेन–देन भी हुआ था. बाद में इन दोनों के बीच पार्टनरशिप नहीं रही, झगड़ा हुआ और अब एलन अभिषेक वर्मा से अलग हो चुका है. इस संबंध में टीम अन्ना को मिले दस्तावेज़ के मुताबिक़, वर्ष 2000 और 2004 में क़रीब 2000 करोड़ रुपये के दो समझौते एलन और अभिषेक वर्मा के बीच हुए. कथित तौर पर यह पैसा अभिषेक वर्मा का था, जिसके प्रबंधन की ज़िम्मेदारी एलन की थी. एलन अमेरिका में अटॉर्नी है. 2010 में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, तो अभिषेक वर्मा ने एलन को पैसे वापस करने के लिए नोटिस भिजवाई. जब एलन ने कोई जवाब नहीं दिया, तब अभिषेक वर्मा ने अमेरिका में ही एलन के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया. सवाल है कि अभिषेक वर्मा के पास ये 2000 करोड़ रुपये आए कहां से? इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है? क्या अभिषेक वर्मा ने इसकी जानकारी किसी टैक्स अथॉरिटी को दी है? इसी एलन ने टीम अन्ना को अभिषेक वर्मा के ख़िलाफ़ सारे दस्तावेज़ मुहैया कराए हैं. साथ ही उसने कई दस्तावेज़ सीबीआई को भी सौंपे है. यह अलग बात है कि किसी जांच एजेंसी की ओर से कोई कार्रवाई न होते देख एलन ने ये सबूत टीम अन्ना को भी दे दिए. टीम अन्ना के मुताबिक़, इन दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता की जांच अभी होनी है, लेकिन इतने सारे दस्तावेज़ों से शक की गुंजाइश तो बनती ही है. सवाल यह भी है कि जब जांच एजेंसी के पास इतने अहम दस्तावेज़ थे तो फिर कोई नतीजा क्यों नहीं निकला?

2010 में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, तो अभिषेक वर्मा ने एलन को पैसे वापस करने के लिए नोटिस भिजवाई. जब एलन ने कोई जवाब नहीं दिया, तब अभिषेक वर्मा ने अमेरिका में ही एलन के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया. सवाल है कि अभिषेक वर्मा के पास ये 2000 करोड़ रुपये आए कहां से? इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है? क्या अभिषेक वर्मा ने इसकी जानकारी किसी टैक्स अथॉरिटी को दी है? इसी एलन ने टीम अन्ना को अभिषेक वर्मा के ख़िलाफ़ सारे दस्तावेज़ मुहैया कराए हैं.

टीम अन्ना के मुताबिक़, स्कॉर्पियन सौदे में जो दस्तावेज़ सामने आए हैं, उनसे साफ होता है कि अभिषेक वर्मा 4 प्रतिशत दलाली की मांग कर रहा था. रक्षा सौदे की दलाली में अभिषेक वर्मा का क़द कितना बड़ा है, इससे साफ होता है कि दुनिया भर की किसी भी रक्षा सामग्री बेचने वाली कंपनी को मदद की ज़रूरत होती है तो वह अभिषेक वर्मा को ही ढूंढती है, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर सौदे में मदद चाहिए या जर्मन कंपनी आरएडी को ब्लैक लिस्ट से नाम हटवाना हो या फिर इजरायली टेलिकॉम कंपनी ईसीआई को एंटी डंपिंग शुल्क वापस कराना हो. इन सारे ग़ैर क़ानूनी कामों के लिए कंपनियां अभिषेक वर्मा को ही तलाशती हैं. नेवी वार रूम लीक मामले में कई ई–मेल सामने आए हैं, जिनमें स्कॉर्पियन डील के 18 हज़ार करोड़ रुपये में से 4 फ़ीसदी कमीशन की बात सामने आई है. थेल्स कंपनी के सामने अभिषेक वर्मा ख़ुद को कांग्रेस का प्रतिनिधि बताता है. इस संबंध में राम जेठमलानी ने ईडी को जांच करने के लिए एक पत्र भी लिखा है.

बहरहाल, टीम अन्ना के एक प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण कहते हैं कि अब जबकि ये दस्तावेज़ सार्वजनिक हो गए हैं और फिर भी सरकारी एजेंसियां कोई क़दम नहीं उठातीं तो हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे. टीम अन्ना के आरोपों के मुताबिक़, अभिषेक वर्मा न सिर्फ़ रक्षा सौदों में दलाली करता है, बल्कि वह कांग्रेस की तरफ़ से ख़ुद बात भी करता है. टीम अन्ना इस मामले के ज़रिए एक बार फिर से भारतीय जांच एजेंसियों की दयनीय हालत सामने रखती है. टीम अन्ना कहती है कि इन दस्तावेज़ों से साफ होता है कि सीबीआई, ईडी और दीगर जांच एजेंसियां किस तरह सत्ताधारी पार्टियों के शिकंजे में होती हैं और चाहकर भी स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकतीं. ज़ाहिर है, टीम अन्ना लोकपाल क़ानून की मांग करते वक़्त भी यही सवाल उठा रही थी और अब भी उठा रही है कि सीबीआई एवं अन्य जांच एजेंसियों को स्वतंत्र होना चाहिए और सरकार के चंगुल से मुक्त होना चाहिए, ताकि निष्पक्ष और त्वरित जांच हो सके. ■

टीम अन्ना कहती है कि इन दस्तावेज़ों से साफ होता है कि सीबीआई, ईडी और दीगर जांच एजेंसियां किस तरह सत्ताधारी पार्टियों के शिकंजे में होती हैं और चाहकर भी स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकतीं. ज़ाहिर है, टीम अन्ना लोकपाल क़ानून की मांग करते वक़्त भी यही सवाल उठा रही थी और अब भी उठा रही है कि सीबीआई एवं अन्य जांच एजेंसियों को स्वतंत्र होना चाहिए और सरकार के चंगुल से मुक्त होना चाहिए, ताकि निष्पक्ष और त्वरित जांच हो सके.

अभिषेक वर्मा कौन है

बहरहाल, लोग यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभिषेक वर्मा है कौन? अभिषेक वर्मा कांग्रेस के पूर्व सांसद श्रीकांत वर्मा एवं वीणा वर्मा का बेटा है. श्रीकांत वर्मा एवं वीणा वर्मा दोनों कांग्रेस के सांसद रहे हैं. श्रीकांत वर्मा की मां भी कांग्रेस की सांसद रहीं. 18 साल की उम्र में 1986 में अभिषेक वर्मा को यूथ कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था. अभिषेक वर्मा कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी करता था और कांग्रेसी नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर आदि भी उपलब्ध कराता था. अभिषेक वर्मा नेवी वार रूम लीक मामले का मुख्य आरोपी है और फिलहाल 2008 से जमानत पर है. स्कॉर्पियन सब मेराइन डील में उसकी भूमिका को प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने नकार दिया. ■

दिल्ली में रह रहे चंपारण के लोग भी जंतर-मंतर पर आए, लेकिन वहां मंच पर दर्जनों सांसदों एवं विधायकों के अलावा संघर्ष समिति के एक भी सदस्य को बैठने तक की जगह नहीं मिली.

पूर्वी चंपारण

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय

जनसंघर्ष और नेतागिरी

संघर्ष ज़मीन तैयार करता है और फिर उसी ज़मीन पर नेता अपनी राजनीतिक फ़सल उगाते हैं. कुछ ऐसा ही हो रहा है मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बने संघर्ष मोर्चा के साथ. चंपारण की जनता केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिन-रात एक करके संघर्ष करती है और जब दिल्ली आती है अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने, तो वहां मंच पर मिलते हैं बिहार के वे सारे सांसद, जो संसद में तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जनता के बीच भाषणबाज़ी का मौक़ा भी नहीं छोड़ते. इस मुद्दे पर जंतर-मंतर का आंखों देखा हाल बताती *शशि शेखर* की यह रिपोर्ट...

चालीस सांसदों का संख्या बल कम नहीं होता. इतने सांसद चाहें तो लोकसभा में किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करा सकते हैं, संसद की कार्यवाही स्थगित करा सकते हैं. ऐसा होता भी है. कुल मिलाकर यह संख्या किसी मुद्दे पर फ़ैसला लेने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है. बिहार से एनडीए के क़रीब तीस से भी ज़्यादा सांसद लोकसभा में हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर बात पर हो-हल्ला मचाने वाले और संसद की कार्यवाही स्थगित कराने वाले माननीय सांसद मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर हो रही देरी और दूसरी तरफ़ मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के अड़ियल रवैये के ख़िलाफ़ चुप हैं. कुछेक सांसद कार्रवाई के नाम पर महज़ पत्रबाज़ी कर रहे हैं. सवाल है कि क्या बिहार के 40 सांसद इतने कमज़ोर हैं कि एक विश्वविद्यालय की तय जगह पर स्थापना तक नहीं करा सकते या फिर मामला कुछ और है?

दरअसल, गांधी की कर्मभूमि चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, इस मुद्दे पर पिछले दो सालों से चंपारण की जनता दिन-रात संघर्ष कर रही है. युवा, शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नेता सब मिलकर अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. बाक़ायदा एक संघर्ष मोर्चा बनाकर ये लोग धरना-प्रदर्शन, रेल रोको अभियान चलाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं. इसी कड़ी में संघर्ष मोर्चा ने यह तय किया कि दिल्ली चलकर जंतर-मंतर पर एक दिन का धरना दिया जाए. 30 अप्रैल का दिन तय हुआ. हज़ार से ज़्यादा की संख्या में लोग चंपारण से दिल्ली पहुंचे. दिल्ली में रह रहे चंपारण के लोग भी जंतर-मंतर पर आए, लेकिन वहां मंच पर दर्जनों सांसदों एवं विधायकों के अलावा संघर्ष समिति के एक भी सदस्य को बैठने तक की जगह नहीं मिली. जो सांसद संसद में मुंह तक नहीं खोलते, यहां पानी पी-पीकर कपिल सिब्बल को कोस रहे थे. मानो अकेले कपिल सिब्बल इन दर्जनों सांसदों से भी ज़्यादा ताक़तवर हैं. चौथी दुनिया से बात करते हुए शिवहर से भाजपा सांसद रमा देवी यह पूछे जाने पर कि आप लोग संसद के भीतर इस मुद्दे पर लड़ाई क्यों नहीं करते? वह कहती हैं कि मैं एचआरडी मिनिस्ट्री की कमेटी में मेंबर हूं और मैंने मिनिस्टर को पत्र भी लिखा है. इससे काम नहीं बनेगा तो आगे और क़दम उठाए जाएंगे, दबाव बनाया जाएगा. लेकिन जब इस संवाददाता ने मोतिहारी से भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह से उनकी राय जाननी चाही तो वह बजाय कुछ बोलने के इस संवाददाता के हाथ में अपना एक प्रेस वक्तव्य थमा देते हैं और कहते हैं कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है. मानो सांसद महोदय के पास वक़्त की बड़ी कमी हो. यह अलग बात है कि जहां कहीं भी वे टीवी कैमरा देखते थे, वहां बोलने से ख़ुद को रोक नहीं पा रहे थे.

> राधा मोहन सिंह ने इस मुद्दे को कभी संसद में नहीं उठाया और एक अन्य सांसद से मुझे मिली जानकारी के मुताबिक़ राधा मोहन सिंह इस मुद्दे पर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वह अगले चुनाव तक इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहते हैं.
> -सुंदर देव शर्मा, *संघर्ष मोर्चा*

> गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला स्कूल चंपारण के ही भितिहरवा और बड़हरवा में खोला था. इस क्षेत्र का विकास शिक्षा से ही हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने.
> -बजरंगी नारायण ठाकुर, संघर्ष मोर्चा

बहरहाल, संघर्ष मोर्चा में शामिल वरिष्ठ नागरिकों एवं चंपारण के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं ने दलीय सीमाओं को भुलाकर यह संघर्ष रूपी मंच तैयार किया है, जिस पर अब सांसद महोदय अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की तैयारी कर रहे हैं. पूर्वी चंपारण के एक जाने-माने सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा से जुड़े बजरंगी नारायण ठाकुर कहते हैं कि मोतिहारी देश भर में सबसे पिछड़ा ज़िला है और बिहार के बंटवारे के बाद सारी अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं झारखंड में चली गईं. अब तो उत्तरी बिहार में शिक्षा का और भी बुरा हाल है. ऐसे में इस इलाक़े का विकास शिक्षा से ही हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने. वह बताते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला स्कूल चंपारण के ही भितिहरवा और बड़हरवा में खोला था. दूसरी ओर, संघर्ष मोर्चा के ही सुंदर देव शर्मा इन सांसदों के रवैये से इतने ख़फ़ा दिखे कि वह चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए कहते हैं, राधा मोहन सिंह ने इस मुद्दे को कभी संसद में नहीं उठाया और एक अन्य सांसद से मुझे मिली जानकारी के मुताबिक़ राधा मोहन सिंह इस मुद्दे पर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वह अगले चुनाव तक इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहते हैं. शर्मा आगे कहते हैं कि जब हम अपने सांसद से मिले और यह बताया कि हम लोग (संघर्ष मोर्चा) दिल्ली में धरने का आयोजन करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, सारा इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो देखा कि मंच पर संघर्ष मोर्चा का बैनर तक नहीं लगा है और एक के बाद एक दर्जनों नेता आकर मंच पर विराजमान हो चुके हैं. मानो हम उनका भाषण सुनने आए हैं.

ज़ाहिर है, संघर्ष का सम्मान जब अपने ही लोग नहीं करेंगे तो दूसरे भला क्यों इसकी परवाह करेंगे. चंपारण से आए संघर्ष मोर्चा की युवा इकाई के अमरेंद्र सिंह, शंभु शरण सिंह, बबन कुशवाहा, साजिद रज़ा, सेवानिवृत्त शिक्षक राम नरेश सिंह, इं. रमेश वर्मा, राम पुकार सिंह, पूर्वी चंपारण प्रेस क्लब के ज्ञानेश्वर गौतम, संजय कौशिक, आनंद प्रकाश, मनीष शेखर और वॉयस ऑफ मोतिहारी के साथ-साथ संघर्ष मोर्चा की छात्र इकाई से जुड़े सैकड़ों युवा इस धरने में शामिल होने आए थे. इनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना था कि आख़िर जब दोपहर 2 बजे तक का समय मिला था तो एक-डेढ़ बजे ही कार्यक्रम को क्यों समाप्त कर दिया गया, आख़िर क्यों हमारे माननीय सांसद समय से पहले ही सभा से चले गए? वे यह भी सवाल उठाते हैं कि सभा के बाद प्रधानमंत्री को ज्ञापन क्यों नहीं सौंपा गया या संसद की तरफ़ मार्च क्यों नहीं किया गया? ज़ाहिर है, इन सवालों के जवाब चंपारण के लोगों को मिलने ही चाहिए. बहरहाल, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए चंपारण की जनता को एक लड़ाई केंद्र सरकार या कपिल सिब्बल से तो करनी ही है, साथ ही उन्हें अपने नुमांइदों पर भी दबाव डालना होगा, ताकि वे संसद के भीतर इस लड़ाई को लड़ें. न सिर्फ़ आपकी आवाज़ उठाएं, बल्कि उसे मानने के लिए सरकार को मजबूर करें. अगर ऐसा नहीं होगा तो तय मानिए, सिर्फ़ कपिल सिब्बल को कठघरे में खड़ा करने या कोसने से केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनने वाला है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... चिंतित सोनिया !

स्टिंग ऑपरेशन का षड्यंत्र

अन्ना कोर कमेटी की बैठकों के बारे में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं कि वे बहुत गोपनीय होती हैं. इस संदर्भ में हाल में शमूम काज़मी की घटना का पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:–

बीते 22 अप्रैल को नोएडा में हुई कोर कमेटी की मीटिंग की घटनाओं के पीछे गहरा षड्यंत्र नज़र आता है. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ताक़तें शमूम क़ाजमी के ज़रिए आंदोलन से जुड़े नेतृत्व का स्टिंग ऑपरेशन कराकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही थीं. कोर की मीटिंग में कुछ भी गोपनीय चर्चा नहीं होती. कई बार बाहर के लोग भी आकर मीटिंग में बैठे हैं और उन्होंने चर्चा सुनी है. लेकिन मीटिंग की कार्रवाई की चोरी छिपे रिकॉर्डिंग करना और पकड़े जाने पर बेचैन होकर चीख़ने-चिल्लाने लगना, इससे ज़रूर संदेह पैदा होता है.

कोर कमेटी सदस्य गोपाल राय ने शमूम काज़मी को रिकॉर्डिंग करते पकड़ा. जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो शमूम ने फोन दिखाने से मना कर दिया. कई सदस्यों के निवेदन करने पर उन्होंने फोन हमारे एक साथी बिभव को दिया. जब बिभव ने फोन देखा तो उसमें पूरे दिन की कई रिकॉर्डिंग मिली. इस पर एक सदस्य काफ़ी गरम हो गए. दूसरे सदस्य ने शमूम से मीटिंग छोड़कर जाने का आग्रह किया. इस पूरे घटनाक्रम में मैंने और मनीष सिसौदिया ने कुछ भी नहीं कहा. लेकिन मज़े की बात यह है कि शमूम ने बाहर निकलते ही पहला निशाना मुझे और मनीष को ही बनाया. ऐसा लगता है कि उन्हें पढ़ा-लिखाकर भेजा गया था.

यह एक सुनियोजित स्टिंग ऑपरेशन का षड्यंत्र था, जिसके बाद शमूम को वही कहना था जो उन्होंने बाहर निकलकर कहा, जो उनके आक़ाओं ने उन्हें सिखाकर भेजा था.हम पारदर्शिता के ख़िलाफ़ नहीं हैं. हम हमेशा से पारदर्शिता की लड़ाई लड़ते रहे हैं. पर यह लड़ाई भ्रष्टाचारी ताक़तों के ख़िलाफ़ है. नोएडा की मीटिंग में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से लड़ने की रणनीति बनाई जा रही थी. अगर यह रणनीति सार्वजनिक हो जाती तो भ्रष्टाचारियों को फ़ायदा पहुंचता. इससे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई की धार कम हो जाती. इस आंदोलन को कमज़ोर करने और तोड़ने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है. लेकिन ऊपर वाला इस आंदोलन के साथ है. सच्चाई इस आंदोलन के साथ है. पहले की तरह इस बार भी जीत सच्चाई की ही हुई. इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और हमें बताएं, आप इस पर भी चर्चा करें कि कोर कमेटी में फूट डालने के अलावा हमें भ्रष्टाचारियों की और कौन सी चालों से सचेत रहना चाहिए.

जयहिंद
अरविंद केजरीवाल

आप अपनी प्रतिक्रिया हमें 09718500606 पर फोन करके या पर ई-मेल करके भेज सकते हैं. इस बार आपके चर्चा समूह में कितने लोग आए, यह आप हमें SMS करके ज़रूर बताएं. SMS करने का वही तरीक़ा है-DF<space> आपका पिन कोड <space> चर्चा समूह में कितने लोग आए. जैसे मान लीजिए, आपका पिन कोड 110001 है और आपके समूह में मान लीजिए, पांच लोग आए तो आप 09212472681 नंबर पर निम्न SMS करेंगे-DF 1100015

आंदोलन जारी है...

फोटो–प्रभात पाण्डेय

राज्य की कांग्रेस सरकार और ख़ासकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के लिए अन्ना की यह यात्रा ज़रूर असुविधाजनक स्थिति लाने जा रही है, क्योंकि अन्ना जिस सख्त लोकायुक्त की मांग कर रहे हैं, वह अभी बनता संभव नहीं दिखता. वजह, एक तो केंद्र में लोकपाल बिल लटका हुआ है और दूसरा चव्हाण को कुछ करने से पहले अपने हाईकमान से आदेश लेना पड़ेगा.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

कभी पास, कभी दूर. टीम अन्ना और रामदेव के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. टीम अन्ना बार-बार रामदेव के साथ मिलकर आंदोलन चलाने की बात से इंकार करती रही है, लेकिन इस बार जब अन्ना हजारे ने यह घोषणा कर दी कि वह 3 जून को दिल्ली में बाबा रामदेव के साथ होंगे तो चाहकर भी टीम अन्ना के सदस्य इसका विरोध नहीं कर पाए. एक और महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिल रही है कि बीते एक मई से जब अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में अपनी यात्रा शुरू की, तब टीम अन्ना का कोई भी अहम सदस्य उनके साथ नहीं था. ज़ाहिर है, महाराष्ट्र अन्ना हजारे का गृह राज्य है और वहां उन्हें किसी अन्य के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है. हालांकि अन्ना हजारे ने मई के महीने में पूरे देश के भ्रमण की बात कही थी, लेकिन अब वह सिर्फ़ महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और 3 जून को जंतर-मंतर पर रामदेव के साथ होंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि उस मंच पर अन्ना और रामदेव के अलावा टीम अन्ना के और कौन-कौन से सदस्य उपस्थित रहते हैं. बहरहाल, एक बार फिर रणभेरी बज चुकी है. एक ओर अन्ना तो दूसरी ओर रामदेव. एक मई से अन्ना हजारे ने अपने अभियान की शुरुआत अहमद नगर यानी अपने गृह ज़िले से कर दी है. वहीं रामदेव भी छत्तीसगढ़ से अपनी स्वाभिमान यात्रा का तीसरा चरण शुरू कर चुके हैं. 3 जून को ये दोनों योद्धा एक साथ होंगे. दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक दिन का आंदोलन होगा, जिसमें काला धन और सख्त लोकपाल के मसले पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा जाएगा. दिसंबर 2011 में मुंबई के अपने अनशन के बाद से अन्ना हजारे कई बार कह चुके थे कि वह अब जनता के बीच जाएंगे. 25 मार्च को जंतर-मंतर पर आयोजित एक दिवसीय धरने में भी उन्होंने यह घोषणा की थी कि वह मई के महीने से पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे. बहरहाल, पूरे देश तो नहीं, लेकिन अन्ना हजारे अब पूरे 5 सप्ताह तक महाराष्ट्र के हर एक जिले में घूमेंगे. मांग है, राज्य में एक सख्त लोकायुक्त क़ानून बनाया जाए. ज़ाहिर है, उनके निशाने पर राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हैं. अन्ना हजारे 2 जून को मुंबई पहुंचेंगे. फिर तीन जून को वह दिल्ली आकर रामदेव के धरने में शामिल होंगे और फिर 4 जून को महाराष्ट्र के ठाणे और 5 जून को नवी मुंबई में होंगे.

इधर, रामदेव विदेश से काला धन वापस लाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर फिर से एक बार दिल्ली आएंगे. पिछले साल जून में ही दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वह एक लंबे समय तक ख़ामोश रहे, लेकिन अब एक बार फिर से वह केंद्र सरकार से दो-दो हाथ करने के मूड में हैं. अपनी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत के साथ ही उन्होंने ज़ुबानी हमला भी शुरू कर दिया है. जिस दिन अन्ना ने अपनी यात्रा शुरू की, उसी दिन रामदेव ने भी अपनी यात्रा छत्तीसगढ़ के भिलाई से शुरू की. इसके बाद रामदेव दुर्ग होकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान और फिर अंत में वह दिल्ली आएंगे. इन दोनों यात्राओं का राजनीतिक असर अभी से दिखना शुरू हो गया है. महाराष्ट्र में अन्ना हजारे से बाल ठाकरे नहीं मिले. राज ठाकरे ज़रूर उनसे मिले और अपना समर्थन भी दिया. राज्य की कांग्रेस सरकार और खासकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के लिए अन्ना की यह यात्रा ज़रूर असुविधाजनक स्थिति लाने जा रही है, क्योंकि अन्ना जिस सख्त लोकायुक्त की मांग कर रहे हैं, वह अभी बनता संभव नहीं दिखता. वजह, एक तो केंद्र में लोकपाल बिल लटका हुआ है और दूसरा चव्हाण को कुछ करने से पहले अपने हाईकमान से आदेश लेना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में अन्ना चव्हाण को भी आरोपों के घेरे में लाने से नहीं चूकेंगे. दूसरी तरफ़, रामदेव ने यह कहकर कि संसद में डकैत और हत्यारे बैठे हैं, पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. ऐसे में 3 जून को तपती दोपहरी में जंतर-मंतर पर अन्ना और रामदेव एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार करेंगे, तब मौसम और बयानों की मिली-जुली गर्मी क्या रंग लाएगी, इसका इंतज़ार सबको रहेगा. ■

अन्ना चर्चा समूह से जुड़े सवाल आप हमें *ईमेल: sawal@chauthiduniya.com* पर भेज सकते हैं.

जब भी आप बैंकों में खाता खोलते हैं, आपको कुछ रकम अपने खातों में जमा करानी होती है. 300 रुपये या 500 रुपये से कम में आप बैंक में खाता खोल ही नहीं सकते.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

बैंक व्यवस्था

शेयर बाज़ार तो पूंजी बाज़ार का एक विभाग मात्र है. असली जगह बैंक हैं, जहां फालतू रुपये लिए-दिए जाते हैं. बैंक में आप अपना खाता खोल लीजिए और जब आवश्यकता हो, बैंक के मैनेजर के पास जाकर रुपये उधार लेने की व्यवस्था कर लीजिए. बैंक तुरंत ही आपको रुपये उधार दे देगा. बशर्ते कि उसे पूरा इत्मीनान हो कि आप उधार लिए हुए रुपये समय पर वापस लौटा देंगे. बैंकों का दरअसल धंधा ही यही है. बैंक आपको कई तरीक़ों से उधार दे सकते हैं. आपके खातों में से आपको आपके जमा से ज़्यादा रुपये निकालने दे सकते है, जिसको ओवर ड्राफ्ट कहते हैं.

किसी दूसरे व्यक्ति से आपको रुपये लेने हैं. वह लिखकर आपको निर्धारित मुद्दत की हुंडी दे दे तो बैंक को यह विश्वास होने पर कि वह व्यक्ति मुद्दत पर हुंडी की रकम अदा कर देगा, बैंक आपकी हुंडी का रुपया उसी वक़्त दे देगा. इसको हुंडी बट्टा करना कहते हैं. इस तरह के कई मार्ग हैं, जिनके द्वारा आप बैंकों से रुपये किराए पर ले सकते हैं. बैंक का चार्ज समय और परिस्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा होता रहता है. आपने कई बार सुना होगा, बैंक रेट बढ़ गया या बैंक रेट घट गया. इसका अर्थ होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शासन की तरफ से सारी बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है, फालतू रकम की बहुतायत या कमी के अनुपात से रुपये किराए पर देने के रेट में कमी या वृद्धि की घोषणा करता रहता है.

जब-जब बैंक रेट बढ़ता है, व्यापारी वर्ग को कठिनाई होती है. जो-जो रकमें उन्होंने उधार ले रखी हैं, वे या तो वापस मांग ली जाती हैं या और रुपये, आवश्यक हों तो भी, मिलने में कठिनाई होती है. वे अपना रोज़गार नहीं बढ़ा पाते हैं. यही वजह है कि व्यापारियों में, जब-जब ब्याज की दर बढ़ती है, काफी घबड़ाहट और चिंता फैल जाती है. और जब-जब बैंक ब्याज की दर घटती है, उनमें ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है. बैंक रेट असल में, फालतू रकम कितनी मिल सकती है, इसको मापने का

आप कहेंगे कि हमारे रुपये बैंक उधार दे देती है तो हम चाहे जब मांगें तो बैंक हमारे जमा रुपये देगा कहां से? बात सही है, आप रुपये मांगें, उसी वक्त हज़ारों लोगों के जो विभिन्न खाते हैं और जिनके रुपये जमा हैं, यदि वे सब एक साथ तमाम रुपये मांगने लगें तो कोई भी बैंक अपना उत्तरदायित्व कभी नहीं निभा सकता. कारण स्पष्ट है. हर बैंक निश्चित अनुपात में अपने जमा खातों के रुपयों में से हाजिर रोकड़ा या तरल निधि अपने पास रखता है. यदि सारा का सारा रुपया फालतू पड़ा रहे तो भी कोई बैंक कभी सफलतापूर्वक बैंकिंग का कारोबार कर नहीं सकता.

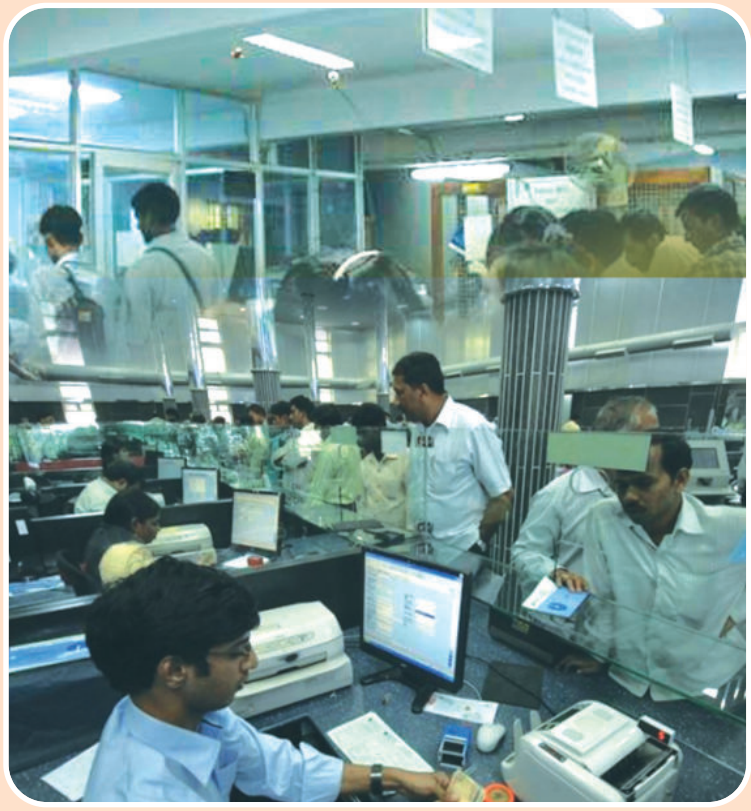

एक पैमाना है. अब प्रश्न यह है कि बैंकों के पास इतना फालतू रुपया उधार देने को आता कहां से है.

जब भी आप बैंकों में खाता खोलते हैं, आपको कुछ रकम अपने खातों में जमा करानी होती है. 300 रुपये या 500 रुपये से कम में आप बैंक में खाता खोल ही नहीं सकते. हर समय बैंक खाते में कम से कम कुछ रकम आपको जमा रखनी ही होती है. जैसा भी आपका व्यापार हो, उसी के हिसाब से हज़ार, दस हज़ार, लाख या अधिक रुपये जमा रहते हैं. आप जब चाहें, चैक काटकर रुपये ले लेते हैं, जमा भी कराते रहते हैं. इस तरह से हर एक व्यापारी को, अगर वह व्यापार करता है तो, सालाना लाखों या करोड़ों के देन-लेन में, अलग-अलग समय, कभी हज़ार, कभी पांच हज़ार, कभी एक लाख , कभी कम, कभी ज़्यादा रुपये अपने खाते में जमा रखने पड़ते हैं. इस तरह हज़ारों खाते हैं. किसी के खाते में कभी कम, किसी के खाते में कभी ज़्यादा, अलग-अलग दिनों में अलग-अलग रकम जमा रहती है. इन चालू खातों की जमा रकमों को संभाले रखने का बैंक आपसे कुछ भी किराया नहीं लेते हैं. इस तरह से लोगों के रुपये, जो वे बैंकों में जमा कराते हैं, उनके वे फालतू रुपये ही होते हैं. बैंक आपको, हमको, सबको आवश्कता पड़ने पर रुपये उधार देता है. बैंक इन रुपयों का किराया चार्ज करता है. यही ब्याज बैंकों की आमदनी है.

आप कहेंगे कि हमारे रुपये बैंक उधार दे देती है तो हम चाहे जब मांगें तो बैंक हमारे जमा रुपये देगा कहां से? बात सही है, आप रुपये मांगें, उसी वक्त हज़ारों लोगों के जो विभिन्न खाते हैं और जिनके रुपये जमा हैं, यदि वे सब एक साथ तमाम रुपये मांगने लगें तो कोई भी बैंक अपना उत्तरदायित्व कभी नहीं निभा सकता. कारण स्पष्ट है. हर बैंक निश्चित अनुपात में अपने जमा खातों के रुपयों में से हाजिर रोकड़ा या तरल निधि अपने पास रखता है. यदि सारा का सारा रुपया फालतू पड़ा रहे तो भी कोई बैंक कभी सफलतापूर्वक बैंकिंग का कारोबार कर नहीं सकता.

कारण, जो-जो रुपया फालतू आता रहता है, उसका किराया वह बैंक कमाता रहे तो अपने ख़र्चे वगैरह सब चलाकर कुछ कमाई भी कर लेता है. अगर उन रुपयों का किराया न उगाहा जाए तो किसी भी बैंक का चलना कभी भी संभव नहीं होगा. बैंक अपने पास जमा रुपयों में से उन रुपयों के किस भाग तक को उधार देने के उपयोग में ला सकता है, उसकी एक तालिका आर्थिक आचार्यों ने बना रखी है. यह तालिका कई वर्षों के अनुभव से सिद्ध है. इन सबके बावजूद कभी-कभी झूठी अफवाहें या अर्द्ध सत्य ख़बर फैल जाती हैं कि अमुक बैंक की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डांवाडोल हो रही है. फलस्वरूप बहुसंख्या में लोग जिनके रुपये वहां जमा हैं, एक साथ अपने-अपने रुपये निकालने दौड़ पड़ते हैं. इसे बैंक रन या बैंक पर टूट कहा जाता है.

ऐसे अचानक टूट आने से परिणास्वरूप अच्छे-अच्छे बैंक भी अचानक अपनी देनदारी चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और पूंजी बाज़ार में आपात स्थिति खड़ी हो जाती है. बैंक को बचाने के हेतु भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कई अधिनियम बना रखे हैं, जिनके अनुसार, ऐसी आपात स्थिति पैदा होने पर रिजर्व बैंक तुरंत उस बैंक की मदद को पहुंच जाता है. उस बैंक द्वारा लोगों को उधार दिए हुए रुपयों के प्रमाणित घाण-पत्र ले-लेकर रिजर्व बैंक उतने-उतने रुपये उस बैंक को दे देता है, ताकि वह अपनी ज़िम्मेदारी या अपना उत्तरदायित्व निभा सके. अगर किसी बैंक ने बिना किसी जमानत के यों ही लोगों को रुपये उधार दे रखे हैं या दूसरे अन्य धंधों में रुपया अटका रखा है या सट्टेबाज़ी में नुक़सान उठा लिया है तो रिज़र्व बैंक से सहायता मिलना कठिन ही है. वरना जबसे बैंकिंग एक्ट भारत में लागू हुआ है, तबसे बैंकों के फेल होने की नौबत शायद ही आने पाए.■

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

कांग्रेस और भाजपा में कोई फ़र्क नहीं

मुझे लगता है कि यह सरकार एक मृतप्राय सरकार है. कोई लोगों ने सरकार से गुज़ारिश की कि गांधी जी की यादों से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी रोकी जाए, लेकिन यह सरकार जब अपने रोजमर्रा के ही काम नहीं कर पा रही है, तो इसे गांधी जी की मेमोरीबिलिया लाने की फुर्सत भला कहां से मिलती! आर्मी चीफ की नियुक्ति से लेकर हर छोटी चीज तक, सरकार नाम की चीज आपको कहीं दिखती है? यह सरकार ही नहीं है, यह नॉन एक्जिस्टिंग सरकार है, नौकरशाही चला रही है इस सरकार को. इस सारे एपिसोड में सरकार ने कोई रोल नहीं निभाया और न विपक्ष ने. जितनी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग सभी गांधी जी का नाम लेती हैं, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया. सरकार तो है ही नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन जो मुख्य विपक्ष है, वह भी नहीं है, न होने के बराबर है. वे छोटी-छोटी बातों पर बहस करते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, उनकी न सरकार को फ्रिक है और न भाजपा को और यह रेखांकित होता है इनके तौर-तरीक़ों से. राज्यसभा का इलेक्शन, जो कि नॉमिनेशन टाइप है, भाजपा को देखिए, कैसे-कैसे उम्मीदवारों को टिकट देती है. लोग नॉन पॉलिटिकल होते जा रहे हैं. अख़बारों में यह ख़बर आई कि सोनिया जी मनमोहन सिंह से इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं कि उन्होंने गांधी जी की यादों से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी रोकने या उसे अपने देश में लाने के संदर्भ में कोई क़दम नहीं उठाया. यह बहुत अच्छी बात है. अगर सोनिया जी का मंतव्य यही था, जैसा कि ख़बर बताती है तो यह काफी अच्छा है. लेकिन, अगर सोनिया जी निर्देश दे देतीं तो मनमोहन सिंह ज़रूर रुचि लेते, पर ऐसा नहीं हुआ. फिर भी अगर सरकार चाहती तो वह ख़ुद बिड करके गांधी जी की इन वस्तुओं को ख़रीद सकती थी या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स का हाई कमिश्नर बिड करके ख़रीद सकता था.

न केवल गांधी जी के मसले पर, बल्कि देश के हर सवाल, लोगों के प्रति विपक्ष और कांग्रेस का रुख़ एक जैसा है. गोविंदाचार्य जो आरएसएस के हैं और भाजपा के जनरल सेक्रेट्री भी थे, उनका एक बयान भी है कि पहले इन दोनों पार्टियों में फ़र्क़ होता था. अब तो इनकी नीति एक है, इसलिए दोनों का आपस में विलय हो जाना चाहिए. पहले मौलिक प्रश्नों पर कांग्रेस अलग थी, भाजपा अलग. जिस कांग्रेस को हम लोग जानते थे यानी गांधी जी की कांग्रेस, जवाहर लाल नेहरू की कांग्रेस, सरदार पटेल की कांग्रेस, उसके कुछ मूल्य थे, जैसे सादगी, खादी पहनना या सेकुलर कंडक्ट. पाकिस्तान अलग हो गया, मुसलमान चले गए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बदलाव नहीं करेंगे.

सोशलिज्म का मतलब कम्युनलिज्म नहीं था हमारे यहां. हमारे यहां था कि ग़रीब तबके का ध्यान रहे, चाहे जातियां हों, चाहे वर्ग हों, दलित हों, ये सब मुद्दे थे. भाजपा जो थी, वह राइट विंग पार्टी थी. वह चाहती थी कि ट्रेन और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले. हालांकि सादगी में वह भी विश्वास करती थी, लेकिन उसने छवि बनाई कि हम कांग्रेस से अलग हैं, क्योंकि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे यहां पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं. अब धीरे- धीरे देखते हैं कि कांग्रेस ने अपने मूल्य छोड़ दिए, भाजपा ने भी अपने मूल्य छोड़ दिए. जो आम काम हैं, दोनों उन पर आ गए. चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे अमेरिका के सामने घुटने टेकने हों, सारे बिंदुओं पर दोनों एक हैं. अभी भी कांग्रेस कह रही है कि वह संसद में दो-तीन बिल लाएगी और पारित कराएगी, जैसे पेंशन बिल आदि. इसका मतलब है कि उसे भाजपा का समर्थन हासिल है.

गांधी जी की यादों से जुड़ी वस्तुएं ख़रीदने और उन्हें वापस लाने के पीछे मेरा मक़सद यह है कि ये वस्तुएं इस देश की धरोहर हैं. मैं चाहता हूं कि इस धरोहर को सरकार राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे, जहां आम लोग इसे आसानी से देख सकें. अगर सरकार चाहेगी तो मैं इन्हें उसके हाथों में सौंप दूंगा. और, अगर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया तो मैं निजी स्तर पर प्रयास करूंगा कि इस धरोहर को देश के लोगों के सामने कैसे पेश करूं. मुंबई में तो यह काम आसानी से हो जाएगा, बाक़ी जगह कैसे संभव हो, इसके लिए भी रूपरेखा बनाई जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

धर्म की आड़ में शोषण

धार्मिक स्थलों और धार्मिक गुरुओं द्वारा महिलाओं का शोषण करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. टीवी चैनलों पर छाये रहने वाले कई बाबाओं के कई क़िस्से सामने आ चुके हैं कि किस तरह उन्होंने महिलाओं का शोषण किया और उन्हें धमकियां दीं. अब केरल की एक पूर्व नन ने अपनी आत्मकथा में पादरियों पर शोषण के आरोप लगाए हैं. हैरानी होती है कि एक तरफ़ तो ये धार्मिक गुरु धर्म के नाम पर बड़े-बड़े उपदेश देते हैं, वहीं स्वयं दरिंदे बनकर महिलाओं का शोषण करते हैं. अफ़सोस की बात तो यह भी है कि इस तरह के मामले सामने आने के बावजूद महिलाएं इनके जाल में फंसती हैं और अपना शोषण कराती हैं. जब

-रफ़त जहां, दिल्ली

वक़्फ़ जायदाद क़ब्ज़े में

देश में वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध क़ब्ज़े हैं. अफ़सोस की बात तो यह है कि वक़्फ़ बोर्ड के जिन अधिकारियों पर इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी है, वही रिश्वत लेकर इन्हें भू माफ़िया के हवाले कर रहे हैं. सरकार से अनुरोध है कि वह वक़्फ़ की संपत्तियों को क़ब्ज़ाधारियों के चंगुल से मुक्त कराए और दोषी लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे.

-असलम ख़ान, *दिल्ली*

सरकार ध्यान दे

नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि वे नक्सलवादियों की जायज़ मांगों को पूरा करे और उन्हें मुख्यधारा से जोड़े. नक्सली भी इसी देश की संतान हैं और वे सरकार की ग़लत नीतियों के कारण परेशान हैं. देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सरकार के नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करें.

-रंजन कुमार सिंह राजपूत, *पटना, बिहार*

साहित्य दुनिया के पेज बढ़ाएं

चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. अख़बार में दिनोदिन अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है. देश-विदेश के मुद्दों पर तो ज्ञानवर्धक आलेख होते ही हैं. साथ ही साहित्य दुनिया की भी उत्कृष्टा देखते ही बनती है. आपसे अनुरोध है कि साहित्य दुनिया के लिए कम से कम दो पेज निर्धारित किए जाएं. इनमें कथा-कहानी को भी स्थान दिया जाए. कोशिश की जाए कि कोई भी कहानी ऐसी न प्रकाशित की जाए, जो कई अंकों तक चले. क़िस्तवार कहानियों से रोचकता ख़त्म हो जाती है.

-काशिफ़, *दरियागंज, नई दिल्ली*

धार्मिक पुस्तक पर विवाद

दुनिया के सभी देशों का झुकाव वैश्वीकरण, बाज़ारीकरण और उदारीकरण की तरफ़ हो रहा है. भारत में सम्राट अकबर ने धर्म निरपेक्षता की नींव रखी थी. अकबर ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया. देश में विदेशी साहित्य को लोग चाव से पढ़ते हैं. यहां शेक्सपियर और गोर्की को ख़ूब पढ़ा जाता है. लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं. लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि विदेशों में हमारी धार्मिक पुस्तकों को लेकर विवाद क्यों पैदा होते हैं? कुछ समय पहले रूस में गीता को लेकर विवाद पैदा हो गया, जबकि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं.

-प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार*

अमेरिका की दोहरी नीति

अमेरिका की दोहरी नीतियां जगज़ाहिर हैं. वह कब अपनी बात से पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है. इस बार अमेरिका ने कहा है कि उसने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद पर कोई इनाम नहीं रखा है. पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत कैमरन मुंटर ने पाकिस्तानी मीडिया पर इस मामले में ग़लत ख़बर देने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सईद मुंबई हमलों के मामले में संदिग्ध है, लेकिन अमेरिका ने उस पर किसी तरह का इनाम घोषित नहीं किया है. अमेरिका की ओर से घोषित बयान ऐसी सूचना के लिए है, जिसके ज़रिए सईद और उसके साथियों की गिरफ्तारी संभव हो सके.

-रहमान, *जयपुर, राजस्थान*

अंत में

माफ़िया राज

दादागिरी, गुंडागर्दी और माफ़िया राज
भारत में हर तरफ़ फैला हुआ है आज
ईमानदार अधिकारी सरेआम मारे जाते हैं
जनता है त्रस्त, खाने को नहीं है अनाज
आज़ादी का उत्सव, प्रजातंत्र का महोत्सव
मनाया जाता है देश में जोश से हर साल
आम आदमी तो सिर्फ़ देखता रह जाता
राजनेता चटकर जाते हैं असली माल
नेताओं, बाहुबलियों और धनबलियों ने
देश की सारी संपदा पर अधिकार कर लिया
भ्रष्ट अधिकारी, दाग़ी नेता, सब मौज करें
पुलिसवालों ने भी उनसे प्यार कर लिया
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
जहां आम आदमी रोटी के लिए परेशान है
सारी दुनिया तारीफ़ करते नहीं थकती
मैं भी कहता हूं, मेरा भारत महान है.

-सीताराम शर्मा, सीकर, राजस्थान.

राजकमल प्रकाशन समूह

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

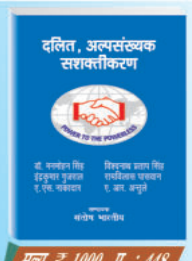

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आप सांसद हैं, देवता नहीं

हमारे सांसद कुछ ज़्यादा ही सेंसेटिव हो गए हैं. उन्हें लगता है कि वे संसद के लिए चुन लिए गए हैं तो वे लोकतंत्र के देवता हो गए हैं. उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता है. अगर देश में भ्रष्टाचार की बात हो तो सांसदों को लगता है कि उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है. बेकारी, महंगाई, लूट, ग़ैर बराबरी, विकास न होना, उन्हें लगता है कि इन मुद्दों के ऊपर कुछ भी कहना उनके ऊपर ऊंगली उठाना है. अगर बड़े पैमाने पर देखें तो इसमें कोई गलती भी नहीं है. संसद इस देश के लिए बनने वाली सारी योजनाओं के लिए ज़िम्मेदार है. जो भी दिशा-निर्देश और नीतियां संसद बनाती है, उन्हीं दिशा निर्देशों और नीतियों के ऊपर राज्य काम करते हैं. योजना आयोग केंद्र के पास है. बजट बंटवारे का अधिकार केंद्र के पास है. अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो उसकी वाहवाही संसद लेती है, तो देश में जो कुछ खराब हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी लेने से संसद क्यों डरती है. जब हम सांसदों की बात करते हैं तो सारे सांसदों को मिलाकर ही संसद के पांच साल का स्वरूप सामने आता है. जैसे सांसद होंगे, वैसे ही संसद काम करेगी. सांसद ज़िम्मेदार होंगे तो संसद ज़िम्मेदार होगी और सांसद ग़ैर ज़िम्मेदार होंगे तो संसद भी ग़ैर ज़िम्मेदार होगी.

आजकल अचानक सांसदों को लगने लगा है कि उनका अपमान हो रहा है, उनके ऊपर उठाया गया सवाल उन्हें बेइज्जत करने के लिए उठाया गया है. इसलिए कुल मिलाकर देश बहुत सावधानी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे, यानी सांसदों के ऊपर कोई न बोले. सांसदों को किसी चीज के लिए ज़िम्मेदार न ठहराया जाए. अगर हम उन्हें ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो हम उनका विशेषाधिकार हनन करेंगे. अगर सवाल पूछें सांसदों से कि क्या आपको पता है, विशेषाधिकार का मतलब क्या है. आप विशेषाधिकार शब्द का इस्तेमाल धमकी के रूप में करते हैं. जबकि विशेषाधिकार सांसदों को इसलिए संविधान या संसद के नियमों में दिए गए, ताकि उनका उपयोग जब कोई अभूतपूर्व स्थिति आ जाए तब किया जाए, लेकिन हमारे सांसदों को अक्सर लगता है कि उनके विशेषाधिकारों का हनन हो गया. ऐसा शायद उन्हें इसलिए लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन छोड़ दिया है. चुनाव के अलावा हमारे सांसद कितनी बार अपने क्षेत्र में गए, यह जानना बहुत मुश्किल है. लोगों को अपने सांसदों से बातचीत करने के लिए भी जी-जान लगाना पड़ता है. वे उन्हें वैसे ही नज़र आते हैं, जैसे कभी-कभी, कोई त्योहार के अवसर पर अचानक सजा-धजा देवता सामने आ जाए. पार्टी के नेता भी जो संसद में हैं, वे भी लोगों के सामने तभी पहुंचते हैं, जब चुनाव का वक़्त हो या फिर उनके सम्मान का कोई अवसर हो. इस स्थिति में अगर कोई सवाल उठाए कि देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क आदि मुद्दों पर सांसद क्यों नहीं बोलते तो सांसदों को लगता है कि यह उनका अपमान है.

दो चीजों पर संसद में एक राय दिख जाती है. एक तो जब सुविधाओं में बढ़ोत्तरी का मसला हो या फिर सांसदों के अपमान का मामला हो. यह अभूतपूर्व एका होता है. सभी मिलकर सुविधाएं बढ़ाते हैं और सभी मिलकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए बांहें चढ़ा-चढ़ाकर भाषण देते हैं. जिस जनता ने चुना, वह अगर कुछ कहे तो इनका अपमान! जिस जनता ने इन्हें इस लायक़ बनाया, वह अगर कुछ बोले तो विशेषाधिकार का हनन और अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर ले, जैसे शर्म, अपराध, गिरोह तो इन्हें लगता है कि इनका इतना ज़्यादा अपमान हो गया कि अब अगर सारी जनता को भी फांसी पर चढ़ाना हो तो चढ़ा देना चाहिए! पहले मनीष सिसोदिया, फिर अरविंद केजरीवाल और अब बाबा रामदेव, इनके ख़िलाफ़ सांसदों के तेवर देखने लायक़ हैं. इन तेवरों से अगर कोई बात कम्युनिकेट होती है तो सिर्फ़ यह कि हमारे सांसद ग़ैर ज़िम्मेदारी की सीमा लांघ रहे हैं. संसद में उपस्थिति इनकी प्राथमिकता नहीं है, संसद में पास होने वाले बिल, संसद में होने वाली बहस इनकी प्राथमिकता नहीं है. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के ऊपर जब बहस होती है तो कोई संसद में दिखाई ही नहीं देता, लेकिन अगर कोई ऐसा बयान आ जाए तो सब संसद में आकर भौंहे चढ़ाकर, आंखें निकाल कर टेलीविज़न के कैमरे को जनता मानकर एक विराट विलक्षण रूप ज़रूर दिखाते हैं. अगर सांसदों को जनता के सामने जाने में संकोच होता है, तो वह कमज़ोरी उनकी है.

आजकल अचानक सांसदों को लगने लगा है कि उनका अपमान हो रहा है, उनके ऊपर उठाया गया सवाल उन्हें बेइज्जत करने के लिए उठाया गया है. इसलिए कुल मिलाकर देश बहुत सावधानी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे यानी सांसदों के ऊपर कोई न बोले. सांसदों को किसी चीज के लिए ज़िम्मेदार न ठहराया जाए. अगर हम उन्हें ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो हम उनका विशेषाधिकार हनन करेंगे. अगर सवाल पूछें सांसदों से कि क्या आपको पता है, विशेषाधिकार का मतलब क्या है. आप विशेषाधिकार शब्द का इस्तेमाल धमकी के रूप में करते हैं.

हम यह बात सांसदों को ज़रूर बता देना चाहते हैं कि आप जितना जनता की आकांक्षाओं से दूर जाएंगे, उतना ही आप देश के लोकतंत्र के साथ मज़ाक करेंगे. कोई बात नहीं, अगर आपको लोकतंत्र पसंद नहीं आता. कोई बात नहीं, अगर लोकतंत्र आपकी रगों में नहीं है. कहने को लोकतंत्र है, लेकिन दिमाग़ से आप तानाशाही के समर्थक हैं. आप नहीं चाहते हैं कि कोई शख़्स लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहे और आप उसका लोकतांत्रिक ढंग से उत्तर दें, राजनीतिक रूप से उत्तर दें. चूंकि आप यह नहीं चाहते हैं और फिर भी अपने को लोकतांत्रिक कहलाना चाहते हैं तो कहलाते रहिए, कम से कम जनता इस बात को नहीं समझेगी. जब संसद में कोई ऐसा बयान देता है तो मीडिया उसका बढ़-चढ़कर प्रचार करता है. हमारे दोस्तों को यह भी नहीं पता कि विशेषाधिकार हनन का मतलब क्या है, कब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है? एक भोंपू बजाना है और हमारे साथी भोंपू बजाने लगते हैं. जनता के ख़िलाफ़ जब आप लिखते हैं, बोलते हैं, उसकी आकांक्षाओं को जब अपने पैरों तले रौंदते हैं, तो वही होता है, जो पिछले चुनावों में आपके आकलन को लेकर हुआ. लोगों ने आपके आकलन का मज़ाक उड़ाया, आपकी रिपोर्ट को सिर्फ़ मनोरंजन के तौर पर देखा. आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों में ज़िम्मेदारी का अभाव पैदा हो गया है. वे अपनी ज़िम्मेदारी समझते ही नहीं हैं, माफी मांगना तो दूर की बात है.

अभी हाल में एक घटना हुई. सोनिया गांधी के घर पर कुछ मंत्रियों की बैठक हुई और यह ख़बर चल गई कि यह बैठक तो कामराज प्लान की तरह की बैठक है, जिसमें चार मंत्रियों ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की. अंदर वे राजनेता हंस रहे थे और बाहर हमारे मीडिया के साथी कैमरा लिए उनके इस्तीफ़े की प्रतीक्षा कर रहे थे. किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह बैठक क्यों हुई. जबकि बैठक एक बहुत गंभीर विषय पर हई थी. अभिषेक मनु सिंघवी के ख़िलाफ़ एक सीडी आई थी और गृहमंत्री चिदंबरम की सीडी आने वाली है, ऐसी अफवाह तेज़ हो गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों, जो ज़्यादा चालाक-चतुर माने जाते हैं, की बैठक गृहमंत्री चिदंबरम सहित सोनिया गांधी के घर पर हुई और लोकसभा की रणनीति के ऊपर बातचीत हुई. बेचारे नारायण सामी ने कहा भी कि यह संसद में रणनीति बनाने की बैठक है, लेकिन हमने नहीं माना. हमें लगा कि नहीं, यह तो कामराज प्लान-2 है. यह है हमारी समझ, यह है हमारी सोच. जब हम उन सांसदों का साथ देते हैं, जो जनता के हित के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन की बात करते हैं तो मैं माफी के साथ आपसे कहता हूं कि आपकी इज्जत जनता की नज़रों में कम होती है. क्या संसद में बलात्कार के आरोप लिए हुए लोग नहीं बैठे हैं, क्या संसद में दंगे का आरोप लिए लोग नहीं बैठे हैं, क्या संसद में भ्रष्टाचार का आरोप लिए लोग नहीं बैठे हैं, क्या संसद में ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जिन्हें निचली अदालत से सज़ा हो चुकी है और वे अपील में हैं?

अगर ये लोग बैठे हैं तो किस आधार पर अगली पंक्तियों में बैठने वाले नेता फावड़े चलाकर, आंखें निकाल कर यह कहते हैं कि हम संसद के विशेषाधिकार का हनन नहीं होने देंगे यानी अपने विशेषाधिकार का हनन नहीं होने देंगे. उन्हें समझना चाहिए कि ये बातें उनके विशेषाधिकार हनन में नहीं आती हैं. अभी पिछले तीन महीनों में आपने बहुत बार मुंह की खाई है. आपने सेना के मामले में मुंह की खाई है. अब तो संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कह दिया कि जनरल वी के सिंह की बातें ग़लत नहीं थीं. आईबी ने कह दिया कि उसके दफ्तर से कोई कागज़ लीक नहीं हुआ और सरकार ने भी मान लिया कि सेना की यह हालत है. उस समय जो लोग भौंहें चढ़ाकर, हाथ उठाकर, मुट्ठियां बांधकर धमकी दे रहे थे, वही आज फिर धमकी दे रहे हैं. इस बार जनता सामने है, थोड़ा संभलिए और थोड़ा समझिए. ■

संपादक

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कौन बनेगा राष्ट्रपति

अमेरिका के जनक को लोगों पर विश्वास नहीं था. उन लोगों ने इसे इस बात से दर्शाया कि न तो अमेरिकी राष्ट्रपति और न सीनेटर मतदाताओं द्वारा चुना जा सकेगा. अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है और यह कॉलेज स्वयं लोगों द्वारा चुना जाता है. इसी तरह बीसवीं सदी की शुरुआत में सीनेटर चुना जाना शुरू किया गया. फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चुनाव के दूसरे दौर के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है. फ्रांस के पांचवें गणराज्य ने चौथे गणराज्य की जगह ली है, जिसमें एक कमज़ोर राष्ट्रपति और मजबूत प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी. फ्रांस का चौथा गणराज्य तत्कालीन समस्याओं के समाधान में विफल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई थीं. पांचवें गणराज्य में राष्ट्रपति दो दौर के चुनाव के बाद निर्वाचित होते हैं और वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा में बहुमत के आधार पर चुना जाता है. इसका मतलब है कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग-अलग दलों के हो सकते हैं. संविधान न तो शाश्वत है और न ऐसा है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है.

भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है. इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिल सकता है. सामान्यत: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, लेकिन किसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसके बारे में कोई ज़्यादा शंका नहीं होती है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है, राष्ट्रपति भी उसी दल का होता है. इसका अपवाद 1969 में देखा गया, जब इंदिरा गांधी ने अपने दल के उम्मीदवार के बदले किसी दूसरे को समर्थन दिया था. उस समय इंदिरा गांधी ने अपने दल को विभाजित कर दिया था. देखा जाए तो भारतीय राजनीति पिछले 65 सालों में इतनी कमज़ोर कभी नहीं रही, जितनी अभी दिखाई पड़ रही है. इसका कारण है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए किसी भी उम्मीदवार पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है. किसी दल या गठबंधन को विश्वास नहीं है कि वह जिसे अपना उम्मीदवार बनाएगा, उसे बहुमत मिल ही जाएगा. यूपीए और एनडीए दोनों को ही अपनी कमज़ोरी मालूम है. दूसरी तरफ छोटे दल जैसे सपा, बसपा, टीएमसी एवं एआईडीएमके अपना अलग राग अलाप रहे हैं. वे किसी भी गठबंधन की ओर जा सकते हैं. ऐसे में किसी एक उम्मीदवार पर सहमति जताने की चाहत रहना ही सबसे बड़ी भूल है. इस समय की राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी एक उम्मीदवार पर सहमति जताई जा सके. अगर राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार होंगे तो दोनों बड़ी पार्टियों को अपनी पोल खुलने का डर है. इस परेशानी को दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कई उम्मीदवार हों और सभी को स्वतंत्र रूप से मतदान करने को कहा जाए. ऐसे में किसी दल को इस बात की परेशानी नहीं होगी कि उसका उम्मीदवार जीता या फिर हार गया. इस व्यवस्था में सबसे अच्छा यही होगा. इस देश के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है. ऐसे भी राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्य जनता मूकदर्शक बनी रहती है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारत पर गर्व किया जाता है. इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही यहां सरकार चलाई जाती है, लेकिन लोगों को मालूम है कि इसका परिणाम क्या निकलता है. सरकार अपना काम ठीक ढंग से करने में असफल रही है. लोग मतदान की व्यवस्था को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उनके मतदान का परिणाम निराशाजनक ही होगा. लोगों के लिए बेहतर यही है कि राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा करने के बजाय स्वयं पर भरोसा करें. अगर राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के लिए नया रास्ता नहीं खोलता है तो लोगों को आगे बढ़ना होगा. सिविल सोसाइटी को लोगों का नेतृत्व करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि लोग किस तरह का राष्ट्रपति चाहते हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति को ही यह तय करना पड़ेगा कि किस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह किसी का पक्ष न लें. अगर राष्ट्रपति किसी दल या गठबंधन से संबंधित नहीं होंगे तो वह पक्षपात रहित फ़ैसला ले सकेंगे.

भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है. इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिल सकता है. सामान्यत: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, लेकिन किसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसके बारे में कोई ज़्यादा शंका नहीं होती है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है, राष्ट्रपति भी उसी दल का होता है. इसका अपवाद 1969 में देखा गया, जब इंदिरा गांधी ने अपने दल के उम्मीदवार के बदले किसी दूसरे को समर्थन दिया था. उस समय इंदिरा गांधी ने अपने दल को विभाजित कर दिया था.

यूरोप का हाल-फिलहाल का अनुभव भी यही बताता है कि जिस देश में संसदीय व्यवस्था है, वहां फ़ैसला लेने में उस सरकार से ज़्यादा समय लगता है, जहां कोई एक व्यक्ति बहुमत का नेतृत्व करता है यानी जहां जनता राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करती है. बेल्जियम को फ़ैसला लेने में एक साल से अधिक का समय लग गया. ऐसी स्थिति में इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि सिविल सोसाइटी एकजुट होकर इस बात के लिए आवाज़ उठाए कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा. यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके लिए मतदान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, जिसमें राज्य और उसकी एसेंबली की भूमिका हो. लोगों को यह तय करने का अधिकार हो कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा. हो सकता है, इसके लिए तीन या चार नाम सामने आएं, लेकिन इससे इतना तो पता चल ही जाएगा कि जनता क्या चाहती है. इसके साथ-साथ नेताओं को भी इस बात की जानकारी हो जाएगी कि जनता क्या चाहती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्य के कृषि विभाग के उपनिदेशक केआर विजय कुमार ने बताया कि केरल के लोगों का पारंपरिक जीवन एवं जीविका नारियल पर टिकी है.

दिल्ली, 14 मई-20 मई 2012 चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

एक आवेदन से समाधान मिल जाएगा

आज देश में एक धारणा बन गई है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता है. बहुत हद तक यह विचार सही भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार उस सीमा तक पहुंच गया है, जहां एक ईमानदार आदमी का ईमानदार बने रह पाना मुश्किल हो गया है. लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था में भी आप यदि चाहें तो अपना काम बिना रिश्वत दिए करा सकते हैं. इसके लिए बस थोड़ी हिम्मत बनाकर रखनी होगी और सूचना क़ानून का इस्तेमाल करना होगा. हर आम या ख़ास आदमी का पाला कभी न कभी किसी सरकारी विभाग से पड़ता है. चाहे राशन कार्ड बनवाना हो या पासपोर्ट, आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, फाइल दबाने या आगे बढ़ाने के लिए सरकारी बाबुओं की रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुज़ुर्गों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु/जन्म-मृत्यु/आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इंकम टैक्स रिफंड लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है अलग से. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा. ऐसा नहीं है. काम ज़रूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए. ज़रूरत है सिर्फ़ अपने अधिकार के इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है सूचना का अधिकार. यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप घूसख़ोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. यह आज़माया हुआ और सफल नुस्ख़ा है. जैसे ही आप अपने लंबित काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं, भ्रष्ट और रिश्वतख़ोर अधिकारियों एवं बाबुओं की समझ में आ जाता है कि जिसे वे परेशान कर रहे हैं, वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक है. तय मानिए, सरकारी विभागों में आमतौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं हैं. सूचना क़ानून में इतनी ताक़त है कि छोटे-मोटे काम तो आवेदन देने के साथ हो जाते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बजाय घूस देकर काम कराने के. चौथी दुनिया आपके हर क़दम पर आपका साथ देने को तैयार है. कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपना अनुभव हमसे बांटना चाहते हों तो हमें पत्र लिखें या ईमेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

आपका पत्र

8 जून, 2011 को मैंने पटना पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था. दो महीन के अंदर पुलिस जांच भी हो गई. लेकिन तीन महीने बाद भी पासपोर्ट नहीं मिला. पटना कार्यालय से पता चला कि मेरी फाइल खो गई है और मुझसे कहा गया कि मैं नया फार्म जमा करूं. मेंने उनके कहे अनुसार फार्म जमा किया. लेकिन अब एक साल होने को है, मेरा पासपोर्ट नहीं मिला. मुझे क्या करना चाहिए.

मो. अकरम, *रोहतास, बिहार.*

इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं. आप अपने इस मामले में (पासपोर्ट के लिए) इस आवेदन का इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीद है कि इस आवेदन को डालने के बाद आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का स्वरूप

किसी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के विषय में सूचना के लिए आवेदन

(राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु-जन्म-मृत्यु-आवास आदि प्रमाण पत्र बनवाने या इंकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार करें)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
मैंने आपके विभाग में .... तारीख़ को .... के लिए आवेदन किया था. (आवेदन की प्रति संलग्न है) लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक क़दम नहीं उठाया गया है.
कृपया इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.

2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है?

3. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): इस सप्ताह आपके पारिवारिक-सामाजिक कार्य सर्वोपरि एवं मनोनुकूल होंगे. वाहन तेज न चलाएं और ज़्यादा मसालेदार भोजन से बचें. नौकरी और व्यापार में सोची योजना फलीभूत होगी और आप प्रसन्न रहेंगे. छोटी-मोटी भावनात्मक बातें, जो परिवारीजनों को आघात पहुंचा सकती हैं, उनसे बचें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): आप आवेश में न आएं, अन्यथा नुक़सान होगा. लेन-देन के कार्यों से बचें. इस सप्ताह आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें. कार्यस्थल पर अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे. विद्यार्थी मेहनत ज़्यादा करेंगे. स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

मिथुन (21 मई से 20 जून): ऐसी योजना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मामलों से जुड़ी हो, में सफल होंगे. पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद से बचें और उसके समाधान का प्रयास करें. कोई ऐश्वर्य की वस्तु और नए वस्त्र ख़रीदने के योग हैं, इसलिए ख़र्च बढ़ सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): किसी कार्य को जल्दबाज़ी में निपटाने का प्रयास न करें. इस सप्ताह परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. थोड़ी भाग-दौड़ रहेगी. नौकरीपेशा वाले लोग उन्नति का समाचार पाएंगे. व्यापारी आम तौर पर आर्थिक रूप से अच्छा करेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): इस सप्ताह आप पराक्रमी रहेंगे और किसी भी विरोधी के विरोध को अपनी शक्ति से ध्वस्त कर देंगे. दुश्मनों से ज़्यादा अपने मित्रों से बचाव रखें, वे नुक़सान पहुंचा सकते हैं. स्थानांतरण का समाचार पाकर विचलित न हों. अपना दायित्व आप परिवर्तित स्थान पर भी अच्छी तरह निभाएंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): मानसिक उद्विग्नता को अपने ऊपर हावी न होने दें, अन्यथा आप क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाएंगे. इस सप्ताह आप सफल होंगे, लेकिन अपनी सफलता के स्तर से प्रसन्न नहीं होंगे. ख़र्च बढ़ा रहेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य परेशानी का कारण बनेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): कोई मित्र आपकी परेशानियां कम करेगा. इस सप्ताह आप अपने धंधे में व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे. अपने अंदर किसी नकारात्मक जिद्द को हावी न होने दें, अन्यथा नुक़सान होगा. आर्थिक रूप से थोड़ा संकोच महसूस करेंगे, जिसके तनाव से शारीरिक परेशानी भी बढ़ेगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): भ्रमण की योजना बनेगी, जो फलदायी होगी. पारिवारिक शुभ कार्य होने का सप्ताह है. ज़मीन-जायदाद की ख़रीद-बिक्री सोच-समझ कर करने की ज़रूरत है. कानूनी मामलों से बचें. कोई आकस्मिक आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा. किसी विरोधी द्वारा विरोध करने पर अपने मन को विचलित न करें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): इस सप्ताह आपको उलझन ज़्यादा रहेगी और निर्णय लेने में थोड़ी उधेड़बुन की स्थिति रहेगी. व्यापारी ख़ुश रहेंगे और व्यवसाय अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा लोग को उन्नति का समाचार मिलेगा. विदेश से संबंधित किसी कार्य से लाभ मिलेगा. व्यय की अधिकता होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): इस सप्ताह आप हर्षित और उत्साहित रहेंगे. मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. भविष्य की चिंता सताएगी. सफलता मिलेगी, लेकिन किसी क़ानूनी दस्तावेज़ को देखने-सोचने के बाद हस्ताक्षर करें. संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा. किसी परिवारीजन का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): इस सप्ताह भाग-दौड़ बढ़ेगी और आप सफल भी ज़्यादा साबित होंगे. कोई पुराना पैसा आपको मिल सकता है. किसी कार्य में आने वाली बाधा से आप चिंतित न हों, अपना प्रयास निरंतर जारी रखें. वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा. धनोपार्जन बढ़ेगा, लेकिन किसी विवाद को तूल न दें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): संदिग्ध आचरण वाले मित्रों-व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें. आप भ्रमण में रहेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी. पारिवारिक सुख सर्वोत्तम रहेगा. किसी वाद-विवाद में अपनी बात सोच-समझ कर रखें. रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे और पूरी तन्मयता से उन्हें पूरा करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

cshekhar_3@hotmail.com

ज़रा हट के

अब बंदर नारियल तोड़ेंगे

केरल में श्रमिकों की कमी के कारण अब बंदरों को पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना है. पेड़ों पर चढ़ कर नारियल तोड़ना ख़तरनाक होने के साथ श्रम साध्य कार्य है. नारियल तोड़ने वाले श्रमिकों में कमी का प्रभाव राज्य के नारियल व्यवसाय पर पड़ा है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फलों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम विकल्प के तौर पर बंदरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

राज्य के कृषि विभाग के उपनिदेशक के आर विजय कुमार ने बताया कि केरल के लोगों का पारंपरिक जीवन एवं जीविका नारियल पर टिकी है. पेड़ पर चढ़ने वालों की संख्या में कमी के कारण यह व्यवसाय प्रभावित हुआ है. इसलिए हमने नारियल तोड़ने के लिए बंदरों को प्रशिक्षित करने के विषय में प्रस्ताव रखा. मनुष्यों से बढ़िया यह कार्य कर सकते हैं. थाइलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में पहले से ही बंदरों को नारियल तोड़ने के कार्य में लगाया गया है. लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन करने पर पशु अधिकारों के रक्षक विरोध कर सकते हैं. विजय कुमार ने कहा कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशु प्रेमी इस क़दम का विरोध कर सकते हैं.

कोच्चि स्थित नारियल विकास बोर्ड के अनुसार, केरल में डेढ़ करोड़ नारियल के पेड़ हैं और फल तोड़ने के लिए 40,000 लोगों की ज़रूरत है. राज्य में साक्षरता दर और खाड़ी देशों की तरफ़ बढ़ने से पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की कमी हो गई है. उन्होंने कहा कि एक प्रशिक्षित बंदर एक दिन में नारियल के क़रीब 500 पेड़ों पर चढ़ सकता है, जबकि मनुष्य एक दिन में 10 से ज़्यादा पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता. उन्होंने बताया कि बंदरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां इंडोनेशिया और थाइलैंड प्रशिक्षक आएंगे.

विजय कुमार की राय से नारियल विकास बोर्ड के एक सदस्य ने असहमति जताते हुए कहा कि नारियल के पेड़ से प्रत्येक 45 दिन में 60 फल लगते हैं. इस पर हमेशा फूल रहता है. कौन-सा फल तोड़ने लायक़ है या नहीं, इसका निर्धारण बंदर नहीं कर सकता. सदस्य ने बंदरों की जगह रोबोट के प्रयोग की वकालत की, पर कृषि विभाग के सदस्य ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि बोर्ड ने रोबोट का प्रयोग किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ. ■

प्यार में गंवाए दांत

प्यार में धोखा खाकर बहुत कुछ गंवाने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन यहां धोखा देने वाले प्रेमी को कुछ ओर ही गंवाना पड़ा. ऐसा ही वाकया लंदन के एक धोखेबाज़ आशिक के साथ हुआ. दरअसल यहां की एक 34 वर्षीय दंत चिकित्सक महिला एक 46 साल के व्यवसायी से प्यार करती थी. इस व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से दगाबाज़ी करते हुए किसी अन्य से प्यार की पींगे बढ़ाना शुरू किया. बात प्रेमिका तक पहुंची. उसे यह धोखेबाज़ी बर्दाश्त नहीं हुई. लिहाज़ा उसने प्रेमी को अपने क्लिनिक बुलाया और धोखे से उसके सभी दांत निकाल लिए. उस धोखेबाज़ आशिक का बुरा समय यही नहीं थमा. पूरे प्रकरण को जानने के बाद यह जिस दूसरी महिला से प्यार करता था, वह भी उसे छोड़कर भाग गई. ■

शादी करने के लिए बीमारी का बहाना

कुछ लोग अपने मक़सद को पूरा करने के लिए झूठ बोलने से क़तई गुरेज़ नहीं करते. ऐसा ही वाक़िया न्यूयॉर्क की एक युवती (25) का है, जिसने शादी करने के लिए फ़रेब का सहारा लिया. पिछले साल उसने एक समाचार प्रकाशित करवाया कि उसको ल्यूकेमिया कैंसर है और वह कुछ महीने बाद मरने वाली है. उसने लोगों से मदद का आग्रह करते हुए इच्छा व्यक्त की थी कि वह मरने से पहले शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं. ख़बर फैलते ही कई लोग मदद के लिए आगे आए और उसके पास कुल 13,368 डॉलर (क़रीब सात लाख रुपये) पहुंच गए. पैसा पाने के बाद उसने शादी की. एक साल बाद उसके पति ने तलाक़ के लिए आवेदन करते हुए मामले को उजागर किया कि इस युवती ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोला था. कोर्ट ने युवती को सज़ा के रूप में संबंधित लोगों को पैसा लौटाने का आदेश दिया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नेपाल में संविधान सभा का गठन मई 2008 में दो साल के लिए किया गया था, लेकिन इस अवधि में संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसका कार्यकाल बढ़ाया गया.

नेपाल

गणतंत्र या राजतंत्र

राजीव कुमार
rajiv@chauthiduniya.com

नेपाल संविधान सभा को इस साल 28 मई तक संविधान बना लेना है. समय निकट है, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि संविधान सभा यह काम कर पाएगी या नहीं. सरकार ने नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान सभा को मिले समय पर पुनर्विचार किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसका कोई क़ानूनी आधार नहीं है कि पिछले महीने के आदेश की समीक्षा की जाए. ग़ौरतलब है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा का कार्यकाल अंतिम बार और 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद संसद में संविधान सभा का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में 508 सांसदों में से 505 ने संविधान सभा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के पक्ष में मत व्यक्त किया था. कार्यकाल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाने से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. इसमें माओवादी लड़ाकों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर कई प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें फ़ैसले पर चिंता जताई गई. संसद और कैबिनेट ने कहा था कि शीर्ष न्यायालय का यह आदेश असंवैधानिक और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है. संविधान सभा के प्रमुख नेमवांग ने भी कहा था कि संविधान सभा के कार्यकाल की समीक्षा करने की याचिका ख़ारिज किए जाने से उन्हें धक्का लगा है. संविधान मसौदा समिति के प्रमुख नियंबर आचार्य ने देश की दो प्रमुख संस्थाओं के बीच टकराव को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था.

नेपाल में संविधान सभा का गठन मई 2008 में दो साल के लिए किया गया था, लेकिन इस अवधि में संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसका कार्यकाल बढ़ाया गया. बढ़े कार्यकाल के भीतर भी नए संविधान का निर्माण करने में सफलता नहीं मिली. इस तरह चार बार संविधान सभा का कार्यकाल बढ़ाया गया. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संविधान सभा का कार्यकाल अंतिम बार बढ़ाया जाएगा और वह भी सिर्फ़ 6 महीने के लिए. यह समय सीमा 28 मई, 2012 को समाप्त होने वाली है. संविधान सभा पर अब तक करोड़ों रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. संविधान सभा के सदस्य लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा है कि 27 मई तक संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन यह संविधान कैसा होगा, इस पर सहमति बनेगी कि नहीं, इस पर संदेह है. एक तरफ़ प्रधानमंत्री संविधान तैयार होने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ़ माओवादी नेता सी पी गजुरेल का कहना है कि नेपाल का संविधान तो भारत में पहले ही बन चुका है, जिसे केवल नेपाल लाया जाना है और उस पर अमल करना है. उनका कहना है कि भारत प्रायोजित इस संविधान को क़तई स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा. ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जा रहा है, उस पर सर्वसम्मति हो जाएगी. वैसे भी बाबूराम भट्टाराई पर यह आरोप लगता रहा है कि उनका प्रधानमंत्री पद पर चुनाव ही भारत की सहमति से हुआ है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के नेता प्रदीप ग्वाली का कहना है कि नया संविधान तभी स्वीकार किया जाएगा, जबकि शांति समझौता अमल में लाया जाए. इसके अलावा तराई में रहने वाले मधेशियों की अपेक्षाएं भी अलग हैं. उनका कहना है कि अगर संविधान में संघीय सरकार की बात नहीं की गई तो वे इसका विरोध करेंगे. तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेशियों का संबंध बिहार से रहा है. वे पहले भी माओवादियों से संघर्ष करते रहे हैं. उन्हें इस बात का डर है कि नेपाल में संघीय सरकार की अनुपस्थिति में उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है. अगर सारी शक्ति केंद्र के पास रही तो मधेशियों को अपनी बात मज़बूती के साथ रखने में परेशानी होगी और भविष्य में उनके लिए अपनी बात मनवाना मुश्किल हो जाएगा. तराई मधेशी लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त महासचिव जितेंद्र सोनार का कहना है कि सरकार के सामने एक कठिन चुनौती है. नया संविधान कैसा होगा, यह तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर वह तराई के हितों के ख़िलाफ़ होगा तो हम उसका विरोध करेंगे. इस तरह देखा जाए तो संविधान बनने के बाद भी उस पर सर्वसम्मति बनना बहुत मुश्किल होगा. संविधान पर सभी दलों की सहमति ज़रूरी है, अन्यथा शासन चलना मुश्किल हो जाएगा.

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आख़िर संविधान सभा ने चार सालों में संविधान का निर्माण क्यों नहीं किया. क्यों उसे बार–बार संविधान सभा का कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है. इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक दलों के बीच तालमेल का अभाव है. माओवादी भी दो धड़ों में विभाजित हैं. उनके बीच कई मतभेद हैं. सत्ता पाने से पहले उन्हें सत्ता के लिए संघर्ष करना था, लेकिन अब उन्हें सत्ता का स्वाद लग गया है. कम्युनिस्ट भी सत्ता पाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं. प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी के अंदर लॉबिंग की जा रही है. नेपाली कांग्रेस की स्थिति भी भिन्न नहीं है. तराई में रहने वाले मधेशियों की पार्टी को माओवादियों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि गृह युद्ध के समय उन्होंने माओवादियों के साथ संघर्ष किया था. वे अलग ही राग अलाप रहे हैं. ऐसी स्थिति में संविधान बने तो कैसे बने. इसलिए संविधान सभा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जब संसद में प्रस्ताव आता है तो 508 सांसदों में से 505 उसका समर्थन करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और इसीलिए उसने फिर से समय बढ़ाने की याचिका ख़ारिज कर दी थी. नेपाल में लोकतंत्र तो नब्बे के दशक में ही स्थापित हो गया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अहमियत नहीं बढ़ाई और न जनता के बीच अपनी पैठ बनाई. इसके बाद वहां माओवादियों का प्रभाव बढ़ा और गृह युद्ध शुरू हुआ. 2006 में गृह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद कई सरकारें बनीं, लेकिन स्थायित्व का नितांत अभाव रहा. पिछले नवंबर में शांति समझौता भी हुआ, जिसमें नेपाल की तीन प्रमुख पार्टियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी), नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के नेताओं ने भाग लिया. समझौते में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के शिविरों में रह रहे 19,600 माओवादियों में से एक तिहाई को सेना में भर्ती किया जाएगा. इसके अलावा क़रीब 12,000 माओवादियों को मुफ्त शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही उन्हें स्वरोज़गार के लिए 5 से 8 लाख रुपये तक की सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें. इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक दल आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं. बाबूराम भट्टाराई का कहना है कि 27 मई तक संविधान बन जाएगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट संविधान सभा को भंग कर सकती है. ऐसे में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच टकराव भी हो सकता है. नेपाल के सामने कई समस्याएं हैं. ग़रीबी, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारी से जूझते युवा, लड़कियों का अवैध व्यापार, गृह युद्ध के कारण निवेश में कमी और भारत–चीन के साथ सामंजस्य स्थापित करना आदि. ऐसे में एक नया विवाद नेपाल के लिए ख़तरनाक हो सकता है. देश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसमें तो जनता दिग्भ्रमित होगी और नेपाल के राजनीतिक दलों से उसका भरोसा उठने लगेगा. वैसे भी जनता के मन में राजघराने के प्रति कोई द्वेष नहीं है. अगर राजनीतिक दलों में यह क्षमता नहीं है कि वे एक सक्षम संविधान दे पाएं तो फिर जनता का भरोसा उनसे उठने लगेगा और राजघराने के समर्थन में जनमत तैयार होने लगेगा. नेपाल में कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं, जो राजशाही का समर्थन करती हैं. अगर राजशाही का समर्थन बढ़ता है तो फिर नेपाल गणतंत्र नहीं बन पाएगा. ऐसे में राजनीतिक दलों को तय करना है कि राजशाही लाई जाए या फिर नेपाल को एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनाया जाए. ■

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान और डॉ. ज़ाकिर हुसैन संस्थान द्वारा आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन नागालैंड के राज्यपाल निखिल कुमार ने किया.

पटना में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

मीडिया की भूमिका पर नज़र

अशरफ़ अस्थानवी

feedback@chauthiduniya.com

आज राष्ट्रीय या फिर प्रादेशिक स्तर पर उत्पन्न परिस्थिति में मीडिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है. यही वजह है कि सबकी निगाह मीडिया पर लगी हुई है. ऐसे में मीडिया अपनी भूमिका को किस रूप में तथा किस हद तक निभा पा रहा है, इस पर चर्चा के लिए पटना में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया. राष्ट्रीय विकास और मीडिया–दशा एवं दिशा विषय पर केंद्रित इस सेमिनार में वक्ताओं ने अपने विचार के ज़रिए यह बताने की कोशिश की कि आज़ादी की लड़ाई के वक़्त जिस जज्बे और स्वच्छता के साथ मीडिया ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, उसमें लगातार कमी आई है. लेकिन वक्ताओं ने यह भरोसा भी जताया कि क़लम अभी भोथरी नहीं हुई है, वरना देश में बड़े–बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर नहीं हो पाते.

सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान और डॉ. ज़ाकिर हुसैन संस्थान द्वारा आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन नागालैंड के राज्यपाल निखिल कुमार ने किया. अपने व्यापक प्रशासनिक तथा राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि आज विकास का लाभ वंचितों को मिले. उग्रवादी गतिविधियों में शामिल संगठनों को मुख्य धारा से जोड़ने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. नागालैंड में इस दिशा में हुए सुधार का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां हिंसा और अलगाववाद पर क़ाबू पाने के आसार बढ़े हैं और यह सबकुछ यूं ही नहीं हुआ इसके लिए कई स्तरों पर पहलें तेज़ हुईं और निरंतर हुई वार्ता के सकारात्मक नतीजे भी आने लगे हैं.

उन्होंने अपने संबोधन में पत्रकारिता में उत्पन्न कई ख़ामियों पर बेबाक टिप्पणी करते हुए मीडिया हाउस को भी पाठकों को गुमराह करने से बचने की नसीहत दी. निखिल कुमार को युवा पत्रकारों से अधिक उम्मीद है, तभी तो उनका कहना था कि वह अपने अंदर स्वतंत्र भावना को विकसित करें, क्योंकि जो क़लम उनके हाथ में है, उसमें बड़ी ताक़त होती है. इससे देश और समाज का भला भी हो सकता है और बुरा भी. इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता ने बड़े आंदोलनों का सूत्रपात किया है तथा कई परिवर्तनों का कारक भी बना है. ये बातें आज भी हो सकती हैं. उन्होंने पत्रकारों का आह्वान किया कि वह सामाजिक कमियों और कुरीतियों को उजागर करें. कुछ मीडिया हाउस में ख़बरों की लीपापोती पर उन्होंने अफ़सोस जताते हुए कहा कि यह गुनाह है, इससे बचना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मिशन होता है. आज़ादी से पूर्व इसका मिशन था देश की स्वतंत्रता और आज़ादी के बाद देश का विकास, लेकिन आज लगता है कि यह अपने मिशन से भटक गया है. आज उसके मिशन का व्यवसायीकरण हो गया है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने देश के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का ज़िक्र करते हुए मीडिया से इसके समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को कहा. उन्होंने मनरेगा को आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकार बड़ी धनराशि ख़र्च तो कर रही है, लेकिन इसका लाभ आम लोगों को पूरी तरह से आज भी नहीं मिल पा रहा है. मीडिया को चाहिए कि इस महत्वपूर्ण कार्य योजना पर पैनी निगाह रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों की हक़ मारी न हो सके. उन्होंने सुरेंद्र प्रताप सिंह, एम जे अकबर एवं संतोष भारतीय को पत्रकारिता का रोल मॉडल बताते हुए कहा कि स्वच्छ और धारदार मीडिया के लिए ऐसी ही शख्सियतों की ज़रूरत है. हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया की बेबाक पत्रकारिता की सराहना करते हुए इसके प्रधान संपादक संतोष भारतीय की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेना अध्यक्ष वीके सिंह प्रकरण में उन्होंने जीवंत पत्रकारिता की मिसाल पेश की है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में मानहानि का मामला चले, ताकि आम लोगों को भी पता चल सके कि सच को दबाने के लिए सियासी दल कौन–कौन से हथकंडे अपनाते हैं.

सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान और डॉ. ज़ाकिर हुसैन संस्थान द्वारा आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन नागालैंड के राज्यपाल निखिल कुमार ने किया. अपने व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि आज विकास का लाभ वंचितों को मिले. उग्रवादी गतिविधियों में शामिल संगठनों को मुख्य धारा से जोड़ने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

अपनी धारदार पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित वरिष्ठ पत्रकार एवं चौथी दुनिया साप्ताहिक के संपादक संतोष भारतीय ने इस मौक़े पर मुख्य वक्ता की हैसियत से आज की पत्रकारिता पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पत्रकारिता तभी आम आदमी के हित में होगी, जब पत्रकार तारीफ़ लिखने के बजाय घटनाओं की तह में जाकर निष्पक्षता के साथ अपनी क़लम चलाए. उन्होंने कहा कि पहले किसी पत्र–पत्रिका के संपादक 60–70 वर्ष से कम उम्र के नहीं होते थे, लेकिन ओजस्वी पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इस मिथक को तोड़ा और महज़ 30 वर्ष की उम्र में ही वह प्रतिष्ठित रविवार पत्रिका के संपादक बने. उन्होंने देश में उजागर हुए बड़े–बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का ज़िक्र करते हुए इसे उजागर करने का श्रेय मीडिया को दिया और कहा कि यह मीडिया की जीवंतता और इसकी प्रभावी भूमिका को दर्शाता है. उन्होंने बड़े ही संतुलित अभिव्यक्ति में कहा कि तारीफ़ करना पत्रकारिता का धर्म नहीं होता, पर जबरिया नकारात्मक चीज़ों का ढूंढना पीत पत्रकारिता है, इससे दूर रहने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉक्टर मरीज़ के सौंदर्य की बजाय उसका मर्ज़ देखता है, इसी तरह पत्रकार को तारीफ़ों के पुल बांधने के बजाय कुरीतियों एवं कमियों को सबके सामने लाना चाहिए. उन्होंने विकास की कमियों को उजागर करने की ज़रूरत बताते हुए कहा कि पत्रकारिता का रिश्ता विकास से भी है. उन्होंने पत्रकारिता में सुरेंद्र प्रताप सिंह के अहम योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी सत्ता से समझौता नहीं किया. इसलिए पत्रकारों को अपनी क़लम बेचने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज देश के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपनी पैठ अपने हक़ में इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. ऐसे में परेशान लोगों की उम्मीदें मीडिया से काफ़ी बढ़ गई हैं. इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी इस भूल के लिए मीडिया को माफ़ नहीं करेगी.

डॉ. ज़ाकिर हुसैन संस्थान के महानिदेशक प्रो. उत्तम कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि समस्त उपलब्धियों का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों तथा अभावग्रस्त नागरिकों तक पहुंचाना मीडिया का अहम कर्तव्य है. उनका कहना था कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में मीडिया का महत्व बढ़ा है. मीडिया ने आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक अपना अहम रोल निभाया है. दूरदर्शन केंद्र पटना के निदेशक एसपी सिंह का कहना था कि मीडिया देश और समाज को सही राह दिखा सकता है. सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रो समीर कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह संस्थान विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है. इस संस्था के डिग्रीधारी देश के कोने–कोने में फैले हैं और वे अपनी पत्रकारिता का जौहर दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह संस्थान मात्र बिहार राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एक आदर्श संस्थान है जो धर्मवीर भारती, सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदर्शों और उनके सपनों पर आधरित शिक्षा देने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है. उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से एमए पत्रकारिता, बीजेडीएम के पाठ्यक्रम में और भी सुधार लाया जाएगा. सेमिनार के आयोजन में डॉक्टर राकेश ने भी सक्रिय भूमिका निभाई. ■

मेहनत रंग लाएगी, लेकिन...

प्रतिभा है, निष्ठा है और ईमानदारी भी. लेकिन आर्थिक कमी की वजह से इनका सपना पूरा होते-होते रह जाता है. यह कहानी है, उन नौजवानों की जिनके पास एक सपना है. उस सपने को पूरा करने का जज़्बा भी है. ऐसा उन्होंने अपने प्रयास से साबित करके दिखाया है. लेकिन इनके सपनों को पंख लगें, इसके लिए ज़रूरत है कि कोई आगे आए और उनकी मदद करे. क्या कोई इस सपने को पूरा करने के लिए आगे आएगा?

राजीव रंजन

feedback@chauthiduniya.com

जहां चाह है वहां राह है, लेकिन अपनी मंज़िल की ओर बढ़ना जितना आसान है उतना ही कठिन भी. कुछ ऐसा ही हाल है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली) के 13 छात्रों का, जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की. मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी. दरअसल, पूरा माजरा यह है कि ये छात्र एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहे हैं, जो पानी के अंदर सक्रिय होगा, जिसे एयूवी यानी एकोयूस्टिक अंडरवाटर व्हेकिल्स कहा जाता है. इस टीम में बिहार के औरंगाबाद के कमलेश कुमार (टीम लीडर), हिमांशु गुप्ता, आशीष शर्मा, हिमांशु जैन, राहुल चौहान, अभिषेक जय कुमार, हिमांशी भारद्वाज, अश्विन अग्रवाल, मानव कपूर, रोहित शर्मा, आदित्य नागर, भारत त्रिपाठी और सुमित गुप्ता शामिल हैं. उनकी टीम का नाम है, टीम समुद्र. 13 जून, 2011 को चेन्नई में एनआईओटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्तर भारत से यही एकमात्र टीम थी, जिसने प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई और रनर–अप भी रही. उनके इस जोश को देखकर एनआईओटी के वैज्ञानिक भी दंग रह गए, क्योंकि मुक़ाबला इतना आसान नहीं था. इस मुक़ाबले में देश भर से आए आईआईटी और एनआईटी के छात्रों को टीम समुद्र ने कड़ी टक्कर दी. अब उन्हें प्रोत्साहन के साथ-साथ ज़रूरत थी थोड़ी सी आर्थिक मदद की. ज़ाहिर सी बात है कि किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के अलावा पैसों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है. इन छात्रों ने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की कि कोई उनके साथ खड़ा हो, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी. शायद इस वजह से क्योंकि उनका कॉलेज कोई नामी गिरामी कॉलेज नहीं था. फिर भी इन छात्रों ने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा और इस रोबोट पर काम करते रहे. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रोबोट को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैवीनिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग की गहन जानकारी होना आवश्यक है. लेकिन इनमें से किसी भी छात्र का मैकेनिक्स प्रमुख विषय नहीं है. फिर भी इन छात्रों के पास इतनी जानकारी है कि ये अपनी जानकारी की बदौलत इस रोबोट को बनाकर खड़ा कर सकते हैं. इन छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस रोबोट को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया. तारीफ़ तो सबने की, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया. एयूवी बनाने का प्रयास हालांकि 2008 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन राह इतनी आसान न थी. इसे बनाने के लिए होनहार छात्रों की ज़रूरत थी, जिनके क़दम किसी भी परिस्थिति में न डगमगाएं. आख़िरकार फाइनल टीम का चुनाव कर लिया गया. इन छात्रों में जोश था, उमंग थी और कुछ कर गुज़रने की चाह भी, जो इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद ज़रूरी थी. सब मिले और उन्होंने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया. ये अब अपने एयूवी को पानी के अंदर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अफ़सोस उन्हें जगह तक नहीं मिली. इतनी कठिन परिस्तिथियों से दो चार होने के बावजूद उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है और अब उन्होंने सारा ज़िम्मा अपने ही कंधों पर उठा लिया है. इसे बनाने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ों को ये ख़ुद ही ख़रीदेंगे और इस रोबोट को आख़िरी रूप देंगे. अब ये छात्र एयूवीएसआई संस्थान और ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च (ओएनआर) द्वारा 17 से 22 जुलाई, 2012 तक आयोजित होने वाली 15वें अंतरराष्ट्रीय रोबो सब प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. यह प्रतियोगिता सैन डियेगो अमेरिका में होगी. अगर इन होनहार छात्रों की मेहनत रंग लाती है तो ये न सिर्फ़ विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी, बल्कि पूरे देश के लिए भी गर्व की बात होगी. ■

मंत्रालय का तर्क है कि उसे प्री सेंसरशिप का अधिकार नहीं है. सवाल यह है कि प्री सेंसरशिप का अधिकार नहीं है, वह तो ठीक है,

फिल्म पर डर्टी सलाह

अनंत विजय

anant.ibn@gmail.com

फिल्म डर्टी पिक्चर को एक निजी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित न करने की सलाह देकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनल को भेजी अपनी सलाह में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 का सहारा लिया और उसके सब–रूल 5 एवं 6 का हवाला देते हुए फिल्म का प्रसारण रात ग्यारह बजे के बाद करने की सलाह दी गई. केबल टेलीविजन रूल यह कहता है कि किसी भी चैनल को बच्चों के न देखने लायक कार्यक्रम के प्रसारण की इजाज़त उस वक़्त नहीं दी जा सकती, जिस वक़्त बच्चे सबसे ज़्यादा टीवी देखते हों. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यह मानकर चल रहा है कि रात ग्यारह बजे के बाद बच्चे टीवी कम देखते हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस बात की जानकारी कहां से मिली कि दोपहर बारह बजे सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे टीवी देखते हैं, उसका आधार क्या है. क्या सिर्फ़ मान लिया गया है कि दिन में ज़्यादा संख्या में बच्चे टीवी देखते हैं या फिर उसका कोई वैज्ञानिक आधार मंत्रालय के पास मौजूद है. क्या रात ग्यारह बजे के बाद बच्चे टीवी नहीं देखते हैं? मंत्रालय के आला अफसर अब तक उसी पुरातन काल में जी रहे हैं, जब यह माना जाता था कि बच्चे खा–पीकर रात नौ बजे तक सो जाते हैं. समाज में हो रहे बदलाव और बच्चों की बदलती लाइफ स्टाइल को मंत्रालय नज़रअंदाज़ कर रहा है.

महानगरों की तो बात छोड़ दें, किस शहर में अब बच्चे ग्यारह बजे तक सोते होंगे, वह भी छुट्टी वाले दिन. मंत्रालय को लगता है कि वह निजी टीवी चैनल पर डर्टी पिक्चर का प्रसारण रुकवा कर बच्चों, किशोरों को यह फिल्म देखने से रोक लेगा. आज बच्चों के लिए इंटरनेट का एक्सेस इतना आसान है कि यह काम मुमकिन ही नहीं है. किशोरों के हाथ में जो मोबाइल फोन है, उसमें भी इंटरनेट की सुविधा मौजूद है. समाज बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, बदल रही है लोगों की सोच, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बैठे कर्ता–धर्ता अभी तक पाषाणकाल में जी रहे हैं. दरअसल, यहां मूल कारण बच्चे नहीं, कुछ और है, जिसका ख़ुलासा होना चाहिए. दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता की ज़िंदगी पर बनी इस फिल्म को पहले तो सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया, लेकिन बाद में पचास से ज़्यादा दृश्यों पर कैंची चलाने के बाद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए यानी यूनिवर्सल एडल्ट का दर्जा दे दिया. एडल्ट फिल्म और यूनिवर्सल एडल्ट फिल्म में बुनियादी फ़र्क़ है. सोलह साल से कम उम्र के बच्चे सिनेमाहॉल में एडल्ट फिल्में नहीं देख सकते हैं, भले ही वे अपने माता–पिता के साथ क्यों न हों, लेकिन जो यूनिवर्सल एडल्ट फिल्म होती है, उसे बच्चे अपने अभिभावक के साथ देख सकते हैं. माना यह गया था कि कई फिल्में बच्चे अपने माता–पिता के साथ देख सकते हैं, ताकि उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर साथ में बैठे माता–पिता दे सकें. अब अगर यही नियम डर्टी पिक्चर को टीवी पर दिखाए जाने पर लागू किया जाता तो भी उसका प्रसारण रोकने की सलाह देना सरासर ग़लत था. अगर बच्चे अपने घर में माता–पिता की मौजूदगी में डर्टी पिक्चर देखना चाहें तो देखें.

दरअसल, यहां मूल कारण बच्चे नहीं, कुछ और है, जिसका ख़ुलासा होना चाहिए. दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता की ज़िंदगी पर बनी इस फिल्म को पहले तो सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया, लेकिन बाद में पचास से ज़्यादा दृश्यों पर कैंची चलाने के बाद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए यानी यूनिवर्सल एडल्ट का दर्जा दे दिया.

जिस तर्क के आधार पर डर्टी पिक्चर का प्रसारण रात ग्यारह बजे के बाद करने लायक़ माना गया, क्या वही तर्क मनोरंजन चैनलों पर दिखाए जा रहे धारावाहिकों पर लागू नहीं होता. ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब एक चैनल पर सबसे ज़्यादा दर्शक संख्या वाले वक़्त पर इस जंगल से मुझे बचाओ जैसा धारावाहिक दिखाया गया, जिसमें नायिकाएं बेहद कम कपड़ों में झरने के नीचे नहाती हुई दिखाई गईं. बिग बॉस में चाहे वह अस्मित एवं वीना मलिक के एक ही बिस्तर में लेटकर संवाद के दृश्य हों या फिर राहुल महाजन एवं उसकी नायिका के स्वीमिंग पूल में तैरने के दृश्य, क्या वे एडल्ट की श्रेणी में नहीं आते? हाल में एक धारावाहिक में लंबे–लंबे चुंबन दृश्य दिखाए गए तो उस वक़्त मंत्रालय ने क्या कर लिया? हमारे देश में सच का सामना जैसा कार्यक्रम भी दिखाया गया, जिसमें सीधे–सीधे पूछा जाता था कि आपने पत्नी के अलावा कितनी महिलाओं से जिस्मानी संबंध बनाए. उसे भी रात ग्यारह बजे के बाद दिखाने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पसीने छूट गए थे.

मंत्रालय का तर्क है कि उसे प्री सेंसरशिप का अधिकार नहीं है. सवाल यह है कि प्री सेंसरशिप का अधिकार नहीं है, वह तो ठीक है, लेकिन क्या रात ग्यारह बजे से पहले वैसे दृश्यों को दिखाने वाले चैनलों के ख़िलाफ कोई कार्रवाई की गई? सिर्फ़ चेतावनी देकर खानापूरी कर ली गई. अब भी कई चैनलों पर ऐसे धारावाहिक चल रहे हैं, जिनके संवाद इतने अश्लील होते हैं कि आप परिवार के साथ बैठकर उन्हें देखने में ख़ुद को असहज महसूस करते हैं, लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों को उस वक़्त केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट की याद नहीं आती है, क्यों? दूसरी जो अहम बात है, वह भी समझ से परे है. इस फिल्म में शानदार भूमिका निभाने के लिए फिल्म की नायिका विद्या बालन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई. अब यहां भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फंस गया है. नियमों के मुताबिक़, जिस भी फिल्म को, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह अभिनय हो या फिर गीत से लेकर साउंड रिकॉर्डिंग तक, अगर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो उस फिल्म को टैक्स फ्री करना पड़ता है, साथ ही उसे दूरदर्शन पर भी दिखाया जाता है. अब अगर मंत्रालय यह मानता है कि यह फिल्म बच्चों के देखने लायक़ नहीं है तो क्या दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण रात ग्यारह बजे के बाद ही किया जाएगा या फिर दूरदर्शन पर डर्टी पिक्चर का प्रसारण नहीं किया जाएगा. दूरदर्शन की पहुंच केबल टीवी से कहीं ज़्यादा है, यह बात तो प्रामाणिक है. क्या डर्टी पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाएगा या फिर इस नियम की भी काट मंत्रालय निकाल लेगा? ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

काव्य दुनिया

बुर्क़ा

जब ख़ुदा मेरी देह बना रहा था
उसी समय उसने
तुम्हारी आंखों पर
बनाया था हया का पर्दा
तुमने मन की कालिमा से
एक लिबास बनाया
और
हमने पहन लिया
तुम्हारी कालिख छिपाने के लिए
तुम हमेशा मुझे पर्दे के मायने समझाते हो
और मैं हां–हां में सिर हिलाती हूं
मन करता है
तुम्हारी बातों की मुख़ालफ़त करूं
मैं जानती हूं कि
बेहयाई मेरे बदन में नहीं है
जो ढंक लूं किसी लिबास से
बल्कि वो तैर रही है तुम्हारी आंखों में
बाग़ी, बेख़ौफ़ लड़ती हुई हर पल
हया के पर्दे से ■

सुशील कुमार
पाण्डव नगर, दिल्ली

प्रेम से ज़िंदगी में रंग भरें

फ़िरदौस ख़ान

firdaus@chauthiduniya.com

शिशिर श्रीवास्तव की पुस्तक–आपके भीतर छिपी सफलता पाने की आठ शक्तियां निराशा में डूबे लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. इसमें बताया गया कि किस तरह ज़िंदगी से मायूस व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर सकता है. लेखक का कहना है कि उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की राह आपके अपने हाथों में है. ईश्वर भी आपको मार्गदर्शन देंगे और राह दिखाएंगे, पर आधा रास्ता तय होने के बाद. किसी ने कहा है कि कोई भी लौटकर नए सिरे से आरंभ नहीं कर सकता, किंतु कोई भी अबसे आरंभ करते हुए एक नया अंत रच सकता है. बक़ौल हज़रत इनायत ख़ान, आत्मा को उज्ज्वल कर देने वाले शब्द रत्नों से भी अधिक मूल्यवान होते हैं. किताब का एक अध्याय है प्रेम की शक्ति. प्रेम एक कर देने वाली वह शक्ति है, जो ब्रह्मांड में हमें हमारा सच्चा उद्देश्य पाने में सहायक होती है. यह भाव उष्मा, आदान–प्रदान, आनंद, करुणा, आभार, निकटता, सेवाभाव और क्षमा से संबंध रखता है. अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक़, एक मनुष्य उसी संपूर्ण का अंश है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं. वह अंश जो समय और काल से सीमित है. वह स्वयं का, अपने विचारों का और भावनाओं का सबसे अलग अनुभव करता है. चेतना का दृष्टिभ्रम एक क़ैद है, जो हमें हमारी निजी इच्छाओं और निकटतम जन के स्नेह तक ही बांध देता है. हमें सभी जीवों और प्रकृति के प्रति करुणा का भाव विस्तृत करते हुए इस दायरे को बढ़ाना चाहिए.

प्रेम शब्द का प्रयोग प्राय: दो प्रेमियों के बीच सशक्त स्नेह भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है. वहीं दूसरी ओर शर्त या समझौता रहित प्रेम परिवार के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों और अन्य वचनबद्ध संबंधों के लिए होता है. जब आप किसी व्यक्ति से उसके कार्यों या मान्यता से परे जाकर प्रेम करते हैं तो वह अन्कंडीशनल लव कहलाता है. सच्चा प्यार सबके लिए होता है, जैसे सूर्य की किरणें, जो उष्मा देती हैं. गुलाब की पंखुड़ियां जीवन में रंग और आनंद लाती हैं, पर्वत का झरना मुक्त रूप से प्रवाहित होता है और सभी जीवों के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है. लोग इसी प्रेम के अभाव में क्रोध, उलझन और व्यग्रता के शिकार होते हैं. जिस तरह शरीर को भोजन और पानी चाहिए, उसी तरह हमारे मन को भावनात्मक रूप से स्नेह चाहिए. जहां भी इसका अभाव होता है, लोग असामान्य रूप से व्यवहार करते हैं तथा दूसरों के ध्यानाकर्षण के लिए हिंसक और आक्रामक साधनों का सहारा लेते हैं.

प्रेम वही है, जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए. यहां बदले में कोई अपेक्षा नहीं होती है. जब हम सच्चे हृदय से सबको स्नेह देने लगते हैं तो ब्रह्मांड से हमारा कोई तार जुड़ जाता है और हमारे भीतर से सूर्य की तरह प्रेम की उज्ज्वल और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है. सूर्य की तरह प्रेम की शक्ति का प्रभाव स्वयं पर भी पड़ता है. हम सच्चा स्नेह देते हैं तो बदले में स्वयं भी वही पाते हैं. जब आप धरती के सभी जीवों को एक समान भाव से स्नेह देते हैं तो सबके साथ जुड़ाव का एक गहरा नाता विकसित होता है. हम परस्पर और प्रत्येक से एक सशक्त संबंध रखते हैं. इस प्रकार प्रेम की शक्ति हमें सदा उपलब्ध रहती है. आप बक़ौल सर विंस्टन चर्चिल, हमें जो मिलता है, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं. हम जो देते हैं, उससे एक जीवन बनाते हैं. जब आप स्वयं को क्रोध, ईर्ष्या और वासना आदि नकारात्मक भावों से मुक्त कर देते हैं तो आपके हृदय के भीतर सच्चे प्रेम के अंकुर विकसित होते हैं. जब आप इन भावों को मिटा देते हैं तो आपके भीतर ब्रह्मांड के सकारात्मक प्रवाह को समा लेने का स्थान बन जाता है. यह अच्छे कर्मों और क्षमादान के अभ्यास से ही संभव है. प्रेम की शक्ति अपने साथ सत्यता, सौंदर्य, ऊर्जा, ज्ञान, स्वतंत्रता, अच्छाई और प्रसन्नता का वरदान लाती है. जब चारों ओर प्रेम होता है तो नकारात्मक प्रभाव भी क्षीण हो जाते हैं. प्रेम की सकारात्मक तरंगें नकारात्मकता को मिटा देती हैं. जब आप तुलना छोड़कर स्वयं को सृजन चक्र से जोड़ देते हैं तो आपके हृदय में बसी प्रेम की शक्ति में निखार आता है. मदर टेरेसा ने कहा था, हम इसी उद्देश्य के लिए जन्मे हैं, प्रेम करने और पाने के लिए.

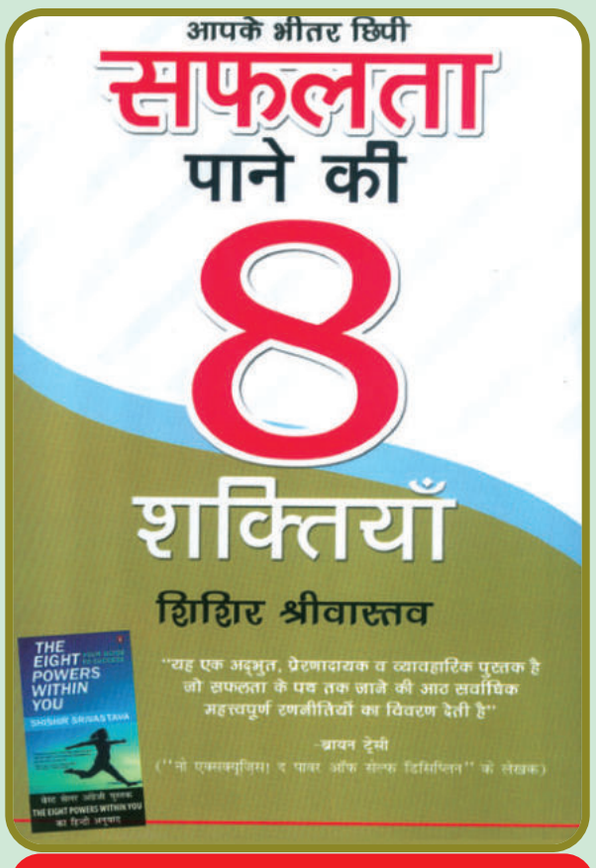

समीक्ष्य कृति : आपके भीतर छिपी सफलता पाने की 8 शक्तियां
लेखक : शिशिर श्रीवास्तव
प्रकाशक : डायमंड बुक्स
मूल्य : 125 रुपये

प्रेम रचनात्मक विचारों के प्रति केंद्रित होने में सहायक होता है, हमें अपने लक्ष्यों पर भरोसा बनाए रखने में सहायक होता है, हमारी कल्पना एवं आंतरिक शक्ति में वृद्धि करता है. यह एक रचनात्मक और निरंतर बनी रहने वाली ऊर्जा है और आकाश के तारों की तरह अनंत है. प्रेम में चुंबकीय और चमत्कारी शक्तियां हैं और ये पदार्थ और ऊर्जा से परे हैं. एक बेहद रोचक कहानी है. एक निर्धन लड़का अपनी शिक्षा का ख़र्च चलाने के लिए घर–घर जाकर वस्त्र बेचता था. एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में केवल दस सेंट बचे हैं. वह भूखा था, उसने तय किया कि वह अगले घर से थोड़ा भोजन मांगेगा. जब उसने एक ख़ूबसूरत युवती को घर का दरवाज़ा खोलते देखा तो उसकी भूख मर गई. वह भोजन की बजाय एक गिलास पानी मांग बैठा. युवती ने उसे पानी की बजाय दूध ला दिया. लड़के ने दूध पीने के बाद पूछा, इसके लिए कितना देना होगा? जवाब मिला, तुम्हें कुछ नहीं देना होगा, मेरी मां ने सिखाया है कि किसी की भलाई करने के बाद उससे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. लड़का बोला, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं. कई वर्षों बाद वह महिला बीमार हो गई. स्थानीय डॉक्टरों ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में भेज दिया, ताकि वहां के विशेषज्ञ उसकी खोई सेहत लौटा सकें. वहां डॉ. हावर्ड कैली कंसल्टेंट थे. जब उन्होंने महिला के शहर का नाम सुना तो स्वयं वहां पहुंच गए. उन्होंने झट से उस दयालु महिला को पहचान लिया और उसकी प्राण रक्षा का संकल्प लिया. वह पहले दिन से ही उस मामले पर विशेष ध्यान देने लगे और वह महिला स्वस्थ हो गई. उन्होंने निर्देश दे रखे थे कि महिला का बिल उन्हें ही दिया जाए. उन्होंने बिल देखा और उसके कोने पर कुछ लिखकर महिला के कमरे में भेज दिया. महिला को लगा कि उसे आजीवन वह भारी बिल अदा करना होगा, पर बिल के कोने में लिखा था, एक गिलास दूध के बदले में दिया गया: डॉ. हावर्ड कैली.

दरअसल, प्रेम आपके भीतर विनय भाव पैदा करता है. क्षमा करना आत्मा का सौंदर्य है, जिसे प्राय: नकार दिया जाता है. हो सकता है कि कई बार दूसरे आपके कष्ट का कारण बनें. आप स्वयं को आहत और क्रोधित पाएंगे. ऐसे में आपको इसे भूलना सीखना होगा. किसी को क्षमा करते ही आपके मन को भी चैन आ जाएगा. आप भी अतीत के घावों से मुक्त होंगे और समय सारे कष्ट सोख लेगा. यहां आपका माफ़ करने और भुला देने का निर्णय अधिक महत्व रखता है. बक़ौल मैक्स लुकाडो, क्षमा देने का अर्थ है, किसी को मुक्त करने के लिए द्वार खोलना और स्वयं को एक मनुष्य के रूप में एहसास दिलाना. जब आप स्वयं तथा दूसरों से सच्चा प्रेम करते हैं तो पाएंगे कि पूरा संसार आपसे प्रेम करने लगा है. लोग धीरे–धीरे आपको चाहने लगेंगे. यदि लोग परस्पर ईमानदारी और प्रेम से बात करें तो सभी संघर्षों का समाधान हो सकता है. जब आप प्रत्येक समस्या का सामना प्रेम से करेंगे तो आपका कोई शत्रु नहीं होगा. लोग आपको एक नई नज़र से देखेंगे, क्योंकि उनके विचार अलग होंगे और वे आपके बारे में पहले से एक प्रभाव बना चुके होंगे. बक़ौल गोथे फॉस्ट, एक मनुष्य संसार में वही देखता है, जो उसके हृदय में होता है. एक सदी पहले तक लोग बिना किसी पासपोर्ट या वीजा, बिना किसी पाबंदी के पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे. राष्ट्रीय सीमाओं का पता तक नहीं था. दो विश्व युद्धों के बाद कई राष्ट्र स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे, पहचान का संकट उभरा और कई संकीर्ण राष्ट्रवादी भावनाएं सामने आ गईं. ये भावनाएं इतनी मज़बूत थीं कि बच्चों को अपने ही देश की सभ्यता और परंपरा पर गर्व करना सिखाया जाने लगा और देशभक्ति का विचार पनपा. इसने पूरी दुनिया के धनी और निर्धनों की खाई को गहरा कर दिया. बक़ौल मोकीची ओकादा, यदि आप संसार से प्रेम करेंगे और लोगों की सहायता करेंगे तो आप जहां भी जाएंगे, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे. किताब बताती है कि इंसान के अंदर ही वह शक्ति छिपी हुई है, जिसे पहचान कर वह अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव ला सकता है. ■

किताब मिली

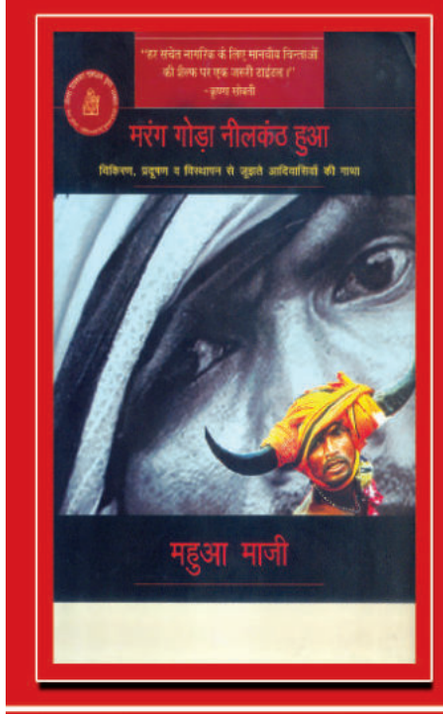

पुस्तक का नाम
मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ

लेखिका
महुआ माजी

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
495 रुपये

यह उपन्यास विकिरण, प्रदूषण एवं विस्थापन से जूझते आदिवासियों की गाथा है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

कैमरे की सबसे बड़ी ख़ासियत है इसमें दिया गया 4के रेज्योलूशन सपोर्ट, जबकि ज़्यादातर डीएसएलआर कैमरों में 3 के सपोर्ट दिया जाता है.

अनोखे डिजाइन के पोर्टेबल स्पीकर

ज़माना टेक्नोलॉजी का है, नई–नई तकनीक और फीचर्स के साथ बाज़ार में एक्सेसरीज मिल रहे हैं. ऐसे ही स्पीकर्स को लेकर भी बाज़ार में काफ़ी वैरायटी मौजूद हैं. एक नज़र दौड़ाकर देखें तो पूरा बाज़ार पोर्टेबल स्पीकर्स से भरा हुआ है. अलग–अलग क़ीमत के अनोखे डिजाइन वाले स्पीकर आपको आसानी से मिल जाएंगे. ऐसे में अपनी पसंद का पोर्टेबल स्पीकर चुनना काफ़ी मेहनत का काम है.

लेकिन म्यूस मिनी कंपनी ने यह काम आसान किया है. कंपनी ने नए पोर्टेबल यूएसबी स्पीकर्स लांच किए हैं. आकार में बेहद छोटे नए म्यूस स्पीकर्स का लुक देखने में काफ़ी अलग है. सिलेंडर शेप के इन स्पीकर्स को आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सकता है, क्योंकि इनका वज़न काफ़ी कम है. कंपनी ने म्यूस स्पीकर्स को सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और ग्रीन कलर में बाज़ार में पेश किया है. अगर आप चाहें तो इन्हें ब्लूटूथ की मदद से अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं. वैसे इनमें कार्ड की सुविधा भी दी गई है. हालांकि स्पीकरों में बॉस और ट्रबल साउंड एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, मगर फिर भी इनकी साउंड क्वालिटी शानदार है. वॉयरलेस कनेक्टीविटी की सुविधा वाले इन स्पीकर्स की क़ीमत 2,339 रुपये है. ■

वेस्पा एलएक्स के साथ शानदार सफ़र

वेस्पा एलएक्स न केवल अपने आकर्षक लुक के कारण दमदार है, बल्कि इसके फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशन भी बेहद ही शानदार हैं. कंपनी ने इस स्कूटर में 125 सीसी की क्षमता का 4 स्ट्रोक, 3 वॉल्व इंजन प्रयोग किया है. सिंगल सिलेंडर एअर कूल्ड सिस्टम इस स्कूटर को और भी शानदार बना देता है. सस्पेंशन के मामले में भी इस स्कूटर का कोई तोड़ नहीं है. पुराने समय के स्कूटरों में सस्पेंशन को लेकर लोगों को काफ़ी दिक्क़तों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण लोग स्कूटरों पर भरोसा नहीं करते थे. लेकिन नई वेस्पा एलएक्स में कंपनी ने फ्रंट और रियर दोनों में बेहतरी सस्पेंशन तकनीक का प्रयोग किया है. कंपनी ने इस स्कूटर में कोल स्प्रिंग और ड्यूल इफेक्टर शॉकर का प्रयोग किया है, जो ख़राब से ख़राब रास्ते पर भी आपको आरामदायक राईड का अनुभव कराएगी. इस स्कूटर में एक और ख़ास बात यह है कि कंपनी ने इसकी सीट को भी काफ़ी आरामदेह बनाया है. नई वेस्पा एलएक्स125 में कंपनी ने लंबी सीट का प्रयोग किया है. इसके अलावा सीट की ऊंचाई भी एक बेहतरीन स्कूटर के मानक को ध्यान में रखकर तय की गई है. कंपनी ने नई वेस्पा एलएक्स125 में एक से बढ़कर एक फीचर्स को शामिल किया है. नई वेस्पा एलएक्स125 में 4 स्ट्रोक, 3 वॉल्व, सिंगल सिलेंडर इंजन है. यह एअर कूल्ड सिस्टम पर बेस्ड है. इसमें लगे इंजन की क्षमता 125 सीसी है. यह स्कूटर 10.06 पीएस की अधिकतम गति देती है, 7500 आरपीएम पर अधिकतम टॉर्क, 10.6 एनएम 6000 आरपीएम पर देती है. यह वैरिएबल ट्रांसमिशन देता है. इसमें कीक और सेल्फ दोनों स्टार्ट सिस्टम दिया गया है. भारतीय बाज़ार में इस स्कूटर की क़ीमत 66,661 रुपये तय की गई है. नई वेस्पा एलएक्स125 रंगों के मामले में भी बेहद शानदार है. वेस्पा आपको 6 बेहतरीन रंगों में से स्कूटर चुनने का मौक़ा दे रहा है, जिसमें मोंटे बियानको व्हाईट, निरो वोल्कैनो ब्लैक, गियालो लाईम पीला, रोसो ड्रैगन लाल, रोसो चियान्टी डार्क बैगनी, मिडनाईट ब्लू जैसे शानदार रंग शामिल हैं. ■

कंपनी ने इस स्कूटर में कोल स्प्रिंग और ड्यूअल इफेक्टर शॉकर का प्रयोग किया है, जो ख़राब से ख़राब रास्ते पर भी आपको बेहतरी राईड का अनुभव कराएगी.

दुनिया का सबसे पतला टैबलेट

सबसे पतले फोन के बाद जल्द दुनिया का सबसे पतला टैबलेट भी पीसी बाज़ार में आ चुका है. पीसी क्षेत्र की जानी मानी कंपनी तोशीबा ने एक्साइट 10 नाम से इस टैबलेट को लांच किया है. टैबलेट को दो मॉडलों 16 जीबी और 32 जीबी में लांच किया गया है. 10 इंच स्क्रीन साइज के तोशीबा एक्साइट 16 जीबी मॉडल को 26,698 और 32 जीबी टैबलेट को 30,220 रुपये में लांच किया गया है. एक तरह से देखा जाए तो तोशीबा के एक्साइट 10 की क़ीमत एप्पल आईपैड के 16 जीबी मॉडल से 1,511 रुपये ज़्यादा है. अगर एप्पल आईपैड 2 से तोशीबा एक्साइट 10 के साइज की तुलना करें तो आईपैड 2 (0.34 इंच) के मुक़ाबले एक्साइट 10 (0.30 इंच) टैबलेट ज़्यादा पतला है, जिससे इसका लुक तो आकर्षक लगता ही है. साथ में इसका भार भी कम हो गया है, जो कैरी करने में यूजर को सहूलियत प्रदान करता है. तोशीबा एक्साइट 10 में 10 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो 1,280/800 रेज्योलूशन सपोर्ट करता है. इसमें ओएमएपी 4430 मल्टीकोर प्रोसेसर है, जो 1.2 गीगाहर्ट स्पीड देता है. इस पतले टेबलेट में 2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा भी दिया गया है. लिड लाइट सपोर्ट इसमें 16 जीबी और 32 जीबी मेमोरी ऑप्शन डाले गए हैं. यूटीलिटी फीचर्स में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, जायरो सेंसर, एसलरोमीटर, जीपीएस दिए गए हैं. इसमें बढ़िया क्वालिटी की साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं. इस ख़ास टेबलेट की क़ीमत 16 जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ 26,698 रुपये और 32 जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ 30,220 रुपये है.■

क्राइसलर जीप का ड्रैगन अवतार

अमेरिका की क्राइसलर कंपनी ने हाल में अपनी ब्रांड जीप का बेहतरीन मॉडल पेश किया है. इस मॉडल को ख़ासकर ड्रैगन की थीम पर तैयार किया गया है. चीन में ड्रैगन की थीम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, उसी को ध्यान में रखकर कंपनी ने इस मॉडल को पेश किया है. बेहद शानदार इंजन क्षमता और बेहतरीन लुक के साथ इस मॉडल को उतारा गया है. इस ड्रैगन थीम रैंगलर को कंपनी ने लिमिटेड एडिसन के तौर पर पेश किया है.

नई रैंगलर में कंपनी ने बेहतरीन एक्सटीरियर के साथ-साथ आकर्षक इंटीरियर भी दिया है. विशेषकर इसमें प्रयोग किया गया एलईडी लाईट किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है. इसमें 18 इंच 5-स्पोक एलॉय व्हील और 35 इंच ऑफ रोड टायर का प्रयोग किया गया है, जो पथरीले से पथरीले रास्ते पर भी दमदारी से फर्राटा भरने में सक्षम है. इस ड्रैगन को चीन में पेश किए जाने के दौरान क्राइसलर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक मेनले ने यह भी बताया कि कंपनी ने इस जीप को ख़ासकर चीन के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सिनेमा मेकिंग डीएसएलआर कैमरा

डिजिटल कैमरा निर्माता कंपनी कैनन ने बाज़ार में एक नया डीएसएलआर कैमरा लांच किया है, जो साधारण डीएसएलआर कैमरों से बिल्कुल अलग है. इसके लुक को देखकर ही आप जान जाएंगे कि इसमें कितना पॉवरफुल लैंस लगा हुआ है. अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं तो कैनन का नया ईओएस 1डी सी आपको पसंद आएगा. कैमरे में 18 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर लगा हुआ है. कैमरे की सबसे बड़ी ख़ासियत है इसमें दिया गया 4के रेज्योलूशन सपोर्ट, जबकि ज़्यादातर डीएसएलआर कैमरों में 3 के सपोर्ट दिया जाता है. एक तरह से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए कैनन ईओएस 1डी सी प्रयोग कर सकते हैं. कैनन ने अभी नए डीएसएलआर कैमरे की क़ीमत के बारे में कोई ख़ुलासा नहीं किया है, मगर जानकारों के अनुसार यह 50 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के बीच उपलब्ध होगा. इसमें 18 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर के साथ एचडी रिकॉर्डिंग की सुविधा दी गई है. इसमें यूजर्स की सहूलियत के लिए एसडीएमआईपोर्ट सपोर्ट दिया गया है. यह 24 फ्रेम पर सेकेंड की दर से 60 पिक्सल फुल एचडी रिकॉर्डिंग करता है. इस कैमरे में ड्यूल सीएफ शॉट की सुविधा दी गई है. ■

एल जी दक्षिण पश्चिम एशिया के अध्यक्ष और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंड़िया के निदेशक सून क्वोन, दिल्ली में एल जी थ्री डी सिनेमा स्मार्ट टेलीविजन की लॉन्चिंग के अवसर पर . फोटो- प्रभात पाण्डेय

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सचिन सांसद बने

नवीन चौहान
navinchauhan@chauthiduniya.com

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मनोनीत कर दिया है. अब सचिन तेंदुलकर संसद सदस्य बन गए हैं. फैंस को सचिन को सांसद के रूप में देखकर हर्ष हो रहा है. राजनीतिक गलियारा इस विषय में दो ख़ेमों में विभाजित है. सचिन के राज्यसभा सदस्य बनने से सभी ख़ुश हैं, लेकिन विपक्षी दल इसे कांग्रेस की डर्टी पिक्चर बता रहे हैं, कोई इसे असंवैधानिक क़रार दे रहा है, कोई मराठी मानुष को लुभाने की कांग्रेसी चाल बता रहा है. सचिन अभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं. इसलिए हर तबक़े के लोगों ने सचिन के संसद में पहुंचने की ख़बर का विश्लेषण करना शुरू कर दिया. लोगों के ज़हन में सवाल उठा कि क्या सचिन को संसद सदस्य बनाए जाने का यह सही समय है? क्या सचिन के पास संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय होगा?

यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है. लेकिन यह कोई पहला मौक़ा नहीं है, जब कोई खिलाड़ी सांसद बना हो, सचिन से पहले संसद पहुंचने वाले अधिकांश खिलाड़ी संसद के निचले सदन लोकसभा में लोगों द्वारा चुनकर आए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आज़ाद, चेतन चौहान, नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अज़हरुद्दीन लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंचे. उनमें से अधिकांश खिलाड़ी वर्तमान लोकसभा में सांसद हैं. सचिन को संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने के दो दिन पहले ही पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने बीजू जनता दल के टिकट पर ओडिशा से राज्यसभा का चुनाव जीता है. लेकिन यह ख़बर नहीं बन सकी. सचिन का किया हर काम हमारे लिए ख़बर है, इसलिए यह मेगा न्यूज बन गई.

सचिन के राजनीति में आने की कई ख़बरों का खंडन सचिन ने ख़ुद ही कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना, मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका. यह सम्मान बड़े-बड़े लोगों को मिला है, जिसमें लता मंगेशकर और पृथ्वीराज कपूर जैसे लोग शामिल हैं. मुझे मेरे क्रिकेट की वजह से यह सम्मान मिला है. मैं खिलाड़ी था, खिलाड़ी हूं और खिलाड़ी ही रहूंगा. राजनीति मेरा काम नहीं है. हां, मेरी उपलब्धि खेल में है और मैं खेलों के विकास के लिए संसद में काम करने की कोशिश करूंगा.

लोग सचिन को उनके क्रिकेट के प्रति लगाव, उनकी ईमानदारी और उनके समर्पण के लिए जानते हैं. साथ ही वह समाज सेवा के कई कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये ख़बरें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि सचिन नहीं चाहते हैं कि लोग उन्हें ग़रीबों का मसीहा कहें. वह आज भी क्रिकेट से भारत की सेवा कर रहे हैं और लोग उन्हें ऐसा करते देखना चाहते हैं. लोग भारत में संसद सदस्य इसलिए बनना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें नाम, पहचान और पैसा मिलता है. सचिन के पास ये सब पहले से ही है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोग बिना किसी बंधन के उन्हें बेहद प्यार करते हैं और उन पर यक़ीन करते हैं. लोगों की उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं. लोगों के ज़हन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सचिन संसद में कुछ अप्रत्याशित कर सकेंगे? क्या वह भारतीय में खेल क्रांति ला देंगे? क्या सचिन संसद में खेल बिल पर बोलेंगे? क्या सचिन संसद में लोकपाल बिल के समर्थन में बोलेंगे? सचिन के पास देश में अन्य खेलों के विकास के लिए क्या प्लान है? सचिन भारत को एक स्पोर्ट्स नेशन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सचिन के पास न तो कोई जादू की छड़ी है, जिससे वह कोई आश्चर्यजनक काम कर दें. अभी भी वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनके पास संसद के लिए समय कम ही होगा. लोग उन्हें आज भी क्रिकेट के मैदान में ही देखना चाहते हैं.

सचिन से पहले जो खिलाड़ी संसद में पहुंचे, वहां उनका प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा. कीर्ति आज़ाद और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी छाप राजनीति में छोड़ पाए हैं. दोनों ने अपने कार्यकाल में लगभग सौ-सौ सवाल संसद में उठाए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा की है. लेकिन देश में खेल के विकास से संबंधित योजनाओं पर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है. सचिन से पहले कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपने खेल करियर के बाद राजनीति में क़दम रखा और वहां भी बड़ा मुक़ाम हासिल किया. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने वाले इमरान ख़ान, रूस के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव, पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा और सनथ जयसूर्या कुछ प्रमुख लोग हैं, जिन्होंने अपने-अपने तरीक़े से राजनीति में क़दम रखा और अपने देश के विकास में योगदान दिया.

सचिन ने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, तब भी लोग दो ख़ेमों में विभाजित थे. लोगों का कहना था कि सचिन की उम्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिहाज़ से कम है, उन्हें कुछ समय बाद टीम में शामिल किया जाना चाहिए. लेकिन इन सभी अटकलों के बावजूद सचिन ने 16 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क़दम रखा और आज तक अंगद की तरह मैदान पर अपने क़दम जमाए हुए हैं. आज वह क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं. राजनीति में सचिन के क़दम समय भी लोग दो ख़ेमों में विभाजित हैं. मैदान पर बल्ले से अपने आलोचकों का मुंह बंद करने वाले सचिन से आशा है कि संसद में भी वह अपने प्रदर्शन से फिर अपने आलोचकों के मुंह बंद करते नज़र आएंगे. ■

ग्वार्डिओला ने बार्सिलोना के कोच का पद छोड़ा

बार्सिलोना के सबसे सफल कोच पेप ग्वार्डिओला ने अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया है. उनका यह फ़ैसला स्पेनिश लीग के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड के ख़िलाफ़ हार के बाद आया है. इससे पहले बार्सिलोना ने लगातार तीन साल तक यह ख़िताब अपने नाम किया था. अपने इस निर्णय के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने पद छोड़ने का फ़ैसला दिसंबर में ही कर लिया था, वह केवल सीजन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे. कोच के रूप में ग्वार्डिओला ने बार्सिलोना को तेरह ख़िताब जितवाए हैं. जिनमें तीन स्पेनिश लीग, दो क्लब वर्ल्डकप, दो यूरोपियन सुपर कप ख़िताब मुख्य रूप से शामिल हैं. उनकी देखरेख में बार्सिलोना ने कुल 242 मैच खेले, जिनमें से 175 में उन्हें जीत हासिल हुई. टीम ने कुल 618 गोल किए और केवल 178 गोल उनकी टीम के ख़िलाफ हुए. ग्वार्डिओला ने अपने भविष्य की किसी भी योजना का ख़ुलासा नहीं किया. उन्होंने चेल्सी के कोच बनने की ख़बर का खंडन करते हुए कहा कि मैं किसी दूसरी टीम के संपर्क में नहीं हूं. मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूं. ■

आदित्य मेहता ने एशियन स्नूकर का ख़िताब जीता

आदित्य मेहता एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का ख़िताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. दोहा में हुई प्रतियोगिता के फाइनल मुक़ाबले में उन्होंने हमवतन पंकज आडवाणी को 7-5 के अंतर से हराकर ख़िताब अपने नाम किया. आदित्य तीसरी बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे. पिछले साल वह इस प्रतियोगिता में उपविजेता रहे थे. लेकिन इस साल वह भाग्यशाली रहे. आठ साल बाद एशियन चैंपियन ट्रॉफी भारत आ रही है. 2004 में आलोक कुमार ने यह प्रतियोगिता जीती थी. पंकज आडवाणी दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे, मगर इस बार भी वह यह ख़िताब जीतने में नाकाम रहे. प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर ईरान के हुसैन वाफ़ई रहे. ■

बहरेन ग्रां प्री फार्मूला वन की छवि पर सवाल

बहरेन फार्मूला वन रेस ख़त्म हो गई और सबेस्टियन विटल विजेता भी बन गए. लेकिन इसके आयोजन से जुड़े विवाद खुले तौर पर सामने आ गए हैं, जो फार्मूला वन की छवि को ख़राब कर रहे हैं. फार्मूला वन रेस के ख़िलाफ़ बहरेन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद आयोजकों ने सरकार के दबाव में कड़ी सुरक्षा के बीच रेस आयोजित कर दी. रेस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ. बहरेन की सरकार ने इस आयोजन से दुनिया को यह संदेश देना चाहा कि 14 महीनों से जारी सरकार विरोधी मुहिम के बावजूद यहां हालात नियंत्रण में हैं. ■

शारापोवा ने जीता स्टुटगार्ड टूर्नामेंट

रूसी टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापावा ने स्टुटगार्ड टूर्नामेंट का ख़िताब जीत लिया है. यह शारापोवा का साल का पहला और करियर का 25वां एकल ख़िताब है. टूर्नामेंट के फाइनल में शारापोवा ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को सीधे सेटों में 6-1,6-4 से हराया.क्लेकोर्ट में खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता को जीतकर शारापोवा ने 27 मई से होने वाले फ्रेंच ओपन के लिए ख़ुद को बड़े दावेदार के रूप में पेश किया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नडाल ने सातवीं बार बार्सिलोना ओपन जीता

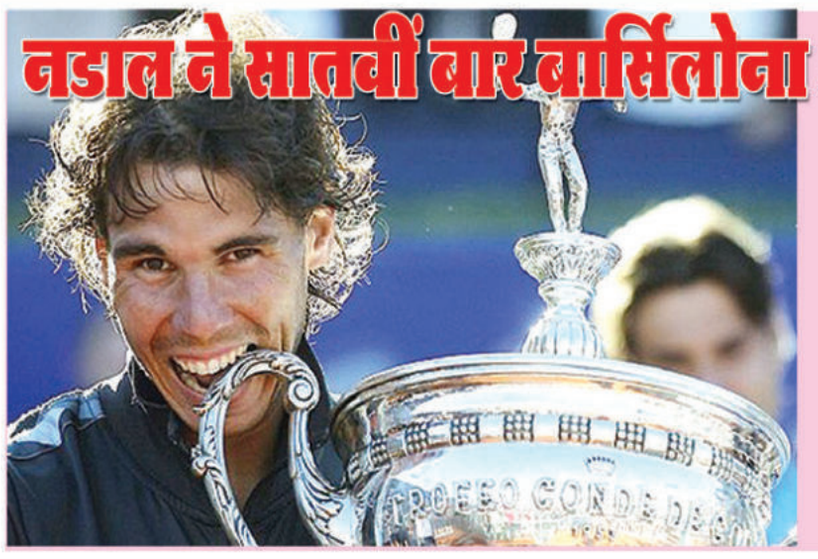

किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल ने सातवीं पार बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है. उन्होंने फाइनल में हमवतन डेविड फेरर को तीन घंटे चले कड़े मुक़ाबले में 7-6,7-5 से हराया. क्लेकोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट को जीतकर नडाल ने 27 मई से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीतने के प्रबल दावेदार बन गए हैं. ■

हिंदी सिनेमा को वह इंटरनेशनल बनाने का उपक्रम सोचने लगे. लिहाज़ा बिना सिर पैर की फ़िल्में बनने लगीं. हॉलीवुड की नक़ल से फ़िल्में फ्लॉप होने लगीं.

सौ साल का हिंदी सिनेमा

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

सौ साल पहले रूपहले पर्दे पर वर्ष 1913 में 21 अप्रैल को पहली श्वेत-श्याम हिंदी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को दर्शकों ने देखा, तो सबको अजूबा लगा. फिल्मी पर्दे पर पहले-पहल वह नज़ारा सचमुच स्वप्न लोक जैसा ही था. राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक, निर्माता और लेखक दादा साहब फाल्के थे, जिन्होंने इंग्लैंड जाकर फिल्म तकनीक सीखने के लिए ज़ेवर बेच दिए थे और उनका यह प्रयास मील के पत्थर की तरह साबित हुआ. राजा हरिश्चंद्र फिल्म में हरिश्चंद्र का किरदार दत्तात्रेय दामोदर दबके, रानीमती तारा की भूमिका पीजी सेन और विश्वामित्र की भूमिका जीवी सेन ने निभाई थी. इस फिल्म में सारे पात्र पुरुष थे. 40 मिनट की इस फिल्म की रील 3 हज़ार 7 सौ फुट लंबी थी. सिनेमा जगत के इतिहास में दादा साहब फाल्के की यह फिल्म अविस्मरणीय है. फाल्के साहब के बनाए मार्ग पर कोलकाता स्थित मदन टॉकीज के बैनर तले ए ईरानी ने पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया. इस फिल्म की शूटिंग रात में रेलवे लाइन के निकट की गई थी. इस फिल्म में डायलॉग कम गाने ज़्यादा थे. इस फिल्म के बारे में निर्माता श्याम बेनेगल ने बहुत ख़ूब कहा है कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत बातचीत के माध्यम से नहीं, बल्कि गानों के माध्यम से हुई है. हालांकि हिंदी सिनेमा में फिल्म आलम आरा ने प्राण फूंके हैं. उसके बाद ही एक से बढ़कर एक अभिनेता और अभिनेत्रियां फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने लगीं और गीतकारों और संगीतकारों के बीच होड़ लग गई, जिससे हिंदी सिनेमा को पंख लग गए. शुरुआती दौर में धार्मिक और पारिवारिक फिल्में बनीं. वर्ष 1935 में बनी फिल्म हंटरवाली में पोशाक और पहनावे ने समाज में नए फैशन का आगाज़ किया. उसके बाद 1949 में राजकपूर की फिल्म बरसात ने तहलका मचा दिया. फिल्म हिट ही इसलिए हुई थी कि उसमें अभिनेत्री नरगिस ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था. जिस पौधे को फाल्के साहब ने लगाया, उसे पुष्पित पल्लवित करने का काम पृथ्वीराज राज कपूर ख़ानदान ने किया. फिल्म निर्माता बिमल रॉय की दो बीघा ज़मीन ने देश के किसानों की दयनीय दशा दर्शायी. यह भारत की पहली ऐसी फिल्म थी, जिसे कॉन फिल्म अवॉर्ड मिला था. फिर यहीं से शुरू हुआ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हिंदी फिल्मों का दौर. शांताराम की साल 1957 में बनी फिल्म दो आंखें बारह हाथ, फणीश्वरनाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी मारे गए गुलफ़ाम सशक्त कथानक के बल पर पूरे देश में छा गई. इसके अलावा बदनाम बस्ती, आषाढ़ का दिन, सूरज का सातवां घोड़ा और नदिया के पार जैसी कई फिल्में चर्चा में आईं. वहीं देवदास, बंदिनी, सुजाता और परख फिल्में काफ़ी सफल रहीं. महबूब ख़ान की साल 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया मील का पत्थर साबित हुई. वहीं सत्यजीत रे की फिल्म पांथेर पांचाली और शंभू मित्रा की फिल्म जागते रहो को ख़ूब शौहरत मिली. निर्माता निर्देशक आसिफ़ ने मुग़ले आज़म के माध्यम से सिनेमा जगत की बुलंदियों को छुआ. त्रिलोक जेटली ने हिंदी सिनेमा के बल पर गोदान का फिल्मांकन कर सामाजिक कुरीतियों को लोगों के सामने रखा. साहित्य का यह प्रयोग फिल्मों के लिए प्राणदायी तो बना ही, वहीं प्रेरणादायी भी साबित हुआ. फिल्म निर्माता गुरु दत्त ने जहां प्यासा, काग़ज़ के फूल, साहब बीवी और ग़ुलाम बनाई, वहीं मुज़फ्फ़र अली ने गमन और विनोद पांडे ने एक बार फिर का फिल्मांकन किया. यह दौर लता मंगेशकर, रफ़ी मोहम्मद, किशोर कुमार जैसे गायकों के लिए स्वर्ण युग बनकर उभरा. उनकी आवाज़ का जादू फिल्मी दुनिया में छा गया. निपुण गीतकार संगीतकार और कलाकारों के चलते सिनेमा का चस्का लोगों को लग चुका था. युवाओं में सिनेमा देखने की ललक इस क़दर बढ़ी कि वे अब आने वाली हर इस पिक्चर की बाट जोहने लगे. सिनेमा देखने के लिए देहात से दूर शहरों के सिनेमाघरों तक जाने लगे. सिनेमा घरों में सत्यजीत रे की कमर्शियल फिल्मों का चलन पर्दे पर हो चुका था.

80 का दशक आते-आते फिल्मी विधा बदलने लगी. जादूगर, तूफ़ान, नास्तिक जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राजकुमार, सुनील दत्त जैसे बड़े अभिनेताओं ने क़िरदार निभाया था. अच्छे हीरो और हीरोइनों का पारिवारिक फिल्मों में एक छत्र राज था. उन्हें देखने के लिए देश के सिनेमाघरों में दर्शकों की अपार भीड़ होती थी. एक ओर हिंदी सिनेमा का नया स्वाद चखने को जनता बेक़रार तो दूसरी तरफ़ कलर टेलीविजन का आग़ाज़. सिनेमा प्रेमियों ने सिनेमाघरों को सप्ताहांत तक ही सीमित कर दिया.

60 के दशक में धर्मेंद्र, देवानंद, राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे सितारे बुलंदी पर थे. चुलबुले अंदाज़ के शम्मी कपूर ने अपना अलग मुक़ाम बनाया. फिल्म गंगा-यमुना, मुग़ले-आज़म ने मानो तहलका मचा रखा था. 70 के दशक के राजेश खन्ना सुपरस्टार बनकर उभरे. बॉक्स ऑफिस में एंग्री यंग मैन की भूमिका में अमिताभ बच्चन का पदार्पण हुआ. यहीं से मिलना शुरू हुआ फिल्मों को गोल्डेन जुबली और डायमंड जुबली का ख़िताब. 80 का दशक आते-आते फिल्मी विधा बदलने लगी. जादूगर, तूफ़ान, नास्तिक जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राजकुमार, सुनील दत्त से दिग्गज अभिनेताओं ने क़िरदार निभाया था. अच्छे हीरो और हीरोइनों का पारिवारिक फिल्मों में एक छत्र राज था. उन्हें देखने के लिए देश के सिनेमाघरों में दर्शकों की अपार भीड़ होती थी. एक ओर हिंदी सिनेमा का नया स्वाद चखने के लिए जनता बेक़रार तो दूसरी तरफ़ कलर टेलीविजन का आग़ाज़. ऐसे में सिनेमा प्रेमियों ने सिनेमाघरों को सप्ताहांत तक ही सीमित कर दिया. फिर भी फिल्म निर्माता शांत नहीं थे, इनका प्रयोग जारी रहा. इनके नए आविष्कार ने घिसे-पिटे डांस की जगह डिस्को डांस का प्रचलन ला दिया, जिसके आधार पर एक्शन फिल्में तैयार की जाने लगीं. इसी दौरान इंसाफ़ का तराज़ू, उमराव जान जैसी सफल फिल्में बनीं. जहां फिल्म राजा बाबू, गोविंदा का जादू चल गया, वहीं एक दो तीन में माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती छा गए. पारिवारिक फिल्मों में जितेंद्र, श्रीदेवी, जयाप्रदा, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल की भूमिका सराहनीय थी. जयाप्रदा और माधुरी दीक्षित बप्पी लहरी की धुन में नाचने लगे. 90 के दशक में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का दौर चल निकला, लेकिन गानों से मिठास ग़ायब थी. बॉलीवुड अब हॉलीवुड की नक़ल करने लगा था. इसके कारण पारिवारिक फिल्में फिल्मकारों के ज़ेहन से हटने लगीं, क्योंकि वह हॉलीवुड की दुनिया की चकाचौंध में खोने लगे थे. हिंदी सिनेमा को वह इंटरनेशनल बनाने का उपक्रम सोचने लगे. लिहाज़ा बिना सिर पैर की फिल्में बनने लगीं. हॉलीवुड की नक़ल से फिल्में फ्लॉप होने लगीं, लेकिन कुछ फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, जो जीता वही सिकंदर, इत्यादि फिल्में पर्दे पर छा गईं. आमिर ख़ान, सलमान ख़ान और शाहरूख़ ख़ान जैसे सितारे उभरे. इस तिकड़ी ने हिंदी सिनेमा को चार चांद लगा दिए. ये सितारे हर अदा में नाचे, इनका जादू सिनेमा प्रेमियों के सिर चढ़कर बोला. खलनायकों की बात करें तो अजीत, प्राण, अमजद ख़ान, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, रंजीत आदि ने विलेन की भूमिका निभाकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया. वहीं विश्व सुंदरियों ने अपनी प्रतिभा सिनेमा जगत में उडेलने में कसर नहीं छोड़ी है. आज जिस दौर में हम हैं, हिंदी सिनेमा में हुए प्रयोग की एक नई दास्तां से रूबरू हो रहे हैं. ■

ज़ोहरा जबीं नहीं रहीं

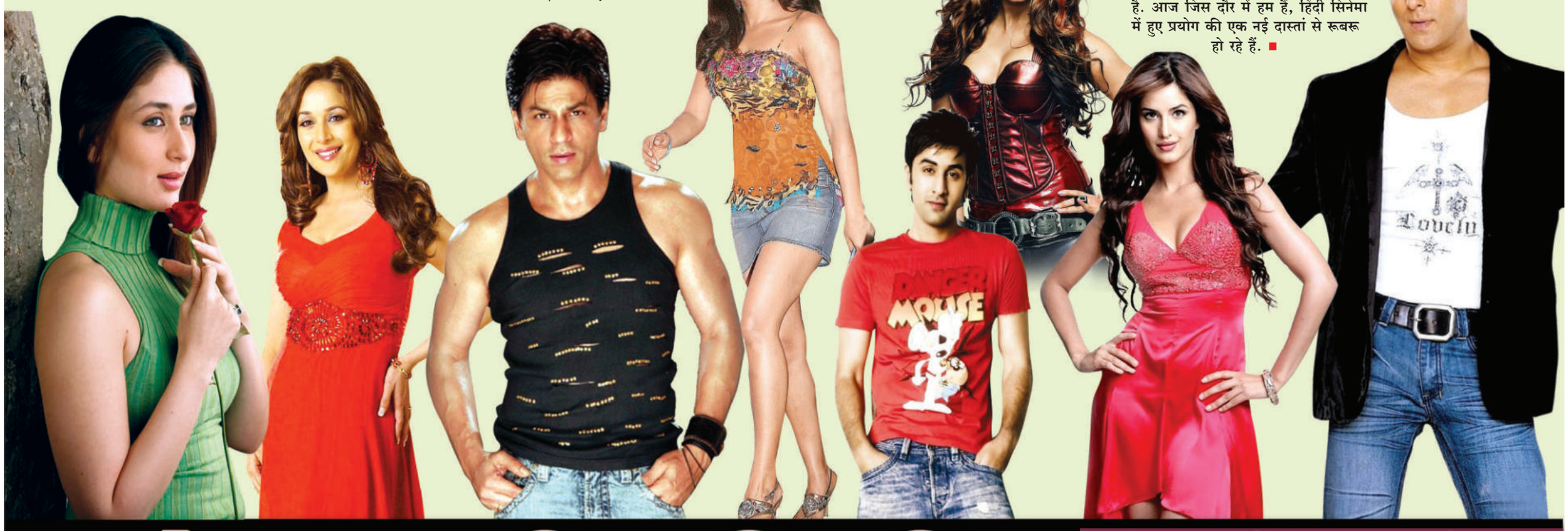

60 के दशक में बॉलीवुड की क़रीब ढाई सौ फिल्मों में अभिनय कर चुकीं मशहूर अभिनेत्री अचला सचदेव का निधन हो गया. बॉलीवुड की ख़ूबसूरत अदाकारा ज़ोहरा जबीं यानी अचला सचदेव अपनों के दिए दर्द और तन्हाई में ही खो गईं. पुराने ज़माने की ख़ूबसूरत अदाकारा अचला सचदेव पक्षाघात से जूझ रही थीं और पुणे के एक अस्पताल में भर्ती थीं. उनका इलाज चिकित्सक विनोद शाह कर रहे थे. वह छह महीने पहले अपने घर में गिर गई थीं, जिससे उनकी बाईं टांग टूट गई थी. सिर में चोट लगने से मस्तिष्क की एक नस अवरुद्ध हो गई थी, जिससे उनकी दृष्टि चली गई थी. वह चल-फिर नहीं पा रही थीं. एक सर्जरी के बाद 15 दिन तक उन्हें एक नली के ज़रिए भोजन के रूप में तरल पदार्थ दिए जा रहे थे. पर्दे पर वह जितनी बिंदास थीं, निजी ज़िंदगी में वह उतनी ही अकेली हो गई थीं. दरअसल, ग्लैमर के पीछे की दुनिया की सच्चाई बेहद दर्दनाक होती है. जिस वक़्त अचला ने आख़िरी सांस ली, उस वक़्त उनकेबच्चे भी पास नहीं थे. हालांकि वह भोसारी स्थित एक फैक्टरी के मालिक और ब्रिटिश व्यवसायी क्लीफोर्ड डगलस पीटर्स के साथ विवाह के बाद से पुणे में रह रही थीं.

उनका बेटा अपने बिजनेस के चलते यूएस में है और बेटी मुंबई में. किसी ज़माने में प्रशंसकों से घिरी रहने वाली अचला सचदेव के आख़िरी वक़्त में उनके फैमिली फ्रेंड राजीव नंदा को छोड़कर कोई नहीं था. अपनी बीमारी से अचला अकेली ही जूझ रही थीं और आख़िरकार वह यह जंग हार गईं. अभिनेत्री अचला को 1965 में बनी फिल्म वक़्त में बलराज साहनी के साथ उन पर फिल्माए गए गीत ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं के लिए जाना जाता है. अचला की अंतिम महत्वपूर्ण फिल्म थी करन जौहर की कभी ख़ुशी कभी ग़म, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था. वह कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी थीं. जनसेवा फाउंडेशन को तो उन्होंने 20 लाख रुपये और पुणे कैंप में स्थित अपना 2बीएचके अपार्टमेंट भी दान कर दिया. फिल्म इंडस्ट्री को अचला ने सात दशक से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दीं. उनकी पहली फिल्म फैशनेबल वाइफ 1938 में रिलीज हुई थी. उन्हें बंधन, मेरी सूरत तेरी आंखें, कोरा काग़ज़, हक़ीक़त, मेरा नाम जोकर, जूली और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाएगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

तुमको न भूल पाएंगे

चौथी दुनिया

दिल्ली, 14 मई-20 मई 2012 www.chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार का पर्याय बनी गोसीखुर्द परियोजना

प्रवीण महाजन feedback@chauthiduniya.com

गोसीखुर्द का नाम आते ही विदर्भ के किसानों का दर्द सामने आ जाता है. कभी गोसीखुर्द परियोजना को विदर्भ के सुखद सपने के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह विदर्भ का दर्द बन चुकी है. उसके साकार होने को लेकर जितनी उम्मीदें थीं, वे 25 वर्षों में चकनाचूर हो गईं. इस परियोजना के निर्माण को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा गया. इस प्रकल्प में कितनी गड़बड़ियां हुईं, यह इस बात से साबित होता है कि बीते 25 वर्षों में इस परियोजना से विदर्भ की 4000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई भी सुचारू रूप से न हो सकी. यदि आज की परिस्थिति में यह कहा जाए कि गोसीखुर्द परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा. यह योजना शुरू तो हुई थी किसानों की ज़िंदगी ख़ुशहाल बनाने के लिए, लेकिन उससे अधिकारी, ठेकेदार और नेता तो ख़ुशहाल होते रहे और जिन किसानों ने अपनी ज़मीन इस परियोजना के लिए दी थी, वे आज निराश हैं और स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. अब तो इस परियोजना के निर्माण कार्य और उसमें हुए कदाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग नेता भी करने लगे हैं. हालांकि इस मांग की गूंज विधानसभा और संसद में भी सुनाई दी, लेकिन सरकार उसके बाद भी इसकी जांच कराने को तैयार नहीं है.

ग़ौरतलब है कि गोसीखुर्द परियोजना को भारत सरकार ने 31 मार्च, 1983 में मंज़ूरी प्रदान की थी. उसके बाद गोसीखुर्द परियोजना वन क़ानून के कारण पांच साल तक अधर में लटकी रही. बाद में विदर्भ के लिए वरदान साबित होने वाली इस परियोजना की आधारशिला 22 अप्रैल, 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी. तब राज्य एवं केंद्र के नेता यह दावा कर रहे थे कि इस परियोजना के पूरी होने पर विदर्भ में हरित क्रांति आ जाएगी, लेकिन पच्चीस साल में विदर्भ के किसानों की उम्मीदें निराशा में बदल गईं. अब इसे विदर्भ का दुर्भाग्य कहा जाए या कुछ और कि जिन लोगों ने इस परियोजना के लिए अपनी खेतीवाड़ी की ज़मीन दी थी आज भी उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है. सरकार ने वादे तो बहुत किए थे कि पुनर्वास के दौरान उन्हें 26 मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लेकिन आज भी वे सभी लोग भटकने को मजबूर हैं. कई लोग इस परियोजना के नाम पर अपनी ज़मीन गंवा कर मज़दूरी करने को विवश हैं. आज भी इस परियोजना से पीड़ित हज़ारों लोगों को मुआवज़े और पुनर्वास के लिए धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ़ इस परियोजना के जुड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और नेताओं की संपत्ति में इज़ाफ़ा हो रहा है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, तब यह तुलतुली परियोजना गढ़चिरोली की व्यवस्थापन के तहत थी. उस समय वहां के जो कार्यकारी अभियंता थे, वे कुछ साल बाद कार्यकारी संचालक बनकर इस परियोजना के निर्माण का कारभार संभाल रहे थे. तब मज़ेदार बात यह थी कि गोसीखुर्द परियोजना का जो निर्माण कार्य उनके कार्यकारी अभियंता रहते हुआ था, वही निर्माण कार्य पुन: उनके कार्यकारी संचालक पद पर विराजमान होने के बाद भी कराया गया. अब इसका कारण तो अधिकारी ही बता सकते हैं, जो निर्माण कार्य उनके कार्यकारी अभियंता पद पर रहते कराया गया था. वही कार्य क्यों उन्होंने कार्यकारी संचालक पद संभालने के बाद कराया? इस बात से ही यह बात साबित होती है कि गोसीखुर्द परियोजना को पहले से ही भ्रष्टाचार का रोग लग गया था. यही वजह है कि परियोजना अधिकारी, ठेकेदार और नेताओं के लिए दुधारू गाय बनी हुई है.

इस राष्ट्रीय परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पुनर्वास अधिनियम 2007 के तहत 26 तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार के पुनर्वास अधिनियम 1999 के तहत भी विस्थापितों को 18 नागरी सुविधाओं को प्रावधान किया गया है, जिनमें पुनर्वास स्थल पर पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल व अन्य शैक्षणिक संसाधन, समाज भवन, पक्की सड़कें/रास्ते, बिजली आपूर्ति, श्मशान व क़ब्रिस्तान के लिए जगह, साफ़-सफाई की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारागाह एवं पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, साधन संपन्न स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, सस्ते अनाज की दुकान, सहकारी संस्था, बच्चों के लिए खेल का मैदान, सामाजिक वनीकरण और कृषि विषयक वृक्ष यानी फलदार वृक्ष, माता एवं बाल संगोपन के लिए पौष्टिक आहार योजना को तत्काल लागू करने की व्यवस्था, पूजा स्थल, पारंपारिक आदिवासी संस्थाओं के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने, पंचायत घर का निर्माण, खाद एवं बीज के रखने के लिए जगह की व्यवस्था, सार्वजनिक तालाब, सुरक्षात्मक उपाययोजना आदि करने की बात कही गई है. पुनर्वास क़ानून के प्रावधानों को देखकर तो ऐसा लगता है कि सरकार विस्थापितों के लिए पूरा शहर बसाने की व्यवस्था करने को तैयार है. गोसीखुर्द परियोजना से विस्थापितों के अनुभव में पुनर्वास क़ानून के प्रावधानों में दी गई व्यवस्था उनके लिए दूर के ढोल सुहावने लगने जैसी है. पीड़ितों का कहना है कि उनके पुनर्वास की ओर कभी किसी अभियंता, अधिकारी एवं नेताओं ने गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी. वहीं अभियंताओं का कहना है कि पांच-सात साल पहले जो पुनर्वास के लिए निर्माण कार्य किया गया, वहां विस्थापितों के न आने से झाड़-झंखाड़ उग आए हैं. वहां विस्थापितों के न आने के अनेक कारण हैं. सुविधाओं के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन चिकित्सक नियुक्त नहीं किए गए हैं. यहां स्कूल है, लेकिन शिक्षक नहीं हैं. बिजली के खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं है. मंदिर अव्यस्थित है. रास्तों के नाम पर जो निर्माण हुआ वह पहली बारिश में ही धुल गया. ऐसी स्थिति में विस्थापित वहां क्यों जाकर रहेंगे?

बात पुनर्वास तक सीमित नहीं है. शासन-प्रशासन की अनास्था की वजह से गोसीखुर्द परियोजना मज़ाक़ बनकर रह गई है. यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जिस परियोजना की लागत प्रारंभ में मात्र 650 करोड़ रुपये थी, आज बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये हो गई है. अब तक इस योजना पर 6000 करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं. इस तथ्य से ही पता चलता है कि यह परियोजना किस तरह से आर्थिक कदाचार की शिकार हुई है. इस परियोजना के निर्माण कार्य में प्रारंभ से ही धांधली होने और निर्माण कार्य निम्न स्तर का होने के आरोप लगते रहे हैं. इसकी जांच के लिए संसदीय समिति, गिरीश बापट की अध्यक्षता वाली समिति, राज्य जलसंपदा मंत्रालय के सेवानिवृत प्रधान सचिव नंद कुमार वडनेरे की एक सदस्यीय समिति, ठेकेदारों के निर्माण की तकनीकी जांच के लिए मेंढेगिरी समिति, इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन झा के नेतृत्व में भी एक समिति गो-सीखुर्द के निर्माण कार्य की जांच करके गई, जिसकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के मद्देनज़र ही केंद्र सरकार ने गोसीखुर्द के लिए दिए जाने वाले पैसे को रोक दिया है. इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने जो 350 करोड़ रुपये दिए हैं, उसे जारी करते समय यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त रक़म सिर्फ़ विस्थापितों के पुनर्वास पर ही ख़र्च की जाए. इसके अलावा केंद्र सरकार ने घटिया निर्माण कार्य पर सख्त रुख़ अपनाते हुए राज्य सरकार को कहा है कि जो निर्माण कार्य निम्न दर्जे का हुआ है, उसका पुन: निर्माण कराया जाए और पैसे ठेकेदारों से वसूल किए जाएं. इसके अलावा वडनेरे समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में निर्माण कार्यों के घटिया होने, टेंडरों के जारी करने में नियमों का उल्लंघन होने, समय से निर्माण कार्य न होने और भ्रष्टाचार होने की बात कही है. मेंढेगिरी समिति ने भी नहरों के निर्माण में ख़ामियां और निम्न दर्जे का होने का उल्लेख किया है. गोसीखुर्द के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर हमेशा ही विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा होती रही है. सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे ने भी सदन में गोसीखुर्द बांध का निर्माण कार्य घटिया होने की बात कही थी और सदन को आश्वासन भी दिया था कि ठेकेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि उनका आश्वासन मात्र आश्वासन बनकर ही रह गया. पूर्व राज्यमंत्री एवं विधायक विजय वड्टेडीवार ने इस विषय पर विधानसभा में गोसीखुर्द के अब तक हुए निर्माण कार्य की सीबीआई जांच कराने की मांग करके पूरे सदन में सनसनी फैला दी थी. वह सदन में इस मांग को तीन बार उठा चुके हैं. अब कांग्रेस के महासचिव एवं नागपुर के सांसद विलास मुत्तेमवार ने भी गोसीखुर्द निर्माण में हुए कदाचार की सीबीआई से जांच कराने और दोषी अभियंताओं, ठेकेदारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है. उसके साथ ही राज्य के नागरी आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख ने भी किसान परिषद में मुत्तेमवार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि गोसीखुर्द के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए. ख़ासतौर पर उन्होंने इस परियोजना से कमाई करने वाले राजनीतिक नेताओं पर भी कार्रवाई करने की मांग भी की. अब अनिल देशमुख ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उनका इशारा तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजीत पवार की ओर तो नहीं है. इन सब बातों से यह बात तो स्पष्ट है कि गोसीखुर्द को ठेकेदार-अधिकारी और नेताओं के गठजोड़ ने भ्रष्टाचार के दल-दल में फंसा दिया है. इस परियोजना के पूरा होने पर विदर्भ में हरित क्रांति होने, खेतों के लहलहाने और किसानों के होठों पर मुस्कान होने की सारी बातें अब 25 वर्ष पूरे होने के बाद भी कहीं पूरी होती नज़र नहीं आती हैं. सिंचाई के अभाव में किसान आज भी उदास है. विदर्भ आज भी सुसाइड जोन बना हुआ है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं. वे अपने को शासन-प्रशासन द्वारा ठगा महसूस कर रहे हैं. गोसीखुर्द को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने पर उसकी आस जगी थी कि संभवत: अब यह परियोजना दो-तीन साल में पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह उसके निर्माण में भ्रष्टाचार होने की बात सामने आ रही है, इससे निराशा और गहरा गई है. यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब विदर्भ का दर्द बन चुकी है. इस दर्द से छुटकारा कब मिलेगा, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है. ■

सरकार क्या करे

- गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को यदि समय पर पूरा करना है तो उसे भ्रष्ट अधिकारियों/अभियंताओं से मुक्त कराना होगा. इस परियोजना के निर्माण का कारभार जिन अभियंताओं की देखरेख में चल रहा है, उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति करनी होगी.
- इस परियोजना के निर्माण कार्य का स्तर तकनीकी रूप से उच्च श्रेणी का बनाए रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल विभाग को और सक्षम बनाना होगा.
- निर्माण कार्य के लिए जारी पुरानी निविदाओं को रद्द कर नए सिरे से जारी किया जाए.
- पुराने अभियंताओं की जगह नए नियुक्त किए गए अभियंताओं को पूर्ण संरक्षण देना होगा, ताकि वे बिना किसी भय के निर्णय ले सकें और निर्माण कार्य समय से पूरा कर सकें. उसके लिए ज़रूरी है कि उनके कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो.
- निर्माण कार्य का उच्च स्तर बनाए रखते हुए, जो अभियंता ईमानदारी से कार्य करें उन्हें पारितोषिक और इनसेंटिव दिया जाए, ताकि उन्हें ठेकेदारों से कमीशन पाने की लालच न रहे.
- निर्माण कार्य के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों व उसके नक्शे के अनुसार कार्य का प्रतिदिन रिपोर्ट में ज़िक्र किया जाना चाहिए. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल के कार्यालय में विशेष गोसीखुर्द सेल बनाकर हर दिन की रिपोर्ट पर कार्य की निगरानी और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए.
- उपविभागीय अभियंता स्तर पर परियोजना के हर दिन होने वाले कार्य का उल्लेख मेजरमेंट बुक में किया जाना चाहिए.
- शासन के नियमों के अनुसार हर अभियंता के तहत होने वाले कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट निर्माण स्थल पर बनाकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए.
- परियोजनाओं का अधिक से अधिक कार्य शासन के तकनीकी विभाग द्वारा किया जाना चाहिए.
- इस परियोजना को भ्रष्टाचार से मुक्त कर निर्धारित समय पर पूरा कराना हो तो सैन्य अभियंताओं की सेवा लेनी चाहिए.
- जब तक इस परियोजना का निर्माण कार्य चालू रहे, तब तक कार्यकारी अभियंता को हर दूसरे दिन, अधीक्षक अभियंता को हर दो दिन के बाद और मुख्य अभियंता को हर सप्ताह कार्यस्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चाहिए.

चौथी दुनिया

सरकार इस बात से उत्साहित है कि उसकी नई वस्त्रोद्योग नीति को निज़ी कपड़ा मिलों का अच्छा समर्थन मिल रहा है.

दरअसल नक्सली हिंसा का यह नया दौर तब शुरू हुआ जब से केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गढ़चिरोली व चंद्रपुर ज़िले का दौरा करके गए हैं.

चौथी दुनिया

महाराष्ट्र हलचल

महाराष्ट्र दिवस पर नागपुर पुलिस परेड निरीक्षण करते ज़िला पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे.

अमरावती ज़िले के वडार समाज के लोग पत्थर फोड़कर सरकारी नीतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए.

सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपुर में आयोजित ग्रीष्म क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते पूर्व मंत्री शांताराम पोटदुखे व मंचासीन अन्य अतिथिगण.

उमरखेड़ तहसील के प्रकल्पपीड़ित पुनर्वास के लिए धरना-प्रदर्शन करते हुए और उन्हें संबोधित करते विधायक विजय खड़से.

वर्धा ज़िले की आर्वी तहसील में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में विवाह बद्ध हुए दूल्हा-दुल्हन व उनके रिश्तेदार.

बस्ती से देसी दारू की दुकान हटाने के लिए आमरण अनशन करते हुए लाखांदुर तंटा मुक्ति समिति के पदाधिकारी.

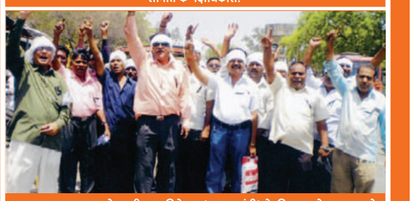

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक (हड़ताल बंदी) के ख़िलाफ़ रोष प्रकट करते अकोला एसटी स्टैंड के कर्मचारी.

मज़दूर दिवस पर बुलढाणा में एटक, सीटू व अन्य यूनियनों द्वारा निकाली गई मज़दूर रैली.

मंगरूलपीर स्थित नाथ विद्यालय के मैदान पर वाशिम ज़िला हांकी एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते अतिथिगण.

क़र्ज़ लेकर बिलों का भुगतान

अमरावती महानगर पालिका भी अजीबो-ग़रीब है. वह पहले से ही क़र्ज़ में डूबी हुई है और अब उसने विविध निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान के लिए करोड़ों का क़र्ज़ और उठाने का फ़ैसला किया है. इतना ही नहीं क़र्ज़ लेने से पहले अप्रैल माह में ठेकेदारों को दो करोड़ का भुगतान किए जाने पर मनपा कर्मचारियों को वेतन से वंचित रहना पड़ा और उन्हें वेतन के लिए इंतज़ार करने को कहा गया. इसका तो यही मतलब हुआ कि अमरावती मनपा पर क़र्ज़ का बोझ और बढ़ेगा.

गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों से अमरावती मनपा का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं किया गया था. इससे आंदोलित ठेकेदारों ने पिछले माह मनपा के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर अपने 20 करोड़ रुपये के बिलों के भुगतान की मांग की थी. साथ ही सभी ठेकेदारों ने मनपा के सभी निर्माण कार्यों का बहिष्कार किया था. इससे मनपा के विकास कार्य ठप पड़ गए थे. इसका तोड़ निकालने के लिए मनपा आयुक्त नवीन सोना के साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने बैठक की. इस बैठक में मनपा आयुक्त के साथ उपायुक्त रामसिद्ध भट्टी, पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस के शहराध्यक्ष वसंतराव साऊरकर, भाजपा के शहराध्यक्ष डॉ. प्रदीप शिंगोरे, संजय अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों उपस्थित थे. इस बैठक में ठेकेदारों के बकाया बिलों के भुगतान को लेकर गहन चर्चा की गई. महानगर पालिका ठेकेदार संगठन के अध्यक्ष अरविंद गुल्हाने ने बैठक में अपना पक्ष रखा. उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि ठेके में मिले कार्यों को पूरा करने के बाद भी पिछले दो साल से बिल भुगतान होने का इंतज़ार हम कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब तक पिछले बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक हमारा किसी कार्य को करना संभव नहीं है.

मनपा आयुक्त नवीन सोना ने राजनीतिक दलों को बताया कि 16 करोड़ रुपये के बिलों को एक साथ भुगतान करना संभव नहीं है. यदि ऐसा किया गया तो मनपा के अन्य कार्यों पर इसका असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बकाया बिलों के भुगतान के लिए मनपा ऋण ले सकती है. उसके लिए मनपा सदस्यों की विशेष आमसभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव पारित कराना अनिवार्य होगा. प्रस्ताव पारित हुए बिना ऋण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है. इस पर पूर्व महापौर विलास इंगोले ने विशेष सभा बुलाकर प्रस्ताव पास होने की आशा व्यक्त की. मनपा आयुक्त का यह भी कहना था कि प्रस्ताव पारित होने के बाद ऋण को मंज़ूरी मिलने में दो से तीन माह लग जाएंगे. क़र्ज़ मिलते ही सभी ठेकेदारों के बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा. क़र्ज़ में मिली रक़म का वितरण सही तरीके से किया जाएगा. यह आश्वासन मनपा आयुक्त ने मनपा ठेकेदार संगठन के अध्यक्ष अरविंद गुल्हाने को दिया. मनपा आयुक्त के इस आश्वासन के बाद ठेकेदारों ने अपना आंदोलन ने तो वापस ले लिया, लेकिन जनता की चिंताएं बढ़ गई हैं. पहले ही मनपा प्रशासन पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगता रहा है. इसके साथ ही इस पर करोड़ों का भारी क़र्ज़ भी है. इस क़र्ज़ को पाटने की बजाय मनपा प्रशासन और क़र्ज़ लेने की बात कर रहा है. वहीं मनपा प्रशासन द्वारा ठेकेदारों को दो करोड़ का भुगतान किए जाने से उसके कर्मचारी भी नाखुश हैं, क्योंकि अप्रैल माह का वेतन उन्हें अब तक नहीं मिला है. कर्मचारियों का कहना है कि बिलों का भुगतान किए जाने पर भी उसमें से कमीशन अधिकारियों को मिलता है. हमें तो अपने पगार का ही सहारा रहता है. इसका तो यही मतलब हुआ कि क़र्ज़ लेकर बिलों का भुगतान किए जाने में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का हित भी छुपा हुआ है.

यह अजीब बात है कि मनपा प्रशासन आज की स्थिति में अपने कर्मचारियों के वेतन का बोझ भी उठाने में समर्थ नहीं है. वहीं ठेकेदारों का कहना है कि हमने मनपा आयुक्त की बातों पर विश्वास करके आंदोलन भले वापस ले लिया है, लेकिन जब तक हमारे पुराने बिलों का भुगतान नहीं मिल जाता है, तब तक हम कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं करेंगे.

दूसरी ओर नागरिकों का कहना है कि मनपा प्रशासन ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करे, उसमें कोई बुराई नहीं है. हालांकि समस्या यह है कि वह जो क़र्ज़ ले रहा है उसका बोझ अंतत: अमरावती की जनता पर ही तो पड़ेगा. जिसके एवज में नए टैक्स लगाए जाएंगे. तरह-तरह के शुल्क वसूल किए जाएंगे. इस क़र्ज़ का असर कुछ दिनों में दिखने लगेगा. यदि मनपा प्रशासन पुराने बकाया टैक्सों की वसूली सही तरीके से करे तो, इतनी गंभीर समस्या नहीं होगी. इसके अलावा मनपा में व्याप्त भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण ही क़र्ज़ में डूबे होने के बाद भी उसे क़र्ज़ लेना पड़ रहा है. समझ में यह नहीं आता है कि मनपा के खजाने में आने वाली रक़म का उपयोग वह किस तरह करता है. यह अजीब बात है कि मनपा प्रशासन आज की स्थिति में अपने कर्मचारियों के वेतन का बोझ भी उठाने में समर्थ नहीं है. वहीं ठेकेदारों का कहना है कि हमने मनपा आयुक्त की बातों पर विश्वास करके आंदोलन भले वापस ले लिया है, लेकिन जब तक हमारे पुराने बिलों का भुगतान नहीं मिल जाता है, तब तक हम कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं करेंगे. यह हमारा अंतिम फ़ैसला है. बात जो भी हो, लेकिन मनपा के साथ ही अमरावती की जनता पर भी क़र्ज़ का बोझ बढ़ता जा रहा है और मनपा की खस्ता हालत के लिए मनपा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार मुख्य वजह है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नई वस्त्रोद्योग नीति में भी भेदभाव

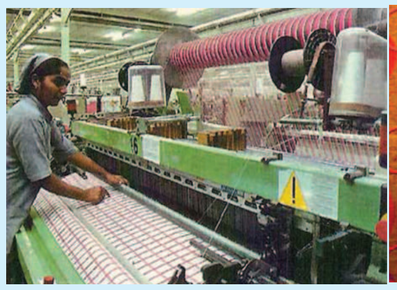

राज्य की कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी सरकार को भले गुजरात की प्रशंसा करने से एलर्जी हो, लेकिन अब उसने अपनी नई वस्त्रोद्योग नीति का प्रचार-प्रसार गुजरात में जाकर करने का फ़ैसला किया है. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि राज्य में बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है और कई बड़ी कंपनियों ने राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करने की तैयारी दर्शाई है. इस बात से राज्य सरकार उत्साहित है और वह गुजरात में जाकर वहां कार्यरत कपड़ा उत्पादक कंपनियों को रिझाने का प्रयास करेगी, ताकि वे महाराष्ट्र में आकर निवेश कर सकें. इसलिए सरकार ने अपनी नई वस्त्रोद्योग नीति की मार्केटिंग राज्य के बाहर करने के लिए गंभीरता से उपाय कर रही है.

वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम ख़ान इस विषय में सरकार के मक़सद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राज्य में उत्पादित होने वाली 90 लाख कपास की गांठ का राज्य में ही प्रोसेसिंग कर और उसमें 40 हज़ार करोड़ का निवेश कर 11 लाख रोजगार के अवसर का निर्माण करने का लक्ष्य सरकार का है. हमारी नई वस्त्रोद्योग नीति को पूरे देश में अच्छा समर्थन मिल रहा है. नई वस्त्रोद्योग नीति का ही परिणाम है कि राज्य के बाहर की पांच निजी कंपनियां कपास उत्पादक क्षेत्रों में 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने को तैयार हैं. इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पड़ोसी राज्य गुजरात में भी अपनी नई वस्त्रोद्योग नीति का प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने नई वस्त्रोद्योग नीति में निजी कंपनियों की परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रतिशत निवेश अनुदान और उसी तरह 12 प्रतिशत ब्याज में छूट की सुविधा देने का खुलासा किया है. इसका परिणाम यह है कि नई वस्त्रोद्योग नीति से प्रभावित होकर विदर्भ-मराठवाड़ा में देश की बड़ी कंपनियां कपास प्रोसेसिंग परियोजनाएं शुरू करने को तैयार हो गई हैं. इन कंपनियों में ओसवाल, एटको, गिन्नी इंटरनेशनल, प्रवीण शेल्ली और येगेन जैसी कंपनियां शामिल हैं. इन सभी कंपनियों ने सरकार को पत्र लिख कर परियोजना शुरू करने की अनुमति मांगी है. उन्होंने संभावना जताई कि साल भर में उक्त कंपनियों द्वारा अपनी परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया जाएगा.

सरकार इस बात से उत्साहित है कि उसकी नई वस्त्रोद्योग नीति को निजी कपड़ा मिलों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. जिन कंपनियों ने सरकार को पत्र लिख कर विदर्भ-मराठवाड़ा में अपनी कपास प्रोसेसिंग परियोजना शुरू करने की इच्छा जताई है, उनके आवेदनों को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है. इसकी प्रक्रिया पूरी होने पर परियोजना शुरू होने की बात कही जा रही है. इसलिए सरकार गुजरात जाकर वहां के उद्योगपतियों को भी महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करने का प्रयास करेगी. इसके लिए सरकार अपनी वस्त्रोद्योग नीति की मार्केटिंग करने की नीति-रणनीति को भी अंतिम रूप देने में जुटी है. यह इसलिए किया जा रहा है कि गुजरात का कपड़े का बाज़ार विश्वविख्यात है और वहां कई उद्योगपति कपड़ा उद्योग में निवेश कर सकते है. इसलिए सरकार की उम्मीदें जाग उठी हैं. यदि विदर्भ में बड़ी कंपनियां निवेश करती हैं तो यहां के कपास उत्पादकों के लिए सरकार की नई वस्त्रोद्योग नीति वरदान साबित हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद का सही और समुचित क़ीमत मिले.

ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 14 टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने को मंज़ूरी दे दी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का वस्त्रोद्योग मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को कपास उत्पादक इलाक़ों में लाने के लिए ज़ोर दे रही है. हालांकि यहां भी राजनीतिक गफलत होने की बात सामने आयी है. अधिकांश टेक्सटाइल्स पार्कों को पश्चिम महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना है. कपास उत्पादक क्षेत्रों के लिए मात्र 4 ही पार्कों को मंज़ूरी दी गई. जिन ज़िलों टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित होने हैं, उनमें धुले, लातूर, हिंगोली, अमरावती के अलावा कोल्हापुर ज़िले के उचलकरंजी में तीन और बारामती, भिवंडी, इस्लामपुर, पुणे, बीड, सोलापुर शामिल है. इससे तस्वीर साफ़ हो जाती है कि टेक्सटाइल्स पार्क के मामले में भी पलड़ा पश्चिम महाराष्ट्र का ही भारी है. इन टेक्सटाइल्स पार्कों को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक को 40 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से 9 करोड़ अनुदान दिया जाएगा. इससे साफ हो जाता है कि केंद्र के स्तर पर भी विदर्भ के प्रति उपेक्षा का भाव है.

बहरहाल सरकार अपनी वस्त्रोद्योग नीति से उत्साहित है. वैसे यहां सवाल यह भी है कि जो कंपनियां अपनी परियोजना यहां शुरू करना चाहती हैं, उन्हें सभी तरह की क़ानूनी सुविधा के साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए ज़रूरी संसाधन पानी, बिजली, मैनपावर उपलब्ध कराया जाए. इसमें किसी तरह की राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए. तभी महाराष्ट्र की तस्वीर को बदला जा सकेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राज्य में नक्सली तांडव जारी

राज्य में नक्सली प्रभावित ज़िले गढ़चिरोली में नक्सलियों की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. जवानों पर हमले हो रहे है, स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के जवानों पर नक्सली हमला होना समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामान्य निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का क्या कारण है, यह बात आदिवासी जनता की समझ में भी नहीं आ रहा है. केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री जयराम रमेश की यात्रा के बाद ही नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट करके 12 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद से ही नक्सली हिंसा में तेज़ी आ गई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है. नक्सली हिंसा से गढ़चिरोली और चंद्रपुर ज़िले में दहशत का माहौल है, लेकिन इस दरम्यान राज्य का गृह मंत्रालय पूरी तरह सुस्त नज़र आया. नक्सली हिंसा से निपटने की घोषणाएं हर बार होती हैं, लेकिन इन घोषणाओं पर अमल अब तक होता नज़र नहीं आ रहा है.

राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उससे नक्सलग्रस्त क्षेत्रों के ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच व सदस्यों में नक्सलियों का भय है. नक्सलियों के अल्टीमेटम बाद क्या वे अपने पदों व सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दें, वे असमंजस में पड़ गए हैं. भामरागढ़ ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. बाकी भी नक्सलियों के दबाव में देने पर विचार कर रहे हैं. नक्सलियों की यह कार्रवाई सीधे-सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात है. आदिवासी जनता को इस समय सरकार व पुलिस प्रशासन के समर्थन की सख़्त ज़रूरत है. अप्रैल माह में जिन राजनीति कार्यकर्ताओं व नागरिकों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया है, उनमें जोगनगुडा के बापू ऐंका व अर्जुन तलांडी, तंटामुक्ति समिति के सदस्य (2 अप्रैल), एटापल्ली के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व ज़िला परिषद सदस्य केवल सावकार अतकमवार (13 अप्रैल), गट्टा में पुलिस जवान रामभुवन पांडे (19 अप्रैल), आरेवाड़ा के पवन भलावी, नागविदर्भ आंदोलन समिति (20 अप्रैल), गर्देवाड़ा के सरपंच चमरू जोई (23 अप्रैल), वांगेतुरी के उपसरपंच रैनू कौशिक सहित तीन लोगों की हत्या (24 अप्रैल) शामिल है. विशेष बात यह है कि नक्सल विरोधी अभियान का असर यहां कहीं नज़र नहीं आया. यहां जवान तो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं, लेकिन सरकार सुस्त नज़र आ रही है. सत्ताधीशों का बोल वचन पर ही अधिक विश्वास है, जो बोला इस पर समय से कार्रवाई करने में बहुत पीछे हैं.

दरअसल नक्सली हिंसा का यह नया दौर तब से शुरू हुआ जब से केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गढ़चिरोली व चंद्रपुर ज़िले का दौरा करके गए हैं. उन्होंने अपने दौरे के दौरान ग्राम विकास करके नक्सलियों को चुनौती देने का आह्वान किया था. पता नहीं उनकी अपील राज्य सरकार ने कितना स्वीकार किया, लेकिन नक्सलियों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया. उन्होंने आदिवासियों के बीच अपनी दहशत कायम रखने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों में तेज़ी लाई. वैसे भी नक्सलियों ने नक्सल प्रभावित इलाक़ों में विकास कार्यों के पहिये को घूमने के पहले ही इस पर ब्रेक लगाने की घोषणा की थी. गढ़चिरोली की भामरागढ़ तहसील में राकांपा नेता की हत्या के बाद ही नक्सलियों ने ज़िला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत सदस्यों व पदाधिकारियों को सरकारी विकास कार्यों को रोकने और अपनी सदस्यता व पदों से इस्तीफ़ा देने का फरमान जारी किया था. इसके लिए सभी को 26 अप्रैल की तारीख़ दी थी. इसके बावजूद जब स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है तो कुछ लोगों का अपहरण तक कर लिया गया. उसके बाद तो बौखलाए नक्सलियों ने सरपंच-उपसरपंच, ज़िला परिषद सदस्यों को मौत के घाट उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि आदिवासी समाज में उनकी दहशत क़ायम रहे और उनका वर्चस्व क़ायम रहे. उन्हें इस बात का भय है कि यदि उनके प्रभावित इलाक़ों में विकास तेज़ गति से हुआ तो उनका आदिवासी समाज पर क़ायम वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा. ऐसा हुआ तो उन्हें गढ़चिरोली और चंद्रपुर सहित गोंदिया-भंडारा ज़िले के भी क्षेत्र में उनका अस्तित्व क़ायम नहीं रह सकेगा. वे हरगिज़ नहीं चाहते कि उनका वर्चस्व राज्य के उक्त ज़िलों में ख़त्म हो और उनका रेड कॉरिडोर खंडित हो. यदि रेड कॉरिडोर खंडित होता है तो उन्हें आंध्र प्रदेश में आने-जाने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा राज्य के अन्य ज़िलों में पैर पसारने की उनकी योजना प्रभावित होगी. इन सारे तथ्यों को मद्देनज़र ही नक्सलियों ने राज्य में अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को तेज़ कर दिया है. अब यह राज्य व केंद्र सरकार का काम है कि वह गढ़चिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा के आदिवासी समाज का विश्वास हासिल करे और उनके साथ मिलकर नक्सलियों के ख़िलाफ़ ठोस रणनीति बनाये. आज जो स्थिति गढ़चिरोली ज़िले की है, उसे देखते हुए यह बात साफ़ हो गई है कि नक्सलियों के प्रति आदिवासियों में गुस्सा व्याप्त है. वह सरकार की हर कार्रवाई के साथ कदमताल मिलाने को तैयार हैं. यह इस बात से पता चलती है कि जब एटापल्ली में जिला परिषद सदस्य केवल सावकार अतकमवार का अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी नागपुर में बी.कॉम. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत इकलौती बेटी पायल ने उन्हें अग्नि देने के बाद जो सवाल खड़ा किया वह सरकार की आंख खोलने के लिए काफी है. पायल ने कहा कि नक्सली अत्याचार के बाद कुछ क्षण के लिए आंसू बहाना बंद करो. कब तक जनता नक्सलियों की हिंसा को बर्दाश्त करती रहेगी? उसने कहा कि उसके पहले प्यारेलाल अग्रवाल, बहादुरशाह आलम, मालू कोपा बोगामी जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ठेकेदार संजय खेंडेकर, बीआरओ के अभियंता गणेश सहित ज़िले के भिन्न-भिन्न स्थानों में निर्दोष लोगों की नक्सलियों ने हत्या की. इन हत्याओं के बाद कुछ क्षण आंसू बहाए और सब शांत हो गया. अब हत्या होने के बाद आंसू बहाना बंद हो और नक्सली हिंसा के ख़िलाफ़ निर्णायक भूमिका अपनाओ. उसने राजनेताओं को भी खरी-खरी बातें सुनाई. पायल ने जो भावना व्यक्त की है वह यहां हर आदिवासी लड़कियों, महिलाओं के मन में है, क्योंकि यहां नक्सलियों ने किसी के भाई, किसी के पिता, किसी के पति व पुत्र को अपनी हिंसा का शिकार बनाया है. मगर इतना होने के बाद भी सरकार आदिवासियों का विश्वास अर्जित करने के कोई प्रयास नहीं कर रही है. इसलिए सरकार का पूरा अभियान कमज़ोर पड़ जाता है, जबकि गढ़चिरोली ज़िले के पालकमंत्री खुद राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल हैं. इसके बावजूद गढ़चिरोली जैसे ज़िले में विकास कार्यों में सरकार कोई तेज़ी नहीं ला सकी है. गृहमंत्री पाटिल इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या वे पल्ला झाड़कर अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं. गृहमंत्री व गढ़चिरोली का पालकमंत्री होने के नाते उन्हें बोल वचन के अलावा कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, जो अब तक वे नहीं कर सके हैं. इस बीच यहां तक चर्चा होने लगी कि छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के अपहृत कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन को गढ़चिरोली में लाकर किसी इलाक़े में रखा गया ताकि यदि वहां की सरकार नक्सलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करे भी तो उसका पता न लगाया जा सके.

राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उससे नक्सलग्रस्त क्षेत्रों के ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच व सदस्यों में नक्सलियों का भय है. क्या वे नक्सलियों के अल्टीमेटम के बाद अपने पदों व सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दें, वे असमंजस में पड़ गए हैं.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

शर्म किसे आती है ?

महाराष्ट्र के राजनेता बेलगाम का मुद्दा उछाल कर जब तब लाल-पीले होते रहते हैं. उन्हें महाराष्ट्र की अस्मिता की याद सताने लगती है. शिवसेना को कर्नाटक सरकार सांप तक नज़र आती है और वह उसे मराठियों पर अत्याचार करने का दोषी क़रार देते हैं, लेकिन जब राज्य के सताधीश ही अपनी जनता का पालन-पोषण न कर सकें, मूलभूत सुविधाएं मुहैया न करा सकें तो किसे दोषी ठहराया जाय. यह कितनी अजीब बात है कि जिस कर्नाटक राज्य पर मराठियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर हमारे नेता बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा में अनेक बार पास कर चुके हैं, वहां शामिल होने को इस राज्य के 44 गांव तैयारी कर रहे हैं. सांगली ज़िले के जिन 44 गांवों के लोग कर्नाटक पलायन कर जाने की बात सोच रहे हैं. क्या उनके दर्द को समझने की कोशिश कभी हमारे राज्य के मंत्रियों-नेताओं ने की है? यह सब हो क्या रहा है? ऐसा क्या हो गया कि हमारे 44 गांवों के मन में कर्नाटक जाने का विचार आया? इस सवाल का जवाब यदि हमारे नेता तलाशने का वक्त निकाल पाते तो शायद यह नौबत ही नहीं आती, लेकिन कहते हैं ना कि करारा तमाचा पड़े बिना सत्ताधीशों की नींद नहीं खुलती है. सांगली ज़िले में भयानक सूखा पड़ा है. जनता को लगता था कि सरकार समय पर जागेगी और उनकी सुध लेकर राहत के उपाय करेगी, लेकिन सरकार तो सत्ता की खुमारी में मस्त है. नेता राजनीति करने में व्यस्त हैं. उनके पास समय ही नहीं कि वह इन सीमावर्ती इलाक़ों की सुध ले. वहां की दुर्दशा का इसी बात से पता चलता है कि उक्त गांव के सरपंचों ने बैठक कर सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि यदि राज्य सरकार उन्हें पानी नहीं मुहैया करा सकती है तो वे कर्नाटक में शामिल होंगे. गांववालों का कहना है कि महाराष्ट्र के गठन के 52 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो सका है तो इस राज्य में रहने का क्या फ़ायदा? इससे यह पता चलता है कि गांववासियों का महाराष्ट्र सरकार से विश्वास उठ गया है. सांगली ज़िले के गांवों की यह स्थिति इस सरकार व इन नेताओं के गाल पर क़रारा तमाचा है, जो बेलगाम के मामले पर कर्नाटक सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन यहां शर्म किसे आती है? शर्म आती तो यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती. गांववासियों की समस्याओं को सरकार समय से पहले सुलझा लेती. यहां तो हालत यह है कि केंद्र सरकार के युवराज राज्य के दौरे पर आते है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा उन्हें अपने ज़िले के सूखाग्रस्त गांवो का दौरा करा कर संतुष्ट हो जाते हैं. उन्हें राज्य के अन्य क्षेत्रों में सूखा दिखाई ही नहीं देता है. दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार समस्या से निपटने का उपाय पहले से नहीं करती है. जब अप्रैल-मई माह में पानी के लिए चहुंओर हाहाकार मच जाता है तो सरकार को कुआं खोदने की याद आती है. अब सुना है कि युवराज के राज्य दौरे के बाद और अप्रैल माह गुजर जाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए 1073 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है. यानी यह पैकेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोग प्यासे ही रहेंगे. 44 गांव के लोगों ने महाराष्ट्र से पलायन करने का जो फ़ैसला लिया है वह खुशी-खुशी तो लिया नहीं है. उनका दर्द यही है कि उनकी बार-बार मांगों, आवेदन-निवेदन देने के बाद भी सरकार ने उनकी ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते मज़बूरन उन्हें यह फ़ैसला लेना पड़ा. सांगली के व्यापारी तो पहले ही कर्नाटक के लिए पलायन कर गए हैं. अब हमारे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री क्या यह बताने का कष्ट करेंगे की इस शर्मनाक स्थिति में सरकार क्या सोचती है?

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बर

मुंबई आईटीआई को सुनहरा अवसर मिला

मुंबई आईटीआई यानि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी को अमेरिकी शहर न्यूयार्क की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया है. यह आमंत्रण दिया है सेंटर फॉर अर्बन साइंस एंड प्रोगेस (कास्प) नामक संस्था ने. इस संस्था की स्थापना पांच देशों के विश्वविद्यालयों ने मिलकर ब्रुकलीन में किया है. उनमें न्यूयार्क, टोरंटो सहित पांच विदेशी विश्वविद्यालय शामिल है और उक्त संस्था के तहत अर्बन साइंस या अभियांत्रिकी विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्नातकोत्तर पदवी की प्रदान की जाएगी. उसमें शामिल होने के लिए मुंबई आईटीआई के तीन प्राध्यापकों को आमंत्रित किया है. संभावना जताई जा रही है कि मुंबई आईटीआई को मिले इस सुनहरे अवसर से कास्प के तहत मुंबई शहर की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भविष्य में अलग से केंद्र स्थापित किया जा सकेगा. इन संभावनाओं का जायज़ा मुंबई आईटीआई के अधिकारी ले रहे हैं. मुंबई आईटीआई के अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर ने अपनी इस कल्पना को आईटीआई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के समक्ष रखा है. उन्होंने आशा जताई है कि कास्प के अनुभवों का फ़ायदा मुंबई शहर की समस्याओं के लिए स्थापित होने वाले केंद्र को भी मिलेगा. यह भी संभावना जताई की मुंबई शहर की समस्या का अध्ययन केंद्र साल भर में अस्तित्व में आ जाएगा.

कुत्तों के लिए शौचालय

मुंबई महानगर पालिका ने मुंबईकरों के पालतू कुत्तों के लिए शौचालय बनाने का फ़ैसला किया है. इससे यह संभावना जताई जा रही है कि कुत्तों द्वारा की जाने वाली गंदगी से मुंबईकरों को छुटकारा मिल जाएगा. ग़ौरतलब है कि मुंबई मनपा ने कुछ वर्षों पूर्व मरीन लाइंस में पालतू कुत्तों को घुमाये जाने पर रोक लगाया था. वहां पालतू कुत्तों के गंदगी करने पर उनके मालिकों को साफ़-सफाई करनी या करानी पड़ती थी, लेकिन कुछ समय बाद पुन: शहर के रास्तों पर कुत्तों द्वारा गंदगी करने के मामले बढ़ गए, क्योंकि मुंबई मनपा प्रशासन अपने आदेश को बरकरार नहीं रख सका. लिहाज़ा श्वानों का मुक्त विचरण रास्तों पर होने लगा है, लेकिन अब मनपा प्रशासन ने कुत्तों से होने वाली गंदगी से मुंबईकरों को मुक्त कराने के लिए रास्तों में श्वान शौचालयों की व्यवस्था करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. दरअसल कांग्रेस के नगरसेवक आसिफ झकेरिया ने मनपा बजट पर चर्चा के दौरान मुंबई के रास्तों पर पालतू कुत्तों से होने वाली गंदगी पर चिंता ज़ाहिर करते हुए रास्तों में डॉग बॉक्स लगाने का सुझाव दिया. अब मनपा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का भी मानना है कि रास्तों पर पालतू कुत्तों को लेकर घुमने वाले और उनसे होने वाली गंदगी को किसी भी क़ानून-नियम के दम पर रोकना असंभव है. उसके लिए डॉग बॉक्स की संकल्पना अच्छी है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. ख़ास बात यह है कि यह व्यवस्था विदेशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में ही देखी गई है. अब मुंबई मनपा भी इसका अनुसरण करेगी.

अहेरी डिपो कमाई में सबसे आगे

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल (एस.टी.) के जहां घाटे में संचालित होने की बात अकसर कही जाती है. उसके चलते बीच-बीच में इसके निजीकरण करने की सुगबुगाहट भी होती है. वहीं एस.टी. महामंडल का ही अहेरी डिपो ने राज्य में कमाई के मामले में सबसे आगे निकल गया है. वर्ष 2011-12 आर्थिक साल में अहेरी डिपो ने कुल 2 करोड़ 38 लाख 48 हज़ार रुपये का मुनाफ़ा कमाकर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. ख़ास बात यह है कि अहेरी डिपो गढ़चिरोली ज़िले के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है. उसके बाद भी इसका एस.टी. महामंडल के अन्य डिपों की बजाय सबसे अधिक मुनाफ़ा कमा कर देना अचंभित करता है. अहेरी एस.टी. डिपो के व्यवस्थापक अशोक वाडीभस्मे का कहना है कि ऐसा अहेरी से साल भर शिर्डी, लातूर, हैदराबाद, गोंदिया, अमरावती, यवतमाल, नागपुर के साथ ही कोर्ला, पातागुडम, कोपेला, झिंगानूर व अन्य जगहों के लिए बसों का संचालन करके यह सफलता मिली है. परंतु अन्य डिपो से भी बसों का संचालन हर क्षेत्र के लिए किया जाता है, उसके बाद भी उनका घाटे में रहना कई सवाल खड़ा करता है. कहीं न कहीं एस.टी. के अन्य डिपो के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के कीटाणु के प्रवेश कर जाने की आशंका को जन्म देता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि नक्सलियों के बंद के दरम्यान अहेरी डिपो से एस.टी. बसों का संचालन बंद कर दिया जाता है.

महिलाओं की भागीदारी का सवाल

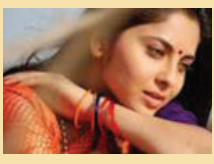

राज्य के महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ने बड़ी मेहनत से पतियों की संपत्ति में महिलाओं को आधा हिस्सा दिलाने के लिए विधेयक बनाया था, लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर ही इस विधेयक को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है. कई मंत्रियों ने इस विधेयक का विरोध किया है. ख़ासकर अल्पसंख्यक मंत्री नसीम ख़ान ने इस विधेयक पर आपत्तियां उठाई थीं. लिहाज़ा स्थानीय स्तर पर महिलाओं को 50 फ़ीसदी हिस्सेदारी देने वाली राज्य की कांग्रेस-राकांपा आघाड़ी सरकार को उक्त विधेयक को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा. इससे पता चलता है कि सरकार में पुरूष प्रधान मानसिकता अभी भी हावी है. उसके बाद भी महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ने हार नहीं मानी है. वह बलात्कार पीड़ित युवतियों व महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए विधेयक तैयार करने में जुटा है. इसके तहत बलात्कार पीड़ित को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, मुफ्त काउंसिलिंग, व्यवसाय प्रशिक्षण, चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इसके अलावा पीड़िता को 2 लाख रुपये और विशेष मामले में 3 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी. इसके लिए जरूरी यह होगा कि पीड़िता द्वारा बलात्कार की घटना के बाद सरकारी आर्थिक सहायता व अन्य मदद प्राप्त करने के लिए 60 दिन के अंदर आवेदन करना होगा.

नक़लची छात्रा की वीरूगिरी

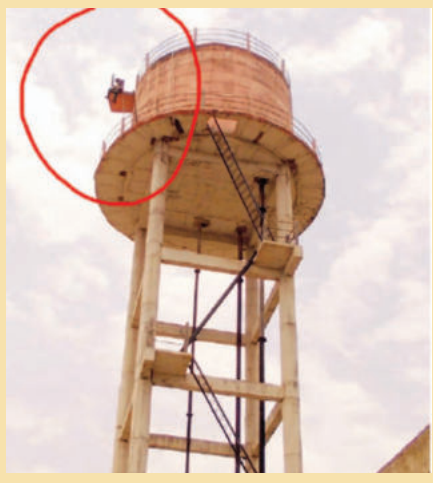

अन्याय के शिकार कई लोगों को वीरूगिरी करते देखा गया है, लेकिन किसी छात्रा द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर वीरूगिरी करने की कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. मगर पुसद में एक छात्रा ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ करते हुए यह कमाल कर दिखाया. पुसद स्थित विद्यालय में कृषि स्नातक की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चल रही थी. इस परीक्षा केंद्र में आर्वी तहसील के ग्राम अंबोडा के कृषितंत्र विद्यालय की छात्रा प्रांजलि देवानंद गजघाटे भी पेपर दे रही थी. उसी दौरान नकल विरोधी दल वहां जांच करने पहुंचा और दल के प्रा. शेख साज़िद (अकोला) ने प्रांजलि को रंगेहाथ नकल करते पकड़ा तो, उसने विवाद करना शुरू कर दिया. उसके बाद परीक्षा हाल से निकल कर परीक्षा केंद्र की छत पर चढ़ गई और धमकाने लगी. हालांकि इससे भी बात न बनते देख वह परीक्षा केंद्र के नज़दीक स्थित डेढ़ सौ फुट ऊंची पानी की टंकी में चढ़ गई और कार्रवाई करने या परीक्षा न देने देने पर कूद कर जान देने की धमकी देने लगी. उसकी वीरूगिरी को देखने के लिए रास्ते में भीड़ जमा हो गई. सभी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं हुई. अंतत: पुलिस को बुलाया गया और कृषि विद्यालय अंबोडा के प्राचार्य कैलाश पुलिस के साथ पानी की टंकी पर चढ़े और उसे समझा-बुझा कर उतरने के लिए राजी किया.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यह ठीक है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह साबित कर दिया कि उन्हें राहुल गांधी का विश्वास हासिल है.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

राहुल के दौरे से घमासान

राजेश नामदेव

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस युवराज राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस पार्टी की खेमेबाजी में अंकुश लगने की बजाय कलह और बढ़ गई है. जब यह दौरा तय हुआ तो कांग्रेस के लोगों को लगा कि राहुल वरिष्ठ नेताओं के बीच जारी खेमेबाज़ी में अंकुश लगाएंगे और नेताओं की मुश्कें कसेंगे. युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, लेकिन उनके इस दौरे से राज्य कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ. इसलिए ऐसा लगता है कि यह दौरा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के अनुरोध पर अनियोजित दौरा था. इस दौरे से पार्टी के सामने वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की अपेक्षा पार्टी के लोगों को राहुल से थी. हालांकि राहुल गांधी का दो दिवसीय दौरा पहले दिन मुंबई के भाईदास हॉल और दूसरे दिन सतारा ज़िले के सूखाग्रस्त गांव तक ही सीमित रहा. उन्होंने न पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राज्य की समस्याओं पर विचारमंथन किया और न ही संगठन को मज़बूत बनाने के लिए कोई खाका पेश किया. स्थिति यह रही कि राहुल गांधी जब मुख्यमंत्री के साथ सतारा ज़िले के सूखाग्रस्त गांवों का दौरा कर रहे थे, तो मुंबई में असंतुष्ट विधायक व नेता राज्य के पार्टी नेतृत्व को बदलने की रणनीति बना रहे थे. हालांकि राहुल गांधी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. इतना अवश्य हुआ कि भाईदास हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने जो बातचीत की उससे कार्यकर्ता व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी जो वहां आए थे वे खुश हुए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह कार्यकर्ताओं से सवाल पूछा कि कौन सा मंत्री अच्छा काम करता है और कौन ख़राब करता है? इससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कान खड़े हो गए. इन नेताओं का मानना है कि राहुल ने ऐसा सवाल कर यह सिद्ध कर दिया कि उनमें राजनीतिक समझ की कमी है.

यह ठीक है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह साबित कर दिया कि उन्हें राहुल गांधी का विश्वास हासिल है. दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी ने उन्हें अभयदान दे दिया है. उनकी कुर्सी को ख़तरा नहीं है. इसके बावजूद राज्य में उनके और माणिकराव ठाकरे के प्रति पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है. विशेष बात यह है कि राहुल ने कार्यकर्ताओं से तो यह ज़रूर कहा कि राज्य के जिन 14 ज़िलों में कांग्रेस की स्थिति नाजुक है, वहां पार्टी को मज़बूत किया जाय, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी द्वारा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का महाराष्ट्र में पहला राजनीतिक दौरा था. राहुल के इस दौरे से पार्टी को कोई दिशा न मिलने से राज्य के नेता बेहद निराश हैं. कई नेताओं का कहना है कि उन्होंने राजनीतिक नासमझी का परिचय देकर राज्य में कलह को और बढ़ा दिया है. वहीं राहुल गांधी ने सूखाग्रस्त इलाक़ों का दौरा करने निकले तो मुख्यमंत्री के ज़िले तक ही सीमित रहे और ढाई घंटे में दौरा पूरा कर दिल्ली रवाना हो गए. इससे अन्य सूखाग्रस्त ज़िले के नेता मुख्यमंत्री के इस रवैये से नाराज़ हैं. उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने सूखाग्रस्त अन्य इलाक़ों का दौरा क्यों नहीं किया? जिस गांव का दौरा किया था, उस गांव के लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि, उन्हें पानी चाहिए. कोई आश्वासन या वादा नहीं चाहिए. विशेष बात यह है कि उस गांव से कुछ ही मील दूर कोयना में जलाशय मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी ने गांव वालों की समस्या का निवारण करने के सिलसिले में मुख्यमंत्री से कुछ नहीं कहा. इससे यह बात ज़ाहिर हो जाती है कि राहुल गांधी का यह दौरा पूरी तरह से अनियोजित और जल्दबाज़ी में तय किया गया था.

जहां तक पार्टी में खेमेबाजी की बात है तो जैसे-जैसे पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, ऐसे में विलासराव देशमुख को लगता है कि उनसे जुड़े मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर कुछ नहीं किया जा रहा है. एक-एक मामला खुलता जा रहा है और उसके लिए पार्टी के लोग ही विपक्ष और मीडिया को सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं. देशमुख और मुख्यमंत्री चव्हाण के बीच आदर्श सोसायटी मामले की जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी न केवल मतभेद हैं, बल्कि तकरार भी बढ़ गई है. रिपोर्ट में आदर्श की ज़मीन सरकार की बताए जाने पर विलासराव देशमुख ने स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार से मांग की थी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीआई के पास दर्ज कराई गई एफआईआर वापस ली जाए. उनका तर्क था कि जब ज़मीन सरकार की है तो यह मामला ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ठुकरा दिया. इससे चव्हाण और देशमुख के बीच तकरार बढ़ने की चर्चा है. यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बदलने की जो क़वायद असंतुष्टों द्वारा की जा रही है, उसे विलासराव देशमुख ही बढ़ावा दे रहे है. देशमुख के उकसावे पर ही बाग़ी विधायकों की दिल्ली जाने की तैयारी उस दिन थी, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर निकले थे, लेकिन राहुल के महाराष्ट्र आने पर असंतुष्टों ने अपना इरादा बदल दिया. देशमुख इस बात से भी नाराज़ हैं कि राज्य सरकार ने विसलिंग वुड्स मामले में भी उनका बचाव नहीं किया और अब लातूर में उनकी संस्था को आवंटित ज़मीन का मामला भी सामने आ गया है. लिहाज़ा जैसे-जैसे विलासराव देशमुख की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, वे असंतुष्टों को और उकसा रहे हैं. पार्टी के लोगों का कहना है कि देशमुख का साथ दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण. आखिर वे भी आदर्श के कारण अपना पद गंवा चुके हैं. असंतुष्टों की मुख्यमंत्री को बदलने की क़वायद और मुख्यमंत्री से देशमुख में तकरार की सूचना राहुल तक न पहुंची हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तकरार को रोकने के लिए अपने दौरे के दौरान कुछ भी नहीं किया. इस बात से न केवल पार्टी कार्यकर्ता हैरान हैं, बल्कि वरिष्ठ नेताओं की समझ में भी यह नहीं आ रहा है राहुल गांधी का यह दौरा किस मक़सद से आयोजित किया गया था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से जब यह सवाल किया था कि राज्य का कौन-सा मंत्री सबसे अच्छा काम कर रहा है और कौन-सा नहीं? यदि इस सवाल का जबाव दिया जाय तो मुख्यमंत्री की कार्यशैली के कारण राज्य के विकास कार्यों की गति में कमी आई है और कई तो रुके पड़े हैं. यदि किसी कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर अंगुली उठाई होती तो पार्टी के अंदर उसकी क्या हालत कर दी जाती. राहुल की इस नासमझी पर पार्टी के अंदर खूब चर्चा हो रही है. वहीं मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं का भी मानना है कि यदि राहुल ने कार्यकर्ताओं की बात पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया तो उनका कार्य करना मुश्किल हो जाएगा. ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की जायज़-नाजायज़ मांगों को न मानना उनके लिए भविष्य में महंगा पड़ सकता है.

प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को बदलने की मांग भी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर बोलने की ज़रूरत नहीं समझी. इसलिए पार्टी के अंदर ही सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस दौरे से क्या लाभ हुआ? राहुल के इस दौरे से राज्य के दो ही नेता खुश हैं, जिनके नाम हैं पृथ्वीराज चव्हाण और माणिकराव ठाकरे. इन दोनों को लगता है कि राहुल के दौरे से पार्टी के असंतुष्टों को यह संदेश मिल गया होगा कि, उन्हें दिल्ली का वरदहस्त प्राप्त है.

नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी यदि इसी तरह कार्य करेंगे तो पार्टी में विवाद और बढ़ेंगे. इस तरह से तो पार्टी का और बेड़ागर्क होगा. इसके अलावा राहुल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की धौंसपट्टी से निपटने के विषय में भी नेताओं को कोई नसीहत नहीं दी. जबकि राज्य में कांग्रेस और राकांपा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी के इस दौरे से निराश हैं. मुंबई का अध्यक्ष पद कृपाशंकर सिंह के इस्तीफ़े के बाद से खाली पड़ा है. इसे लेकर गुरदास कामत और मिलिंद देवड़ा के बीच खींचतान चल रही है. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को बदलने की मांग भी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर बोलने की ज़रूरत नहीं समझी. इसलिए पार्टी के अंदर ही सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस दौरे से क्या लाभ हुआ? राहुल के इस दौरे से राज्य के दो ही नेता खुश हैं, जिनके नाम हैं पृथ्वीराज चव्हाण और माणिकराव ठाकरे. इन दोनों को लगता है कि राहुल के दौरे से पार्टी के असंतुष्टों को यह संदेश मिल गया होगा कि, उन्हें दिल्ली का वरदहस्त प्राप्त है. उनकी कुर्सी को किसी प्रकार का ख़तरा नहीं है. दूसरी ओर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पार्टी को वर्ष 2014 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करनी है तो राज्य में नेतृत्व को बदला जाना ज़रूरी है. राज्य की कमान ऐसे नेता के हाथ में देनी होगी, जो पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर सके. घोटाले में घिरी सरकार की छवि को जनता की नज़र में सकारात्मक बनाने की क्षमता रखता हो. यदि ऐसा नहीं होता है तो पार्टी की राह 2014 में आसान नहीं होगी. एक और ख़ास बात राहुल के दौरे में देखी गई कि उनके प्रति राज्य के युवा वर्ग का वैसा आकर्षण नहीं रहा जैसा उत्तरप्रदेश चुनाव परिणाम आने के पहले होता था. पार्टी के युवा नेताओं में जमकर गुटबाज़ी हावी है और वे अपने आकाओं के इशारे पर कार्य करते हैं. अब यदि राज्य में चल रही कलह पर पार्टी आलाकमान अंकुश नहीं लगा पाता है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव पार्टी को रामभरोसे ही लड़ना होगा. ■

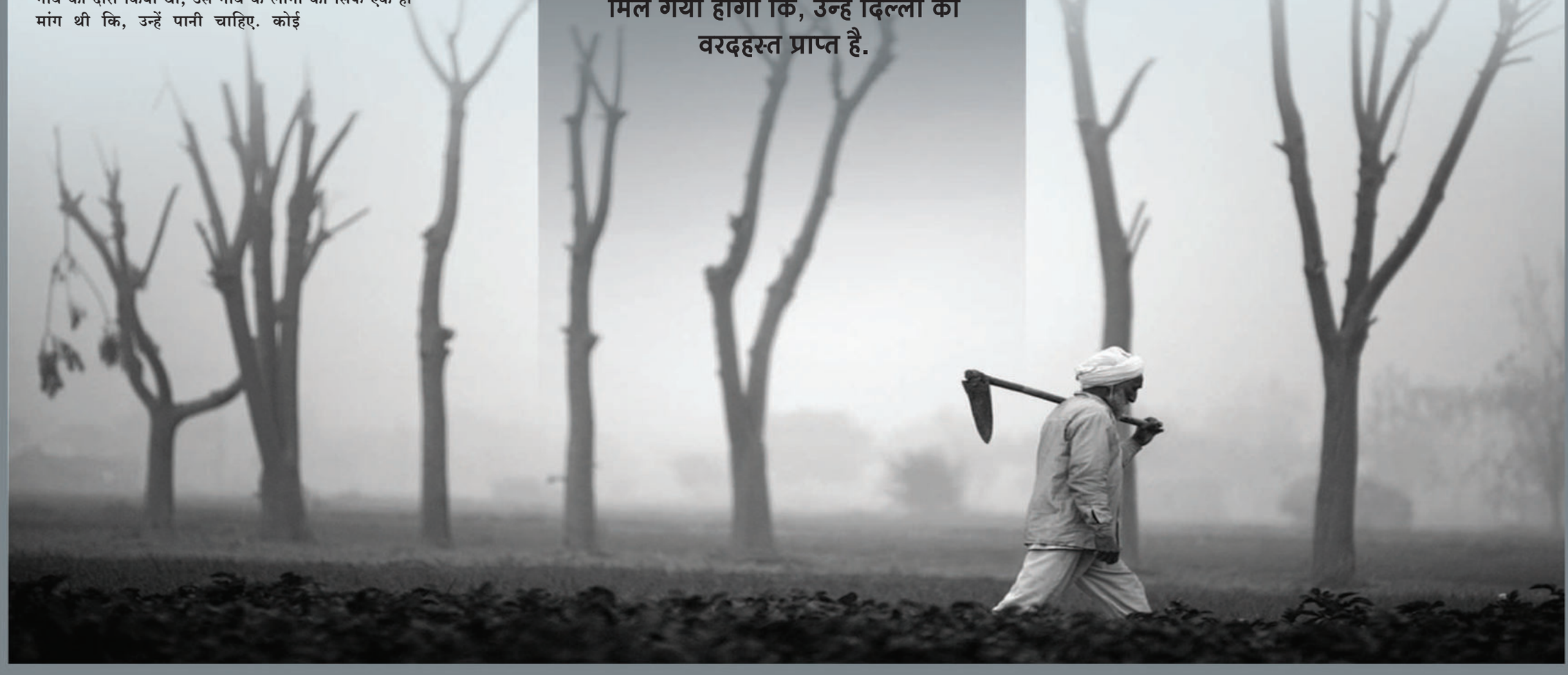

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 14 मई–20 मई 2012

www.chauthiduniya.com

राज्य सूचना आयोग

आरटीआई का दुश्मन

क्या राज्य की जनता को यह जानने का हक़ नहीं है कि मुख्यमंत्री की यात्राओं में जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा लुटाया जा रहा है. आख़िर इस तरह की सूचना सरकार छिपाना क्यों चाहती है. मैंने मुख्य सचिव को भी इस संबंध में पत्र लिखकर अविलंब इससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की मांग की है.

- मिथिलेश सिंह

आयोग से सूचना लेना लंका विजय जैसी बात है. लोग सूचना मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिलती है. काग़ज़ी खानों में ऐसा फंसा दिया जाता है कि सूचना मांगने वाला आदमी थक हार कर बैठ जाता है. आयोग के एक सदस्य जिस मामले की सुनवाई करते हैं दूसरे सदस्य इस मामले को सुनवाई के योग्य नहीं मानकर ख़ारिज कर देते हैं. आयोग के अंदर ही इतनी खिंचतान है कि सही समय पर सूचना मिलना टेढ़ी खीर हो गई है.

-शिवप्रकाश राय
आरटीआई कार्यकर्ता

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बड़ी मुश्किल है, मुख्यमंत्री सचिवालय कहता है कि मुख्यमंत्री की यात्राओं से संबंधित ब्योरा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग कहता है कि उसके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. आख़िर मुख्यमंत्री की इन यात्राओं से संबंधित जानकारी किसके पास है.

सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

सूचना क्रांति के इस युग में अगर सूचना आयोग ही सूचना छिपाने के काम में मशगूल दिखे तो इसे क्या कहा जाएगा. सूचना के अधिकार क़ानून के लागू हो जाने के बाद आम जनता यह अपेक्षा रखती है कि उसे हर वह सूचना समय पर मिल जाएगा जो नियम क़ानून की परिधि में आता है. लेकिन बिहार में सूचना आयोग के कामों पर अगर सतही नज़र भी डाली जाए तो वह इस संकल्प में काफ़ी पीछे नज़र आ रहा है. आरटीआई कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने एवं उनकी हत्याओं में हो रही लगातार बढ़ोतरी तो एक अलग कहानी है. यहां पर बात आयोग के कार्यशैली के कारण सूचना मांगने वाले लोगों को हो रही निराशा से शुरू करते हैं.

लोक चेतना मंच के संयोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने 7 जनवरी 2012 को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2006 से दिसंबर 2011 तक न्याय यात्रा, विकास यात्रा और इस तरह की जो भी यात्राएं की हैं, इसमें कितनी धनराशि का ख़र्च आया है, इसका विवरण दिया जाए. मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग के द्वारा मिथिलेश कुमार सिंह को बतलाया गया कि वांछित सूचना इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. यह मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है. इसलिए उनके आवेदन को इस विभाग में भेज दिया गया है. आठ फरवरी के पत्र में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी जय कृष्ण दास ने मिथिलेश सिंह को बतलाया कि आपने जो सूचना मांगी है, वह इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है. बड़ी मुश्किल है, मुख्यमंत्री सचिवालय कहता है कि मुख्यमंत्री की यात्राओं से संबंधित ब्योरा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग कहता है कि उसके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. आख़िर मुख्यमंत्री की इन यात्राओं से संबंधित जानकारी है किसके पास. मिथिलेश सिंह कहते हैं कि क्या राज्य की जनता को यह जानने का हक़ नहीं है कि मुख्यमंत्री की यात्राओं में जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा लुटाया जा रहा है. आख़िर इस तरह की सूचना सरकार छिपाना क्यों चाहती है. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को भी इस संबंध में पत्र लिखकर अविलंब इससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की मांग की है.

आरटीआई कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय बताते हैं कि आयोग से सूचना लेना लंका विजय जैसी बात है. लोग सूचना मांगते–मांगते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिलती है. काग़ज़ी खानों में ऐसा फंसा दिया जाता है कि सूचना मांगने वाला आदमी थक हार कर बैठ जाता है. उन्होंने आयोग की कार्यशैली पर कहा कि आयोग के एक सदस्य जिस मामले की सुनवाई करते हैं दूसरे सदस्य इस मामले को सुनवाई के योग्य नहीं मानकर खारिज कर देते हैं. आयोग के अंदर ही इतनी खिंचतान है कि सही समय पर सूचना मिलना टेढ़ी खीर हो गई है. सूचना आयोग की कार्यशैली की एक और बानगी देखिए. यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि बिहार राज्य सूचना आयोग को यह भी जानकारी नहीं है कि पांच वर्षों से उसके पास लंबित वाद कितने हैं. आयोग को इतना भी मालूम नहीं है कि सूचना अधिनियम, 2005 के तहत कितने आवेदन पत्रों का निष्पादन हुआ अथवा बिहार के प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के समक्ष बतौर अपील कुल कितने आवेदन दाख़िल किए गए और कितने निष्पादित किए गए. आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि बिहार राज्य सूचना आयोग इस बात से भी अंजान है कि बिहार के कुल कितने लोक सूचना पदाधिकारियों के नाम अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई और कितने लोक सूचना पदाधिकारियों ने अपने वेतन से अर्थदंड अदा किया. आवेदक प्रो. दिग्विजय नाथ झा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग से मांगी गई. जानकारी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 01 अप्रैल, 2006 से 30 सितंबर 2011 के बीच बिहार राज्य सूचना आयोग की ओर से कुल कितने लोक सूचना पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई और आयोग की अनुशंसा पर कितने लोक सूचना पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की गई, यह जानकारी राज्य सूचना आयोग के पास नहीं है. हद तो यह है कि 2006 से 2011 के बीच आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों की संख्या भी बताने में राज्य सूचना आयोग सक्षम नहीं है. जानकारों के मुताबिक इस तरह की स्थिति का मुख्य कारण आरटीआई वर्करों के ख़िलाफ़ सितम ढ़ाना ही है. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले आवेदक पदाधिकारियों के कोप का शिकार हो रहे हैं. कोई झूठे मामले में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहा है तो कोई पुलिसिया डंडे का शिकार बन रहा है. सूचना का अधिकार क़ानून लागू होने के बाद से सूचना मांगने वाले कई आवेदकों के साथ हुई बदसलूकी इस बात को चीख–चीखकर बयान कर रही है कि बिहार में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगना गुनाह बनता जा रहा है. बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक सिंह तथा पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि की अगर माने तो सच से सरकार घबराती है. प्रो. दिग्विजय नाथ पांडेय अकेले ऐसे आवेदक नहीं हैं, जिन्हें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना पदाधिकारी ने आधी अधूरी जानकारी देकर अपना पल्ला झाड़ लिया. आवेदकों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है सचिन ठाकुर, शिवकृति सिंह, मो. सरफुद्दीन सहित कई ऐसे आवेदक हैं, जिन्हें वाजिब सूचना देना लोक सूचना पदाधिकारी ने गंवारा नहीं समझा. मो. सरफुद्दीन ने यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक सह लोक सूचना पदाधिकारी से जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए स्वास्थ्य परिदर्शक अनिल प्रसाद एवं भूपेंद्र कुमार के संदर्भ में यह जानकारी मांगी थी कि किस आधार पर दोनों अभी तक सेवा में बने हुए हैं और वेतन भुगतान पा रहे हैं. लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब जानकारी नहीं दी गई तो उन्होंने अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलीय आवेदन दाख़िल किया. अपीलीय पदाधिकारी के दिशा–निर्देश पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मो. सरफुद्दीन को यह जानकारी दी गई कि अपीलीय पदाधिकारी के नाम संबोधित आपके आवेदन पत्र की छाया प्रति उपनिदेशक मुख्यालय स्वास्थ्य सेवाएं सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी(यक्ष्मा) द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन आपके द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी के नाम आवेदित आवेदन कार्यालय को अप्राप्त है. इसलिए समय सीमा बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप ग़लत है. उन्होंने अपना पल्लू झाड़ने वाले अंदाज़ में जानकारी देते हुए लिखा कि आयुक्त एवं सचिव स्वास्थ्य सेवाएं पटना को भेजे गए पत्र (पत्रांक 831/24.12.05) एवं (पत्रांक–749/19.12.2006) के आलोक में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं अपने पत्र(पत्रांक 924/22.12.06) में इस मामले से संबंधित किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं बताई है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि निदेशक प्रमुख के पत्रांक 1408(11) तथा निदेशक टीवीडीसी के पत्रांक 352/18.07.09 के द्वारा अंकेक्षण आपत्ति को विलोपित करने हेतु लिखा है. संबंधित कर्मचारियों के संबंध में मुख्यालय से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी सेवा में बने हुए हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं. जबकि इसके पूर्व यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक ने अपने पत्र(ज्ञापांक 749/19.12.06) के ज़रिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को लिखे पत्र में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल (निगरानी) अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 249/02.08.06 का हवाला देते हुए स्पष्ट लिखा था कि स्वास्थ्य परिदर्शक अनिल प्रसाद एवं भूपेंद्र कुमार जाली एवं फ़र्ज़ी स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हैं और अवैध रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं.

निगरानी विभाग के आरक्षी अधीक्षक द्वारा दोनों स्वास्थ्य परिदर्शकों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखा गया है. 1984–1985 तक 9वें बैच के रूप में अंतिम स्वास्थ्य परिदर्शक का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था. इसलिए दोनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जाली है. दोनों नामित कर्मी के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने की दिशा में आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए. इतनी प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद भी जब आवेदक सरफुद्दीन को पूर्ण जानकारी नहीं मिली तब उन्होंने राज्य सूचना आयोग से इस संदर्भ में जानकारी की मांग की. लेकिन राज्य सूचना आयोग के द्वारा भी जानकारी नहीं दी गई कि आख़िर दोनों नामित स्वास्थ्य परिदर्शक किस आधार पर सेवा में बने हुए हैं. इस तरह के कई ऐसे मामले हैं. जिसमें आवेदक के द्वारा बार–बार सूचना अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन संबंधित विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी तो क्या राज्य सूचना आयोग के द्वारा भी जानकारी देना उचित नहीं समझा गया. उम्मीद की जानी चाहिए कि आयोग अपनी कार्यशैली में सुधार करेगा ताकि आमलोगों को सही समय पर ज़रूरी सुचनाएं उपलब्ध हो सके. ■

चौथी दुनिया

माले के कट्टर समर्थक प्रभु बरनवाल ने इस बार की चुनाव में पार्टी से ख़फ़ा होकर माले के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है.

सरकारी योजनाओं से काफ़ी दूर पूर्वी चंपारण ज़िले के छियासठ पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरें दम तोड़ने के कगार पर हैं.

बेगूसराय

किसान छले जा रहे हैं

युवराज feedback@chauthiduniya.com

नीतीश सरकार के द्वारा किसानों के उत्थान के बाबत कई तरह की योजनाएं चलाने का दावा किया गया था, लेकिन सुशासन की सरकार के लापरवाह अधिकारियों के कारण कोई कारगर क़दम अभी तक नहीं उठाया गया है. इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों को फ़सल की वास्तविक क़ीमत दिलाने तथा उनका आर्थिक बोझ कम करने के ख्याल से 1285 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं ख़रीदने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिए जाने के बावजूद इसका सीधा लाभ ग़रीब किसानों को मिलने के बजाय पूंजीपतियों, जमाखोरों, दलालों तथा अधिकारियों को मिलने के आसार अधिक दिख रहे हैं. अगर बेगूसराय ज़िले की बात की जाए तो बीते 15 अप्रैल से ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की ख़रीदारी सरकारी स्तर पर शुरू करने की घोषणा की गई थी. इसके लिए ज़िले के 247 पैक्सों के अलावे स्टेट फूड कॉरपोरेशन को अधिकृत भी कर दिया गया था. सरकार के द्वारा साफ़ एवं 12 प्रतिशत तक नमी वाले गेंहू का 1285 रु. प्रति क्विंटल मूल्य अदायगी का सब्जबाग़ किसानों को दिखाया गया था. बावजूद इसके अप्रैल माह की समाप्ति तक भी ख़रीदारी शुरू नहीं की जा सकी है. अगर कुछ जगहों पर ख़रीदारी शुरू भी की गई है तो पहचान पत्र, एलपीसी, ज़मीन की अद्यतन रसीद की गई खेती का ब्योरा, अनुमानित पैदावार एवं बिक्री योग्य गेंहू आदि का ब्योरा जैसे काग़ज़ी उलझन को सुलझा पाना अधिकांश किसानों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है. जबकि हक़ीक़त यह है कि 95 प्रतिशत गेंहू की फ़सल तैयार हो चुकी है ऐसी स्थिति में ग़रीब किसानों का कमर टूटना लाजमी है. ग़रीब किसानों के द्वारा क़र्ज़ लेकर खेती करना और फ़सल तैयार होते ही क़र्ज़ वापसी करना उनकी मजबूरी होती है. कई ग़रीब किसानों के समक्ष बेटी की शादी एवं जिंदगी गुजारने के लिए फ़सल के एवज में मिलने वाली राशि ही एकमात्र सहारा होता है. ऐसी स्थिति में इस तरह की घोषणा महज छलावा साबित हो रही है. [illegible]

बेगूसराय ज़िले की बात की जाए तो बीते 15 अप्रैल से ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की ख़रीदारी सरकारी स्तर पर शुरू करने की घोषणा की गई थी. इसके लिए ज़िले के 247 पैक्सों के अलावे स्टेट फूड कॉरपोरेशन को अधिकृत भी कर दिया गया था. सरकार के द्वारा साफ़ एवं 12 प्रतिशत तक नमी वाले गेंहू का 1285 रु. प्रति क्विंटल मूल्य अदायगी का सब्जबाग़ किसानों को दिखाया गया था. बावजूद इसके अप्रैल माह की समाप्ति तक भी ख़रीदारी शुरू नहीं की जा सकी है.

परिस्थिति के मारे किसान अधिप्राप्ति शुरू होने की राह देखते-देखते इस क़दर हार गए कि अब कम क़ीमतों पर गेंहू बेचना उनकी मजबूरी हो गई है. इन ज़रूरतमंद ग़रीब किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पूंजीपतियों के साथ-साथ बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं जबकि किसान कंगाल हो रहे हैं. बिचौलिए और पूंजीपतियों के द्वारा ग़रीब किसानों से महज 1050 रुपये प्रति क्विंटल ही गेंहू की ख़रीददारी की जा रही है. इतना ही नहीं कई तरह का सब्जबाग़ दिखाकर उनसे परिचय पत्र एवं ज़मीन की रसीद का फोटोकॉपी भी ले लिया जाता है.

जानकारों की बातों पर भरोसा करें तो अधिकारियों की मिलीभगत से अधिप्राप्ति में विलंब कर ज़िले के अधिकांश किसानों का गेंहू कम क़ीमतों पर पूंजीपतियों के गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है. जानकारों का यहां तक कहना है कि बाद में ऐसे ही किसानों के नाम पर समर्थन मूल्य में अधिप्राप्ति की काग़ज़ी प्रक्रिया पूरी कर पैक्सों एवं स्टेट फूड कॉरपोरेशन की पूंजी पर आंकड़ें पूरे कर लिए जाएंगे और मोटी रक़म का बंदरबांट कर लिया जाएगा. परना पैक्स अध्यक्ष नागेश्वर महतो, बछवाडा पैक्स अध्यक्ष रामलखन सिंह, प्र लाद राय, भोला शर्मा नरसिंहपुर पैक्स अध्यक्ष रामनरेश राय सहित लगभग सभी पैक्स अध्यक्ष की कमोवेश एक ही शिकायत है. यह बात अलग है कि सभी आरोपी पैक्स अध्यक्ष इस तरह की शिकायत को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि विरोधियों के द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है. किसानों का स्पष्ट कहना है कि कहीं [illegible] मांगा जाता तो बगले झांकने लगते हैं. वैसे वह यह स्वीकारने से गुरेज नहीं करते हैं कि अब तक मात्र 117 पैक्सों को ही राशि उपलब्ध कराई जा सकी है. अगर ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी की ही मानें तो अब भी 130 पैक्सों को राशि उपलब्ध नहीं हो सकी है. हक़ीक़त यह भी है कि 117 पैक्सों में अधिकांश खाली बोरे एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है. जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्थिति के कारण लगभग सभी जगह पैक्सों द्वारा गेंहू की ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी है. आंकड़ों के खेल का एक और नमूना अगर देखा जाए तो सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिख जाएगा. ज़िले में 70 हज़ार एमटी गेंहू की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ज़िले में फिलवक्त महज 30 हज़ार एमटी गेंहू संग्रहण के लिए सरकारी गोदाम उपलब्ध हैं. इतना ही नहीं कई गोदामों में पूर्व से जनवितरण प्रणाली अथवा अन्य सरकारी योजना के खाद्यान्न भरे पड़े हैं. कई गोदामों में तो अब तक ख़रीद किए गए धान भी रखे हैं. ऐसी स्थिति में यह समझ से परे है कि 70 हज़ार एमटी गेंहू की ख़रीद का लक्ष्य आख़िर कैसे रखा गया.

इधर डीएसओ का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर क्रय किए जाने वाले गेंहू को रेल द्वारा अन्यत्र भेजा जाएगा. वैसे इसके लिए भी अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. रेल बुकिंग के लिए लगने वाली कतार के कारण डीएसओ द्वारा यह कहा जाना भी महज सांत्वना देने के समान लगता है. इस तरह के हालात से नराज़ कांग्रेसी नेत्री अमिता भूषण, राजद के अशोक [illegible]

कई दाग़ी प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ संगीन आरोप

शुभम राज चौहान feedback@chauthiduniya.com

छपरा

[illegible] है कि कुछ उम्मीदवार अपने वार्ड के मतदाताओं को लुभाने के लिए दूसरे वार्ड में ढ़ाले गए स्लैब को चुराकर रातों-रात अपने वार्ड में लगाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं. अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रत्याशी कोई भी हथकंडा अपनाने से परहेज नहीं कर रहे हैं. पांच वर्षों तक भले ही लगभग सभी वार्ड अंधेरे में डूबे थे, लेकिन अब वार्डों में इन दिनों वेपर लाइट लग जाने के कारण गलियां गुलजार दिख रही हैं. इतना ही नहीं गलियों में भी आजकल काफ़ी साफ़-सफ़ाई किया जा रहा है. इस तरह की व्यवस्था देखकर लोगों के मुंह से यह बरबस निकलता है कि काश रोज चुनाव का मौसम आता. वैसे पांचों नगर निकायों में कुल 55 दाग़ी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. छपरा नगर परिषद में 32 प्रत्याशी, रिविलगंज नगर पंचायत में 12, सोनपुर नगर पंचायत में 8 तथा मढ़ौरा नगर पंचायत में 3 प्रत्याशी दाग़ी बताए जा रहे हैं. इनमें 49 पुरुष एवं छह महिलाएं हैं. दर्जन भर प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं. आधा दर्जन प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ लूट, चोरी और झपटमारी के मुक़दमें दर्ज हैं. कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं, जिनके ख़िलाफ़ शराब के अवैध धंधे में लिप्त होने का आरोप है. शहर के समस्याओं की अगर बात की जाए तो शहर के वार्ड संख्या 33 में गड़खा विधायक ज्ञानचंद्र मांझी तथा मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय का निवास स्थान होने के कारण आए दिन लालबत्ती लगी गाड़ियों का गुजरना और प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है. बावजूद इसके यहां समस्याएं सूरसा के समान मुंह बाए खड़ी हैं. सड़क की साफ़-सफ़ाई एवं जलजमाव की समस्याएं विकराल बनी हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक शिकायत करते-करते और आश्वासन सुनते-सुनते थक चुके हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

वार्ड की सबसे बड़ी समस्या नाली के पानी की निकासी को लेकर है. कई जगह पर नालियां जर्जर हो चुकी है. इधर रेलवे लाइन के पास ऊंचाई होने के कारण नाली के पानी की निकासी नहीं हो पाती है. ऐसे में गर्मी हो या बरसात, नाली का गंदा पानी सड़कों पर ही जमा रहता है. यह स्थिति कमोवेश वार्ड के सभी गली-मोहल्लों की है. कुछ जगहों पर नालियां बनी भी है, तो इन पर रखे अधिकतर स्लैब टूटकर बिखड़े पड़े हैं और हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. 22 नंबर वार्ड वीआईपी मोहल्ला कहलाता है. इस वार्ड में राजद के राष्ट्रीय नेता सह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, जदयू के वरीय नेता सह विधान पार्षद डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह, एकमा के विधायक धूमल सिंह सहित जलालपुर-रामपुर के समाजसेवी रमेश कुमार सिंह, वरीय अधिवक्ता सीपी सिंह उर्फ़ टूनटून बाबू सहित कई वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं. लेकिन इस वार्ड में भी कचरा और गंदगी का साम्राज्य कायम है. कभी-कभार ही सफ़ाईकर्मी वार्ड में दिखाई पड़ते है. जबकि वार्ड पार्षद का दावा है कि कम संसाधनों के बाद भी अतिरिक्त व्यवस्था कर सफ़ाई कार्य को चालू रखा गया है. वैसे वार्ड में पेयजल की समस्या भी है. नगर परिषद की वार्ड संख्या 31 में रहनेवाले लोग ख़ुद को उपेक्षित मानते है. सफ़ाई, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से महरूम वार्डवासियों की माने तो लगभग एक दशक से नगर विकास विभाग के पूर्व राज्यमंत्री उदित राय का निवास होने के बावजूद न तो यहां नियमित रूप से कचरे का उठाव होता है और न ही नालियों की सफ़ाई होती है. वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रही पूर्व मुख्य पार्षद उर्मिला देवी के ख़िलाफ़ उनकी ही जेठानी चुनावी मैदान में कूदकर चुनावी जंग को रोचक बना दी हैं. छपरा नगर परिषद की पूर्व मुख्य पार्षद शोभा देवी के ख़िलाफ़ वार्ड नंबर 25 से कुमकुम देवी कड़ी टक्कर देने को उतावली हैं. वार्ड नंबर 11 से तीन दशक से भी अधिक समय से लगातार पार्षद रहे सियाराम सिंह को भी साहेब हुसैन द्वारा टक्कर मिल रही है. नशा उन्मूलन तथा नगर विकास के लिए प्रयासरत दिलीप कुमार द्वारा वार्ड नंबर 8 से चुनाव में ताल ठोंकने के कारण यह वार्ड सुर्खियों में है. रिविलगंज नगर पंचायत में तीन पूर्व अध्यक्ष यथा वार्ड संख्या 16 से रमेश प्रसाद, 20 से दिनेश प्रसाद यादव एवं 11 से निर्मल कुमार सिन्हा चुनावी समर में हैं. तीन-तीन पूर्व अध्यक्षों का एक साथ चुनावी जंग में कूदना रोचक दृश्य उपस्थित कर रहा है. नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान अध्यक्ष पूनम देवी एवं उपाध्यक्ष रंजीत यादव की नगर पंचायत में दोबारा वापसी संभव नही है क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष पूनम देवी ख़ुद चुनाव नहीं लड़कर अपनी देवरानी को सहयोग करने का निर्णय ले चुकी हैं. उपाध्यक्ष रंजीत यादव अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं. इधर नगर निकाय चुनाव में लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की तरफ़ से शहर के वार्डों मे नुक्कड़ सभा का आयोजन कर संयोजक बब्लू राही द्वारा लोगों से अपने कर्तव्य व दायित्व के प्रति सजग रहने का आह्वान किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक विद्याभूषण सिंह, सुविख्यात गांधीवादी एवं गांधी आश्रम के संस्थापक विजय कुमार, कश्मीरा सिंह सहित दर्जनों समाजसेवी इस अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं. ■

दम तोड़ रही हैं चंपारण की ऐतिहासिक धरोहरें

इंतेजारूल हक़ feedback@chauthiduniya.com

ऐतिहासिक धरोहरों का अस्तित्व बचाने तथा इसे विकसित करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं किए जाने के बाद भी चंपारण की ऐतिहासिक धरोहरें दम तोड़ रही है. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केसरिया महोत्सव के दौरान हुई घोषणाओं पर भी अभी तक अमल नहीं किया गया है. सीताकुंड धाम की स्थिति देखकर लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन इससे न ही सरकार को सरोकार है और न ही विभागीय पदाधिकारी इसके लिए संजीदा हैं.ऐतिहासिक धरोहरों का अस्तित्व बचाने तथा इसे विकसित करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं किए जाने के बाद भी चंपारण की सैकड़ों ऐतिहासिक धरोहरें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं. इस संदर्भ में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरजमीं पर लाने का ऐलान करने वाली सरकार पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के क़रीब एक सौ ऐतिहासिक धरोहर के विकास के प्रति संजीदा नहीं है. विभागीय उदासीनता के कारण ज़िला प्रशासन चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाती है. जानकारी के मुताबिक सरकारी योजनाओं से काफ़ी दूर पूर्वी चंपारण ज़िले के छियासठ पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरें दम तोड़ने के कगार पर हैं. केसरिया का बौद्ध स्तूप हो या फिर कस्बा मेहसी के साढ़े सात बीघा में फैला गुरू नानक मठ. चकिया प्रखंड का बेदीबनगढ़ हो या सीताकुंड धाम, तमाम ऐतिहासिक धरोहरें अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को विवश है. इनके विकास के लिए अब तक की गई तमाम कार्रवाई हवा-हवाई साबित हो रही है. प्रत्येक वर्ष केसरिया में लाखों रुपये की लागत से आयोजित होने वाले केसरिया महोत्सव में घोषणाओं की बरसात होती है, लेकिन महोत्सव समाप्ति के बाद घोषणाएं जमींदोज हो जाती है. दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप माने जाने वाले केसरिया के बौद्ध स्तूप के आस-पास पर्यटकों का आगमन सालों भर लगा रहता है. लगभग एक सौ पांच फीट उंचे इस स्तूप के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए मंत्रियों ने केसरिया को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की घोषणाएं की थी. नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व प्रमुख एवं कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव, केसरिया अनुमंडल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ. बीके राय, पूर्व मुखिया राज कुमार प्रसाद, पार्षद पति शंभू महतो, राजद के युवा नेता जयंत कुमार सिंह, लोजपा नेता शर्वदेव राय, महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान के सचिव सीताराम यादव, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मो. मुस्ताक, पंचायत समिति सदस्य मो. इशाक अहमद, राजद के युवा नेता मुन्नीलाल यादव आदि कहते हैं कि विगत वर्ष 2011 में केसरिया महोत्सव के उद्घाटन के दौरान सूबे के लोक स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय ने न केवल केसरिया में पानी टंकी निर्माण की घोषणा की थी बल्कि इस क्षेत्र के अन्य विकास योजनाओं पर कार्य शुरू कराने का ऐलान भी किया था. महोत्सव के दूसरे दिन पहुंची शिवहर की सांसद रमा देवी ने विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के विकास एवं केसरिया को पर्यटन स्थल घोषित कराने के मुद्दे पर लोकसभा में मामला उठाने का आश्वासन दिया था. महोत्सव के समापन के मौक़े पर पहुंची कला संस्कृति एवं युवा मामले की मंत्री प्रो. सुखदा पांडेय ने केसरिया स्तूप के विकास के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजने तथा केसरिया में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम निर्माण एवं कला संस्कृति भवन बनवाने की घोषणा की थी. लेकिन घोषणा के अनुरूप एक भी योजना सरजमीं पर नहीं उतर सकी. हाल बेहाल बेदीबनगढ़ के विषय में भी किसी को चिंता नहीं है. किसी प्राचीन किले का अवशेष कहे जाने वाले सीताधाम की सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है. वैसे लगभग अठारह एकड़ में फैले पंद्रह फीट उंचे सीताकुंड कुंड धाम के संदर्भ में जानकार बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम- सीता यहां आए थे, लेकिन नवविवाहिता सीता के स्नान के लिए बनाया गया सीताकुंड, गिरीराज महादेव का प्राचीन मंदिर, पुरातात्विक महत्व के शीलालेख समेत कई देवी-देवताओं की तस्वीरें अपनी बदनसीबी पर मायूस है. लगभग चार सौ वर्ष पुराना कस्बा मेहसी स्थित मिर्जा हलीम साह का दरगाह विकास के लिए लालायित है. ऐतिहासिक धरोहरों में बेलवतिया का मठ भी काफ़ी चर्चित है. 1895 में केशव बाबा द्वारा स्थापित कबीर पंथ की पारखा शाखा का कबीरा आश्रम तथा साहेब की गद्दी की स्थिति देखकर लोगों को तरस आती है. अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी उद्धारक को तलाशता महात्मा गांधी का बुनियादी विद्यालय बड़हरवा लखनसेन अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है. सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पंद्रह अप्रैल 1917 को धर्म समाज चौक स्थित गोरखबाबू अधिवक्ता के जिस मकान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ठहरे थे, उसकी भी हालत ठीक नहीं है. बीते वर्ष 1903 के 25 जून को मोतिहारी स्थित गोपाल साह विद्यालय के छात्रावास में जन्मे अंग्रेजी के उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली एवं इसाइयों का प्राचीन कब्रिस्तान भी हाशिए पर है. हालांकि एनईपी के निदेशक की मानें तो तत्कालीन जिलाधिकारी नर्मदेश्वर लाल ने चंपारण के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के बाबत पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा था. इसी परिप्रेक्ष्य में धरोहरों को विकसित करने के लिए ज़िला प्रशासन अपना काम भी कर रही है, लेकिन सुलगता सवाल यह है कि क्या पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजने से ही ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प संभव है? अगर नहीं तो विभागीय पदाधिकारी और सरकारी हुक्मरान के द्वारा इस संदर्भ में क्या-क्या क़दम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हाशिए पर दिख रहे ऐतिहासिक धरोहरों का विकास नहीं होना सरकार एवं विभागीय कार्यशैली पर सवालियां निशान खड़ा करने के लिए काफ़ी है. ■

एक नज़र

लालू के बेटे ने हीरो का शोरूम खोला

क्रिकेट के मैदान में कुछ ख़ास न कर पाने के बाद लालूजी ने अपने बेटे तेज प्रताप उर्फ़ तेजू को पारिवारिक राजनीति से इतर व्यवसाय में उतरने की सलाह दी. पिता की नेक सलाह मानकर तेजू ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को चुना और उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प की औरंगाबाद में एजेंसी ले ली. शहर में एनएच-2 (बाइपास रोड) पर कामाबिगहा के पास एक साल से एजेंसी का भवन निर्माण चल रहा था. शुभ मुहूरत में 28 अप्रैल को लालूजी ने शोरूम का उद्घाटन किया. तेजू ने इस एजेंसी का नाम बड़े प्यार से अपने पिता एवं मां के नाम पर लारा हीरो रखा है, ला से लालू और रा से राबड़ी. हालांकि लारा (लालू-राबड़ी) हीरो शोरूम के कर्मचारीगण इस बात से इंकार करते हैं कि यह शोरूम लालू-राबड़ी के नाम पर है. उनका कहना है कि लालू परिवार ने पहले भी लारा नाम से एक कंपनी गठित किया था और इसी कंपनी के नाम पर हीरो मोटोकॉर्प की एजेंसी ली गई है. फिलहाल औरंगाबाद में हीरो के बाईक वह भी लालूजी के बेटे के शोरूम से ख़रीदने के गौरव से गौरवान्वित होने के लिए बाईक ख़रीदने के इच्छुक लोग शोरूम की ओर लगातार रूख कर रहे हैं.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

तालीमी केंद्र खोलने की आज़ादी हो

जमुई और नवादा ज़िला के सरहद पर उर्दू मीडिल स्कूल आढ़ा में एक जलसा आयोजित हुआ. इस मौक़े पर मौलाना वली रहमानी ने अपने तकरीर के बीच कहा कि 2010 के आरटीई क़ानून लागू होने के बाद अकलियतों में मजहबी तालीम का वजूद ख़तरे में पड़ गया. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को मानने वालों के मुताबिक़ उन्हें तालीमी केंद्र खोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए. मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा लागू किए गए कुछ क़ानून से तालीम के होकूक और धर्म तालीम पर बंदीश लग जाएगी. मुंतजीम कार की हैसियत से डॉक्टर सोहेल, शाहिद मलिक, हाफिज तनवीर, मास्टर गाजी आदि ने अपनी ज़िम्मेदारी बख़ूबी निभाया और बाशिंदगान आढ़ा ने जलसा को कामयाबी दिलाने के लिए दिलोजान से कोशिश की. जमुई के मास्टर हिजुफर रहमान ने भी इस जलसा को कामयाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

- इमरान ख़ान

फ़र्ज़ीवाड़े की शिकायत

हंटरगंज प्रखंड के कोबना पंचायत में आठ अपूर्ण इंदिरा आवास के नाम पर भुगतान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. पंचायत सचिव विरेंद्र राम एवं उपमुखिया रीना देवी द्वारा मुखिया सरिता देवी का फ़र्ज़ी हस्ताक्षर कर सरकारी राशि निकालने की जानकारी मिलने के बाद सरिता देवी द्वारा बीडीओ छुटेश्वर दास से शिकायत की गई है. इस संदर्भ में बीडीओ ने भी स्वीकार किया है कि जांचोपरांत फ़र्ज़ी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है, दोषियों के ख़िलाफ़ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

- अमरेंद्र कुमार

नाव परिचालन के नाम पर मनमानी

राज्य सरकार के द्वारा निषाद समाज के साथ-साथ चौधरी समाज के युवकों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए नाव यातायात सोसाइटी बनाते हुए नदियों में नाव चलाने का अधिनियम बनाया गया, लेकिन सरकार की ऐसी लाभकारी योजना आज दबंगों के लिए सोने पे सुहागा वाली योजना बनकर रह गई है. स्थिति यह है कि खुले डाक के बाद भी सिर्फ़ सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव ही बोली लगा सकते हैं. इससे नाव यातायात सोसाइटी के दबंग अध्यक्ष और सचिव नाव के घाटों की बोली लगाकर ग़ैर जातीय स्थानीय दबंगों के हाथ मोटी रक़म पर बेच देते हैं. इससे ग़ैर जातिय दबंग घाटों के पार उतराई पर सवारियों से मनमानी राशि ले रहे हैं. खगड़िया ज़िला अंतर्गत चौथम प्रखंड के सुदूर दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले रोहियार, बुच्चा सरसवा, ठुठ्ठी मोहनपुर, मध्य बौरने एवं पूर्वी बौरने पंचायत सहित कुछ अन्य इलाक़े के लोगों के लिए आवागमन का साधन सिर्फ़ नाव ही है. वित्तीय वर्ष 2011-12 में ज़िला प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र में पड़ने वाले घाटों के लिए खुला डाक एडीएम के निर्देशन में कराया गया. जलधारी चौधरी ने अंचल के 18 घाटों का बंदोबस्त किया, लेकिन इसके बाद स्थानीय दबंगों के हाथ मोटी रक़म वसूल कर बेच दिया गया.

- ज्योतेंद्र नारायण सिंह

विकास की गंगा बहाएंगे संजय : अमरेंद्र

संजय सिंह के एमएलसी चुने जाने पर उनके शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है. उनके शुभचिंतकों का कहना है कि विकास पसंद संजय सिंह की जीत सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है. अमरेंद्र सिंह और रिंटू सिंह ने एमएलसी चुने जाने पर संजय सिंह को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि जदयू के टिकट पर उनकी जीत ने विकास का नया द्वार खोल दिया है. जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, उसी तरह संजय सिंह भी विकास को लेकर अपनी अलग पहचान बनाएंगे. संजय सिंह समाज के सर्वमान्य रहे हैं. उनकी जीत से जनता में आस बंधी है.

इस्योग की साधना फलदायी

इस अवसरवादी युग में लोगों का मन भटकाव की ओर है. लोगों का अपने मन पर नियंत्रण नहीं रह गया है. ऐसी स्थिति में इस्योग की साधना से ही मानव मन पर अधिकार करना संभव है. उक्त बातें अंतरराष्ट्रीय इस्योग समाज के द्वारा पटना में आयोजित शक्तिपात दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए मां विजया ने कही. इस अवसर पर कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने कहा कि वर्तमान परिवेश में इंसानी रिश्तों में खटास आना समाज और परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है. लेकिन इस्योग ऐसा माध्यम है, जिसकी साधना से न केवल मानव मन पर अधिकार संभव है बल्कि आपसी रिश्ते में भी मिठास भरी जा सकती है. सुलभ ने आम लोगों से शक्तिपात दीक्षा लेने की अपील करते हुए कहा कि इस्योग की साधना के लिए शक्तिपात की दीक्षा ज़रूरी है.

- चौथी दुनिया ब्यूरो

मैरवा नगर पंचायत चुनाव

वोटरों को रिझाने में जुटे दिग्गज

पंकज कुमार feedback@chauthiduniya.com

मैरवा नगर पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं. वहीं इस बार की चुनाव में कई बड़े दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. चुनाव की तिथि को नजदीक देखते हुए प्रत्याशियों के दिन का चैन और रातों की निंद उड़ गई है. इस बार के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार पिछले चुनाव में जिते प्रत्याशियों की पोल खोलने में लगे हैं. मैरवा नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला देवी की भी प्रतिष्ठा इस बार के चुनाव में दांव पर है. प्रत्याशियों से मतदाता भी तनिक पिछे नहीं हैं. जो भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए उनके दरवाज़े पर आ रहा है उसे पूरी तरह से सहयोग करने का दिलासा दे रहे हैं. ताकि कोई भी प्रत्याशी उदास न लौट सके. मैरवा नगर पंचायत के कई ऐसे वार्ड हैं जो विकास की रौशनी से कोसों दूर हैं. मैरवा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 9 तथा वार्ड संख्या 11 विकास की रौशनी से अबतक अछूता है. बताया जाता है कि यहां के वार्ड पार्षदों के वार्ड के साथ सौतेले व्यवहार से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है. फिर भी अपनी नाराज़गी को लोग उनके सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं. पिछले बार की चुनाव में शिकस्त पा चुके कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार की चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर भ्रमण कर वार्ड को विकास से अपेक्षित बता अपनी पापड़ सेंकने में लगे हैं. गौरतलब है कि मैरवा नगर पंचायत 13 वार्डों में विभक्त है. नगर के विकास के बारे में नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला देवी का कहना है कि नगर के सभी वार्डों में बड़े पैमाने पर विकास किया गया है. नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा भी अपने वार्ड में घूम घूमकर विकास की कहानियां सुना रहे हैं. माले के कट्टर समर्थक प्रभु बरनवाल इस बार की चुनाव में पार्टी से ख़फ़ा हो कर माले के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. बताया जाता है कि इस बार की चुनाव में पार्टी उन्हें समर्थन नहीं दे रही थी, इससे नाराज़ प्रभु बरनवाल माले से बाग़ी होकर अपनी पत्नी प्रो. संगीता कुमारी बरनवाल को वार्ड संख्या 9 से चुनाव मैदान में उतारा है. संगीता पूरे नगर पंचायत में सबसे शिक्षित एवं योग्य प्रत्याशी मानी जा रही है. इसलिए चुनाव में इनका दबदबा कायम है. वहीं मैरवा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 के प्रत्याशी सुभावती देवी चुनावी आखाड़ा में कुछ पड़ी है. इनके पुत्र सुनील कुमार मद्देषिया क्षेत्र के समाजसेवी है. क्षेत्र के किसी भी समाजिक कार्य में तत्पर रहने वाले सुनील की मतदाताओं में खुब चर्चा है. इनका दावा है कि जीत दर्ज करने के बाद वार्ड में सफाई, नाला निर्माण, छठ घाट का निर्माण सहित कई कार्यो की प्राथमिकता होगी. कइ इस वार्ड के तत्कालीन वार्ड पार्शद रामेष्वर तुरहा की पत्नी माया देवी से यहां की जनता में अंदर ही अंदर काफी नाराजगी है इसका सीधा फायदा सुनील को पहुंचने वाला है. वार्ड संख्या 3 में राजनीतिक दाव पेंच काफी तेज हो गया है. संजय सिंघानिया इस बार मतदाताओं को रिझाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं. फिर भी लोगों का रूझान जदयू नेता मदन बैठा के पिता मोती लाल बैठा की ओर है. मोती लाल बैठा का कहना है कि जीत के बाद वार्ड में पीसीसी, नालों का निर्माण, सफाई, पेयजल आपूर्ति सहित कई कार्यो को कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी. ख़ास बात है कि मैरवा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7 से एक किन्नर भी चुनाव मैदान में है. हालांकि किन्नर झलरी का पूरे वार्ड में पलड़ा भारी है. इस वार्ड में मात्र दो ही प्रत्याशी लड़ाई में रह गए हैं, शशि बरनवाल और झलरी. अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ वार्ड पार्षदों को छोड़कर सभी वार्डों में नए चेहरे आने की संभावना है. वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष सुशीला देवी के विरोध में मोनिका देवी भी इस बार चुनाव मैदान में हैं. लोग उन्हें शिक्षित प्रत्याशी मानते हुए मदद के मूड में हैं. कुल मिलाकर मैरवा नगर पंचायत के अधिकतर वार्डों में नए चेहरे दिखने की उम्मीद है. देखना है ऐसे में नगर पंचायत की अध्यक्ष सुशीला देवी आपनी प्रतिष्ठा बचा पाती हैं या नहीं. ■

पूर्णिया में लगा दिग्गज डॉक्टरों का जमावड़ा

नीरज कुमार सिंह feedback@chauthiduniya.com

पूर्णिया ज़िले के इतिहास में पहली बार एसोसिएसन ऑफ फिजीशियन ऑफ इंडिया की पूर्णिया शाखा द्वारा दो दिवसीय राजस्तरीय सम्मेलन बापीकॉन 2012 का आयोजन पूर्णिया की विद्या बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मरंगा में किया गया जिसके आयोजन में दवा कंपनी एरिस्कोन फर्मा ने महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभाई. देश भर से आए प्रसिद्ध फिजीशियन चिकित्सकों ने कंपनी को इस आयोजन में सहयोग के लिए तारीफ़ों के पुल बांध दिए. चिकित्सकों के बापीकॉन-2012 सत्र की शुरुआत प्रात: 10:30 बजे हुई जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. एस एन आर्या ने किया जबकि अतिथि डॉक्टरों का स्वागत ऑर्गेनाइजेशन चेयरमेन डॉ. देवी राम ने बुके देकर किया. वहीं डॉ. आर्या का सम्मान डॉ. देवी राम ने शॉल देकर किया. सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. एस एन आर्या ने कहा कि पूर्णिया जैसे शहरों में इस तरह के वैज्ञानिक सत्र का आयोजन कराने के लिए पूर्णिया के डॉक्टर धन्यवाद के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होने से छोटे डॉक्टरों को भी नए शोधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौक़ा मिलता है. इस दो दिवसीय वैज्ञानिक सत्र के पहले दिन देश के नामी-गिरामी चिकित्सकों ने अलग-अलग विषयों पर अपना व्याख्यान दिया. मालूम हो कि इस सत्र में बिहार एवं अन्य राज्यों से आए सैकड़ों प्रसिद्ध चिकित्सकों के अनुभवों को सुनने के लिए सैकड़ों मेडिकल छात्रों ने इसमें भाग लिया.

सत्र के प्रथम दिन सांय काल में पूर्णिया के भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह एवं धमदाहा विधायक लेसी सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस तरह के सत्र का पूर्णिया में आयोजन को लेकर प्रसन्नता जाहिर की. इस दौरान सांसद एवं चिकित्सकों की आगवानी से लेकर व्यवस्था की देख रेख में एरिस्कॉन फर्मा के वरूण सिंह, अमरेंद्र कुमार एवं पूरे बिहार से आए उनके टीम के सदस्य जी जान से जुटे रहे. बापीकॉन-2012 में पांडीचेरी, नागपुर, बंगलौर, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मोतीहारी आदि जगहों से आए चिकित्सकों ने भाग लिया. इस सेशन में फिजीशियनों को कालाजार, हृदय रोग मधुमेह, मलेरिया, डायबिटीज, किडनी, कैंसर एवं एड्स पर हुए नवीनतम अनुसंधान के बारे में जानकारी दी गई. इस सत्र को सफ़ल बनाने के लिए पूर्णिया के डॉ. देवीराम सीनीयर एसपी सिंह, डॉ. देवी राम, सीनीयर एस पी सिंह, डॉ. आर के मोदी, डॉ. बी पी साह, डॉ. एके पाठक, डॉ. उमेश कुमार एवं डॉ. अजय कुमार विगत कई महीनों से प्रयासरत थे, वहीं बाहर से आए चिकित्सक डॉ. एन कंजल्क, डॉ. मिलिंद नादकर एवं डॉ. बी आर बानसौड जैसे प्रसिद्ध चिकित्सकों ने भाग लिया. ■

संजय झा झंझारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं

विजय शंकर पांडेय feedback@chauthiduniya.com

मिथिलांचल के बहुचर्चित भाजपा नेता संजय झा एमएलसी का टिकट लेने से क्यों इंकार कर गए, यह रहस्य गहराता जा रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर मधुबनी तथा पटना में भी सियासी जानकारी रखने वाले इस बात का कई मतलब निकाल रहे हैं. पार्टी में चर्चा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली के आशीर्वाद से पिछली बार एमएलसी बनने वाले संजय झा को किस बात की नाराज़गी थी कि इस बार वह एमएलसी का टिकट लेने से पीछे हट गए. सियासी जानकारों की माने तो पिछली बार एमएलसी बनने के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के काफ़ी क़रीब पहुंचने वाले झा नीतीश के नाक के बाल माने जाते हैं. नीतीश से निकटता इसी बात से समझी जा सकती है कि व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में भी संजय झा से नीतीश कुमार सलाह मशविरा लेते हैं. जब भी बिहार के मुखिया का मिथिलांचल दौरा होता है तब सभास्थल का निरीक्षण करने से लेकर सभा में मुख्य भूमिका निभाने में वह आगे रहे हैं. दिल्ली में आयोजित बिहार दिवस भी संजय झा के ही नेतृत्व में मनाया गया था. यह देखकर कयास लगाया जाने लगा कि झा भाजपा छोड़कर जदयू का दामन थाम सकते हैं. वैसे झा ने भाजपा छोड़ने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एमएमसी का टिकट लेने से इंकार कर झा ने जदयू में जाने का इशारा ज़रूर कर दिया है. जानकारों की माने तो विगत लोकसभा चुनाव में दरभंगा से चुनाव लड़ने का इरादा उन्होंने जाहिर किया था. दरभंगा के पूर्वी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के सहयोग से उन्होंने कई विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया, एमएमसी फंड का अधिकांश हिस्सा उन्होंने इसी इलाक़े के विकास के नाम पर ख़र्च किया. इस अति पिछड़े क्षेत्र का विकास किए जाने के कारण उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई. जनता से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें दरभंगा से लोकसभा टिकट मिलने की बात होने लगी, लेकिन टिकट बंटवारे के समय लालकृष्ण आडवाणी के आशीर्वाद से कीर्ति झा आज़ाद को टिकट मिल गया. कीर्ति झा आज़ाद की जीत के बाद दरभंगा में भाजपा दो ख़ेमों में बंटने लगी. भाजपा के स्थानीय चुनाव में कीर्ति झा के पसंदीदा अमरनाथ गामी का भाजपा जिलाध्यक्ष बनना भी संजय झा को सालने लगा. वर्तमान में भाजपा जिलाध्यक्ष अमरनाथ गामी हायाघाट के विधायक भी हैं. जानकारों के मुताबिक झा मधुबनी या अपने कार्य क्षेत्र दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीतने की चाहत रखते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि भाजपा में रहते उनका सपना पूरा नहीं हो सकता. इसलिए वह भाजपा को छोड़ना चाहते हैं. झा को यह भय सताने लगा है कि कीर्ति झा आज़ाद फिलहाल दरभंगा के सांसद हैं और अगले लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद होने के कारण उन्हें टिकट मिलना तय है. मधुबनी संसदीय क्षेत्र न उनका कार्य क्षेत्र है और न ही गृह क्षेत्र. ऐसे में मधुबनी संसदीय क्षेत्र से टिकट लेना वह मुनासिब नहीं समझते. मधुबनी संसदीय क्षेत्र से टिकट लेने की तमन्ना वह पार्टी नेताओं के समक्ष रखेंगे भी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव का वहां से सांसद रहने के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी. इन दो सीटों के अलावा उनकी नज़र झंझारपुर लोकसभा सीट पर भी हो सकती है. वर्तमान में झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए उन्हें जदयू का टिकट मिल सकता है. जदयू सांसद मंगलीलाल मंडल को जदयू से निलंबित कर दिया गया है. जदयू से मंगलीलाल मंडल की सदस्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुशंसा भी की जा चुकी है. लोकसभा अध्यक्ष की मंडल की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है तो वहां उपचुनाव होना तय है. ऐसे में संजय झा को लोकसभा उप-चुनाव के लिए टिकट थमाना आसान है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी राजनीतिक इच्छा के कारण वह भाजपा से अलग होकर जदयू का दामन थामते हुए झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं. झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अरड़िया संग्रामपुर में उनका पैतृक घर होने और नीतीश के क़रीबी होने का राजनीतिक लाभ मिलना तय माना जा रहा है. जानकारों की माने तो भाजपा कोटे से एमएलसी होने के बाद भी भाजपा द्वारा उन्हें तरजीह नहीं दिया गया जितना मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया. पिछले लोकसभा चुनाव में झंझारपुर सीट मुख्यमंत्री के द्वारा अति पिछड़ों के लिए छोड़ा गया था. नतीजतन विधान परिषद के पूर्व उपसभापति वीरेंद्र चौधरी ने इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अंत में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने मंगली लाल मंडल को टिकट थमा दिया. मंगली लाल के निलंबन के पश्चात विरेंद्र चौधरी इस सीट पर नज़र लगाए बैठे हैं. देखना है कि इस सीट के लिए विरेंद्र चौधरी को टिकट मिलता है या संजय झा को, लेकिन इस मामले में संजय झा का पलड़ा इसलिए भारी लगता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का राजनीतिक क़द छोटा करने के बाद बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री नीतीश मिश्रा का ब्राह्मण समाज में बढ़ते क़द के कारण बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, संजय झा को टिकट देने का राजनीतिक गोटी खेल सकते हैं. बहरहाल, संजय झा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और वह भाजपा का दामन छोड़कर जदयू का दामन थामने के बाद भी क्या झंझारपुर के सांसद बन सकेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन झा के द्वारा एमएलसी का टिकट लेने से इंकार करना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है. ■

वार्ड नं. दो में अलाउद्दीन एवं अफ़रोज अंसारी, तीन से हसीबउद्दीन एवं मोशाकिबूल हसन, 15 से संगीता देवी एवं गुड्डी देवी, 16 से पूनम देवी एवं रेहाना खातून के बीच सीधा मुक़ाबला होना तय है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सहरसा नगर परिषद्

चक्रव्यूह में दिनेश सिंह

दिनेश चंद्र यादव

डॉ.आलोक रंजन

गुंजेश्वर साह

आनंद मोहन

श्याम सुंदर साह

राजू महतो

उमेश यादव

विनय ठाकुर

रेणु सिन्हा

संजीव प्रियश्री

संजीव कुमार झा

रंजना सिंह

मो.महफ़ूज

बलेश्वर भगत

बजरंग गुप्ता

अनिता देवी

ए.रहमान

सिद्धी प्रिया

दुर्गाकांत झा पिंटु

अनिता कुशवाहा

अनिल गोप

विमल किशोर

सुबोध साह

श्याम जायसवाल

सरस्वती देवी

साजन शर्मा

राजेंद्र यादव

आवेश कर्णी

मुन्नी देवी

जयप्रकाश शर्मा

रेशमा शर्मा

संजय सोनी

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया के सांसद दिनेश चंद्र यादव का अब तक सहरसा की नगर परिषद से लेकर ज़िला परिषद तक की राजनीति में सिक्का चलता रहा है, लेकिन इस बार पूर्व विधायक संजीव झा एवं गुंजेश्वर साह भी राजनीतिक तिकड़म खेलने के लिए तैयार बैठे हैं. वैसे यह अलग बात है कि सहरसा के विधायक डॉ. आलोक रंजन के राजनीतिक सुर के संदर्भ में कयास लगाना अभी भी मुश्किल प्रतीत हो रहा है.

सहरसा नगर परिषद का चुनाव सिर्फ़ राजनीति का हिस्सा नहीं रह गया है बल्कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी यहां दांव पर लगी रहती है. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सहरसा के नगर परिषद से लेकर ज़िला परिषद की राजनीति तक के लिए खगड़िया के सांसद दिनेश चंद्र यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल, पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व विधायक गुंजेश्वर साह, पूर्व विधायक संजीव कुमार झा, एवं श्याम सुंदर साह के साथ-साथ पूर्व विधायक सतीश चंद्र झा सरीखे नेताओं के बीच घमासान होता रहा है. लेकिन हाल के कई चुनावों में सिर्फ़ सांसद दिनेश चंद्र यादव का ही वर्चस्व कायम रहा है. वैसे यह अलग बात है कि पूर्व मंत्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल बीमार रहने के कारण राजनीति से दूर हैं, जबकि पूर्व विधायक सतीश चंद्र झा किसी न किसी कारण फिलवक्त राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं. पूर्व नगर पिता श्याम सुंदर साह भी राजनीति के कमजोर खिलाड़ी बनकर रह गए हैं, इसके कारण तो कई हैं.

चर्चा है कि जदयू के पूर्व विधायक गुंजेश्वर साह एवं भाजपा के पूर्व विधायक संजीव कुमार झा एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं. जबकि कड़वी सच्चाई यह भी है कि पंद्रहवी विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बगावत का झंडा बुलंद करने के कारण आपस में चाचा-भतीजे का रिश्ता रखने वालों की ज्वाइंट पॉलिटिक्स चल रही है. यह दोनों चाचा-भतीजे अक्सर सांसद दिनेश चंद्र यादव के राजनीतिक दांव-पेंच का काट करने में लगे रहते हैं. लेकिन सांसद यादव की शातिराना राजनीतिक खेल के कारण इनका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है. वर्तमान राजनीतिक स्थिति यह है कि सहरसा विधानसभा सीट पर भाजपा के डॉ. आलोक रंजन भी सांसद यादव के सुर में सुर मिलाते देखे जा रहे हैं. इस तरह की स्थिति के कारण यह तय है कि नगर परिषद चुनाव 2012 में मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के बीच ही अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने को लेकर राजनीति होगी. इतना ही नहीं अभी से ही सहरसा नगर परिषद के 40 वार्डों में अंदर ही अंदर अपने पसंदीदा उम्मीदावारों के पक्ष में चुनावी बिसात बिछाए भी जा रहे हैं. लेकिन सांसद यादव के राजनीतिक तिकड़म की यह ख़ासियत है कि वह दिल या भावना से नहीं बल्कि जीत का परचम लहराने वाले पार्षदों को ही अपने पक्ष में गोलबंद करने में महारथ रखते हैं. यही कारण है कि अब तक अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय लेने में वह सफ़ल भी होते रहे हैं. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि, वर्ष 2002 से 2007 तक अध्यक्ष की कुर्सी पर सांसद की पत्नी रेणु सिन्हा काबिज रही. फिर अध्यक्ष पद आरक्षित होने की वजह से वार्ड संख्या 19 के पार्षद राजू महतो को अपना शागिर्द बनाते हुए सांसद यादव ने अध्यक्ष की कुर्सी पर उनकी ताजपोशी करवाई. महतो भी पांच वर्षों तक गुरू भक्त आरूणी की तरह सांसद के पक्ष में अपनी भूमिका निभाते रहे, लेकिन पांच वर्षों में विकास की बात तो दूर महतोजी नगर परिषद के 40 वार्डों का भ्रमण भी शायद नहीं कर पाए. नगरवासी आज तक नगर अध्यक्ष के रूप में रेणु सिन्हा को ही जानते रहे हैं.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बीच पूर्व विधायक संजीव झा विनय ठाकुर को अध्यक्ष बनाने के लिए अपने राजनीतिक क्षमता एवं दक्षता का भरपूर उपयोग करने से बाज नहीं आए. यह बात सही है कि सफ़लता उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन इस बार नगर परिषद चुनाव के पहले दाव में ही सांसद यादव एवं पूर्व विधायक झा आमने-सामने दिख रहे हैं. हालांकि वार्ड सं. 29 से सांसद यादव की पत्नी रेणु सिन्हा के साथ-साथ वार्ड सं. 11 से भाजपा के पूर्व विधायक झा के वार्ड के प्रत्याशी विनय ठाकुर निर्विरोध चुन लिए गए. इस तरह की स्थिति देखकर यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद अध्यक्ष पद के लिए घमासान होना तय है. चर्चाओं पर भरोसा करें तो सांसद यादव का सिक्का इस बार भी चलना आसान नहीं होगा. हालांकि राजनीतिक दाव-पेंच अंदर ही अंदर चल रहा है. सभी दिग्गज समर्थित उम्मीदवार नगरीय वैतरणी पार करने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं. ■

नए चेहरे भी खिलाएंगे गुल

सहरसा नगर परिषद क्षेत्र के कुल चालीस वार्डों में से वार्ड सं. 11 एवं 29 को छोड़कर कुल 191 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. सभी पाषर्दों को अपनी काबिलयत पर न केवल गरूर है बल्कि चुनावी जंग जीतने का भरोसा भी है. वैसे कई वार्ड पार्षदों का नगर वासियों के साथ रिश्ता मधुर नहीं है. कुछ वार्ड पार्षद लोगों को विकास का आईना तो नहीं दिखा पाए, लेकिन वार्ड के कुछ नव युवकों को नशेड़ी ज़रूर बना दिए. विकास कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो पांच वर्षों में विकास का ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, जिसकी चर्चा प्रमुखता के साथ की जाए. हां! यह अलग बात है कि नगर परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी होने के क़रीब एक पखवाड़ा पूर्व अधिकांश वार्डों में स्ट्रीट लाइट ज़रूर लगाए गए. बिजली के बिना वेपर लाइट भले ही नहीं रौशन हो लेकिन नया रहने के कारण अपने वजूद का एहसास ज़रूर कराती हैं. खैर, कई चुनाव में लगातार असफ़ल रहने वाले प्रत्याशियों ने इस बार वार्ड बदल कर तक़दीर आजमाना जायज समझा है. नगर परिषद के 40 वार्डों में वार्ड सं. 19 के पार्षद सह निवर्तमान अध्यक्ष राजू महतो एवं वार्ड सं. 28 के पार्षद सह निवर्तमान उपाध्यक्ष उमेश यादव वर्ष 2007 से 2012 के कार्यकाल को पूरा किया है. वार्ड सं. 20 के पार्षद जयप्रकाश शर्मा, वार्ड सं. 22 से पार्षद घनश्याम चौधरी, वार्ड सं. 8 से पूर्व नगर पिता श्याम सुंदर साह की पत्नी सरस्वती देवी, वार्ड सं. 26 से बिमला देवी, वार्ड सं. 3 से शहनाज खातुन, वार्ड सं. 17 से अनिता कुशवाहा सहित अन्य पुराने प्रत्याशी मैदान में हैं. जबकि वार्ड सं. 9 से अनिता देवी, वार्ड सं. 4 से बुचिया देवी, वार्ड सं. 21 से रेशमा एवं वार्ड सं. 20 से बजरंग गुप्ता, वार्ड सं. 23 से संजीव प्रियश्री, वार्ड 27 से रंजना सिंह, वार्ड 22 से बालेश्वर भगत, वार्ड 28 से पत्रकार ए. रहमान, वार्ड सं.30 से दुर्गाकांत झा पिंटु, वार्ड 38 से मो. मोफीज आदि नए चेहरे इस चुनाव में बाजी मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं.

मतदाताओं की ख़ामोशी से प्रत्याशी परेशान

मनेंद्र/गीता कुमार

feedback@chauthiduniya.com

मई माह में होने वाले नगर पंचायत चुनाव के लिए कई चुनावी पहलवान अखाड़े में कूदने को बेताब हैं. सभी प्रत्याशी अपने-अपने तरीक़े से चुनावी गणित मतदाताओं को समझाने में लगे हैं. खगड़िया ज़िले के गोगरी जमालपुर नगर पंचायत के 20 वार्डों में से कई वार्ड ऐसे हैं, जहां दो ही प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में होने के कारण मुक़ाबला सीधा नज़र आ रहा है. कई ऐसे भी वार्ड हैं, जहां वार्ड पार्षदों ने इस बार चुनावी मैदान में कूदना मुनासिब नहीं समझा. वार्ड नं. 1 के वार्ड पार्षद अमर कुमार साह, वार्ड नं. 7 से सरोजनी देवी एवं वार्ड नं. 17 से नसीम अहमद इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं, जबकि वार्ड नं. दो में अलाउद्दीन एवं अफरोज अंसारी, तीन से हसीबउद्दीन एवं मोशाकिबूल हसन, 15 से संगीता देवी एवं गुड्डी देवी, 16 से पूनम देवी एवं रेहाना खातून के बीच सीधा मुकाबला होना तय है. जानकारों के मुताबिक वार्ड नं. 4 में अबु मोहम्मद का राजनीतिक भविष्य दाव पर लगा हुआ है. उन्हें शाकिर हुसैन के द्वारा कड़ी चुनौती मिलना तय माना जा रहा है. वार्ड नं. 12 में सनोज मिश्रा, कुमार रवि एवं अजित मिश्र के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला होने वाला है. वार्ड नं. 13 में फुलचंद्र पटेल, माया राम एवं त्रिलोकि चंद्रनाथ शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि वार्ड पार्षद बीते पांच वर्षों में किए गए विकास कार्यों को गिनाकर मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं. मतदाताओं का नब्ज टटोलने पर यह स्पष्ट हुआ कि वार्ड नं. 3 में हसीबउद्दीन तथा उनके प्रतिद्वंद्वी, वार्ड नं. 15 में संगीता देवी एवं गुड्डी के बीच सीधी टक्कर है. वार्ड नं. 14 में किरण देवी तथा अंजली कुमारी के बीच टक्कर होना तय माना जा रहा है. वार्ड नं. 9 से चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रही पूर्व राज्य सभा सदस्य सह पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद की पुत्रवधु रंजीता कुमारी निषाद के संबंध में उनके समर्थकों का कहना है कि जीत सुनिश्चित तो है ही, नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर विराजमान होना भी तय है. वर्ष 2007 के चुनाव में पूर्व मंत्री की छोटी पुत्रवधु प्रियंका कुमारी अध्यक्ष पद पर काबिज हुई थीं. इधर वार्ड नं. 17 से कमरउद्दीन, वार्ड नं. 18 से रंजना देवी, वार्ड नं. 19 से वार्ड पार्षद युवा नेता ऋषिकांत मंडल एवं राजीव कुमार चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं, लेकिन इन सभी के चुनावी जंग जीतना इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि इन वार्डों में रोचक मुकाबला होना है. वहीं वार्ड नं. 20 में रेणु देवी एवं अनिता शर्मा के बीच घमासान की स्थिति बनी हुई है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस बार गोगरी जमालपुर पंचायत में नगर पंचायत का चुनाव जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं है. मतदाताओं की ख़ामोशी के कारण सभी प्रत्याशियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचती जा रही है. ■

बिहार का नं. 1 Consultancy
M.S. EDUCATIONAL TRUST
ADMISSION GIDANCE & CAREER SOLUTION (Govt. Registered) NO DONATION CONFIRM ADMISSION
MEET OUR BEST CAREER COUNSELOR IN BIHAR More than 551 Colleges on No Donation on Direct Admission
45 प्रतिशत PCM वाले बच्चों का एडमिशन निश्चित ADVISED OFFERED IN : Engineering, Medical, MBA, BBA, BCA, Polytechnic, PGDM & B.Ed.
Free with Every Registration
Bihar Head Office: Maa Complex Saketpuri, Bazar Samiti, Bahadurpur, Patna - 016, Ph :0612-6560169, Fax : 0612-2673939, email : sanjay1976_singh@rediffmail.com, website : www.mset.co.in
Branch Office : Rampur Road Near S.K. Tyagi Coaching, main Gate, Bazar Samiti, 2) Baidhianath Atta Chakkki Jai prakash Path (Near anup Cinema Hall) Chhapra, and also in (Siwa, Dhanbad, Jamshedpur, Ranchi, Aurangabad, Katihar) Admission Helpline : 9308392927, 9430292927, 9572323234 Jharkhand Office Shatabdi Tower, Shop No.-1, Second Floor Jamshedpur

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 14 मई–20 मई 2012

www.chauthiduniya.com

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

लोकायुक्त के दायरे में नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री

दर्शन शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण होती नज़र आने लगी है. लोकायुक्त का हौसला तब और बुलंद हो गया जब सपा सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही उनका कार्यकाल का अगले दो वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया. लोकायुक्त ने मायावती सरकार में हुए घोटालों में लिप्त विधायकों और मंत्रियों की जांच करने में कोई कोताही नहीं बरती, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने की पूरी कोशिश की. यद्यपि उनकी सहज प्रवृत्ति के कारण उन पर कई सवाल उठाये गये. वह निडरता से मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अमल करते रहे. उन्होंने न तो कोई ढील दिखाई और न ही किसी को बख्शा. अच्छी बात यह रही कि बसपा सुप्रीमों ने आपरेशन क्लीन के दौरान सरकार के कई दागी मंत्रियों और विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था. लेकिन बसपा सरकार ने अपनी पार्टी के रसूखदार मंत्री नसीमुद्दीन को लोकायुक्त के फंदे से बचाने की सिफारिश कर अपने बेदाग होने का प्रमाण दे दिया था. उत्तरप्रदेश में सपा सरकार के गठन के बाद लोकायुक्त के कार्यकाल और नए लोकायुक्त को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गयी थीं. इन सभी अटकलों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकायुक्त मेहरोत्रा को 2 साल का सेवाविस्तार देकर विराम लगा दिया था. वहीं नई सरकार ने लोकायुक्त कार्यालय को भी नए भवन में स्थानांतरित कर दिया है. न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा के लिए सब कुछ चमत्कार जैसा है. नए कार्यालय में पहुंचते ही उन्होंने उन पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया, जिन पर बसपा सरकार के दौरान क़ायदे से अमल नहीं हो सका था.

लोकायुक्त के काम करने के तरीके में आए बदलाव को देखकर शिकायतों में दर्ज रसूखदारों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खिंच गयी हैं. सपा के घोषणा पत्र में दर्ज है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त संस्था को न केवल मजबूत बनाना जरूरी है बल्कि उसके नियंत्रण में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को भी लाने की आवश्यक्ता है. सपा सरकार लोकसेवकों के बीच से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए कटिबद्ध होगी.नहीं तो भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी तंत्र की वजह से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकेगा. सपा के घोषणापत्र के अनुरूप लोकायुक्त ने भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ कमर कस ली है. लेकिन इसी बीच उन्हें इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि यदि उन्होंने रसूखदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की तो उनके पास इससे बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है, जो उनके प्राणों की रक्षा कर सके. इसलिए उन्होंने शासन से लोकायुक्त कार्यालय में उपयुक्त सुरक्षा इंतजाम करने के लिए कहा. लेकिन लोकायुक्त के इस कदम से लोगों के बीच यह संदेश गया कि बसपा शासन में लोकायुक्त ने सुरक्षा संबंधी कोई बात नहीं की थी, जबकि लोकायुक्त बसपा सरकार के बड़े से बड़े नेता के विरुद्ध कार्यवाही करते जा रहे थे. लेकिन सपा शासन में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सरकार से सुरक्षा की मांग करनी पड़ गयी. लोकायुक्त ने कार्यालय के सभी प्रवेश द्वारों पर सशस्त्र गार्डों की तैनाती करने के साथ ही भवन में आने–जाने वालों की जांच पड़ताल के लिए मेटल डिटेक्टर लगाने का शासन से अनुरोध भी किया है. मुख्य सचिव (गृह) को भेजे गये पत्र में न्यायमूर्ति महरोत्रा ने कहा है कि बहुत से भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ जांच चल रही है. कार्यालय में बहुत से लोगों का आना–जाना लगा रहता है. मौजूदा समय में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं हैं, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए आने जाने वालों पर निगाह रखने के लिए कार्यालय के सभी प्रवेश द्वारों पर सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात करने की आवश्यक्ता है.

गृह सचिव का कहना है कि उन्हें इस संबंध में लोकायुक्त का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. गृह सचिव लीना जौहरी के अनुसार पत्र मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त को सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा. न्यायमूर्ति मेहरोत्रा ने लोकायुक्त को और मजबूत करने के लिए अपने सुझाव शासन को भेजे हैं. इन सुझावों में मुख्यमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी को जांच के दायरे में लाने की बात की गई है. सरकारी धन लेने वाली सभी संस्थाएं, एनजीओ, ट्रस्ट, और समितियां, अनुदानित शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग व मेडिकल संस्थान आदि भी इसकी जद में हों. वहीं लोकायुक्त संगठन को बहु सदस्यीय बनाने की बात भी की गई है. सांसदों को छोड़ हर जनप्रतिनिधि लोकायुक्त कार्यालय को सालाना संपत्ति का ब्यौरा दें. यदि सरकार जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न करे तो उन्हें स्वत: कार्यवाही करने का अधिकार हो. पुलिस, एसटीएफ, ईओडब्ल्यू, सीबीसीआईडी, एंटी करप्शन या विजिलेंस आदि जांच एजेंसी सभी उनके नियंत्रण में हो. लोकायुक्त को सर्च वारंट जारी करने का अधिकार हो और किसी भी मामले में स्वत: संज्ञान भी ले सकने का अधिकार लोकायुक्त को हो. प्रदेश में लोकायुक्त संस्था को और मजबूत बनाने और इसके दायरे में मुख्यमंत्री को लाए जाने संबंधी लोकायुक्त मेहरोत्रा के सुझावों के दो दिन बाद ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वह सीएम को लोकायुक्त के दायरे में लाए जाने के पक्ष में नहीं हैं. बुद्धजीवियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त ने इस संस्था को मजबूत बनाने के लिए जो सुझाव दिए हैं उनको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना कम ही लग रही थी, क्योंकि इन सुझावों में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त जांच के दायरे में रखे जाने की बात की गई है. मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी मुख्यमंत्री यह नहीं चाहेगा कि वह लोकायुक्त की जांच के दायरे में आए. केंद्र में लोकपाल विधेयक पारित न हो पाने का एक बड़ा कारण यह है कि राज्य सरकारों को इस पर आपत्ति है. जिस तरह लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को शामिल करने की बात की जा रही है, उसी तरह मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के जांच के दायरे में होना चाहिए. यह विचित्र है कि मुख्यमंत्री जिस व्यवस्था को प्रधानमंत्री के लिए ठीक मान रहे हैं वैसी ही व्यवस्था को अपने प्रदेश में अस्वीकार कर रहे हैं. फिलहाल यह उम्मीद नहीं है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर सहमत होंगे कि उनका पद लोकायुक्त की जांच के दायरे में आएं. बहरहाल मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अन्य सुझावों पर प्राथमिकता के आधार विचार करना चाहिए. मुख्यमंत्री पद को लोकायुक्त के दायरे में लाने जैसे मुद्दे पर उनकी आपत्ति का कारण कुछ भी हो, लेकिन उनके अन्य सुझावों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. इन सुझावों को लोकायुक्त की संस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक माना जा रहा है. कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि लोकायुक्त की ऐसी सिफारिशों के मल में देरी न होने पाए. ये सुझाव प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मददगार साबित हो सकते हैं. ये ऐसे सुझाव नहीं हैं जिससे सरकार मुसीबत में पड़े. यह एक अच्छा अवसर है जब सपा सरकार अपने घोषणापत्र के मुताबिक काम कर वाहवाही लूट सकती है. लोकायुक्त का कहना है कि लोकायुक्त के दायरे में किसे रखा जाए किसे नहीं, यह तय करना विधायिका का अधिकार है. बहुत से राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं. दिल्ली में तो नौकरशाह भी लोकायुक्त के दायरे से बाहर हैं. ■

प्रभावशाली लोकायुक्त बनाने की कवायद

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल छह वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया है .सरकार ने इस निर्णय से व्यायमूर्ति मेहरोत्रा को संजीवनी दी है. महरोत्रा का पिछला कार्यकाल 15 मार्च को ही खत्म हो चुका था. अपने नए कार्यकाल में उन्होंने फिर से लोकायुक्त के रुप में काम करना शुरू कर दिया है. वह लोकायुक्त प्रशासन को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश में हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ लोकायुक्त प्रशासन को कर्नाटक और मध्यप्रदेश से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनाने की ठान ली है. फिलहाल लोकायुक्त के पास बसपा सरकार के 15 मंत्रियों और 49 विधायकों के खिलाफ हुई शिकायतों की जांच लंबित है. लोकायुक्त के अनुसार शिकायतों की जांच समय से पूरी की जाएगी. उनका कहना है कि सपा ने घोषणा पत्र में साफ तौर पर लोकायुक्त प्रशासन को मजबूत बनाने पर जोर दिया है. उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराना चाहे तो वह संबंधित साक्ष्यों के साथ लोकायुक्त कार्यालय से आ-वेदन पत्र लेकर उसे दाखिल कर सकता है. मगर अब शिकायतकर्ता को एक हजार रूपए आवेदन पत्र के साथ जमा कराने होंगे, उसके बाद ही शिकायत पर विचार किया जाएगा और जांच शुरू की जाएगी. उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान, सहायता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं. ये संस्थाएं उनके दायरे में नहीं हैं. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और राज्य के मंत्रियों की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत उनके कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं.

मुख्यमंत्री का बयान वादाख़िलाफी है:भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने की जोरदार वकालत की है. उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉ मनोज मिश्र ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाए बिना संभव नहीं है. डॉ मिश्र ने कहा कि सशक्त लोकपाल लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा. सरकार का मुखिया जब तक लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान कि समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है, चौंकाने वाला हैं. मुख्यमंत्री से लेकर छोटे तक लोकायुक्त के दायरे में होना ही चाहिए. समाजवादी पार्टी ने चुनाव के पहले प्रदेश की जनता से सशक्त लोकपाल लाने का वायदा किया था. मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त के दायरे से बाहर रहने का बयान देकर जनता से वादाखिलाफी की है.

लोकायुक्त जांच में अड़ंगा लगा रहे हैं बसपाई

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी का कहना है कि बसपाई लोकायुक्त जांच में अड़ंगा लगा रहे हैं. लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है. लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जांच करने वाली इन एजेंसी का अपना महत्व है. इस संस्था ने अब तक कई महत्वपूर्ण जांचें की है. बसपा शासनकाल में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. उन्होंने कहा कि बसपा के विधायकों, मंत्रियों और दबंगों से त्रस्त जनता ने जब उनके अवैध कब्जों, सत्ता के दुरूपयोग और लूटमार के साक्ष्य दिए तो जांच में कई मामले सही पाए गए. बसपा के कई मंत्री पद से हटे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने कारनामों को छुपाने के लिए लोकायुक्त संस्था को भी बदनाम कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में बसपा के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व खेल राज्यमंत्री अयोध्या प्रसाद पाल के आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच चल रही है. कानून के राज की बड़ी-बड़ी बातें करने वाली बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अपने शासनकाल में कानून के साथ खूब खिलवाड़ किया. अपराध बढ़ते रहे शासन प्रशासन बेपरवाह बना रहा. न्यायिक संस्थाओं की गरिमा धूलधूसरित होती रही. विरोध के स्वर उठते ही बसपा राज में गोलियां और लाठियां बरसने लगती थीं. लोकायुक्त की जांच में सबसे ज्यादा अड़ंगेबाजी बसपा के पूर्व मंत्री ही कर रहे हैं. पूर्व खेल राज्यमंत्री का लखनऊ स्थित फार्म हाउस तिलिस्म बनकर रह गया है. पता ही नहीं चल रहा है कि उस पर मालिकाना हक किसका है. रोज किसी नए पार्टनर का नाम उछलता है. लोकायुक्त ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन और अयोध्या पाल के बेटों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है. लेकिन वो बार-बार बुलाए जाने पर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं. यह मानसिकता जांच संस्थाओं की परवाह न करने और अपनी सामंती उदंडता दिखाने की है. संविधान के प्रति जिनमें दुर्भावना है वही जांच एजेंसी के सामने जाने से घबराते हैं. दरअसल उन्हें अपने कारनामों से डर लगता है. उन्हें यह भी घबराहट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके कृत्यों पर पर्दा नहीं पड़ पाएगा.उन्होंने जो किया है उसका फल भुगतना ही पड़ेगा.

आवश्यकता है

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया को उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों एवं ज़िलों में आवश्यकता है संवाददाताओं, विज्ञापन प्रतिनिधियों एवं प्रसार व्यवस्थापकों की. अनुभवी एवं कार्यरत लोगों को वरीयता दी जाएगी. सम्मानजनक वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय. इच्छुक लोग पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं:-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11
नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष -0120-6451999, 6452888, 6450888

Email -advt.uttarpradesh@gmail.com

कांग्रेस और भाजपा सपा फोबिया से ग्रस्त

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. दोनों ही दल के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के समय बड़ी-बड़ी बातें की थीं. यूपी का किला फतेह करने के लिए दोनों दल ने पूरे देश से आयातित नेताओं को उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में उतारा था. चौपालों से लेकर चौराहों तक गांव के हाट से लेकर शहरों के मॉल तक नेता ही नेता नज़र आते थे, लेकिन बाज़ी समाजवादी पार्टी के हाथ लग गई. हार ने कांग्रेस और भाजपा में हड़कंप पैदा कर दिया. जो नेता जीत के बड़े-बड़े दावे कर रहे थे वह पार्टी की हार के बाद नदारत हो गए. उत्तर प्रदेश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने ज़रूर हार की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया. इसी के साथ ख़त्म हो गया राजनीति का एक अध्याय. निकाय चुनाव के साथ कांग्रेस और भाजपा को नई शुरुआत करना है, लेकिन दोनों दलों के नेता सपा फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बसपा निकाय चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर समाजवादी पार्टी को वॉक ओवर दे चुकी है, लगता है कि पस्त कांग्रेसी और भाजपाई नो बॉल करके सपा को निकाय चुनाव में फ़्री हिट लगाने का मौक़ा देने का मन बना चुके हैं. दोनों ही दल नेतृत्व के अभाव से जूझ रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता जब हार के सदमें से उबरे तो पार्टी में नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई. नया अध्यक्ष जल्द चुनना ज़रूरी था, क्योंकि नगर निकाय चुनाव सिर पर थे. दोनों ही दलों के आलाकमान विधानसभा चुनाव में मिली हार के आंसू निकाय चुनावों में पोंछ लेना चाहता है. इसके लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों को ही किसी तेज तर्रार नेता की ज़रूरत थी. कई नाम तलाशे गए, लेकिन पार्टी से अधिक होशियार नेता निकले. भाजपा और कांग्रेस आलाकमान को पार्टी को आगे ले जाने की चिंता थी तो दोनों दलों के उन नेताओं को जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे आया था, इस बात का डर था कि निकाय चुनाव में भी पार्टी का विधानसभा चुनाव जैसा हश्र हुआ तो उनका राजनीतिक करियर ख़तरे में पड़ जाएगा. नेताओं की इसी सोच ने दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को संकट में डाल दिया. खैर, भाजपा आलाकमान ने तो किसी तरह से एक गुमनाम चेहरे को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली, लेकिन कांग्रेस के लिए नए अध्यक्ष की तलाश मुसीबत बनी हुई है. रीता बहुगुणा जोशी जो अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुकी हैं और केयरटेकर अध्यक्ष के रूप में कुर्सी पर विराजमान हैं, निकाय चुनाव से पहले किसी भी तरह से वो इस दायित्व से छुटकारा पा लेना चाहती हैं. कांग्रेस आलाकमान निकाय चुनाव तक रीता को ही अजमाने को आतुर है. उसे पता है कि निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का हश्र भी विधानसभा चुनाव से कुछ अलग नहीं रहेगा. इसी लिए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रीता के ऊपर निकाय चुनाव का भी ठीकरा फोड़ देना चाहता है, ताकि जब नया अध्यक्ष आए तो उसे काम करने के लिए समय मिले. निकाय चुनाव के बाद वैसे भी 2014 में लोकसभा चुनाव ही होने हैं.

दरअसल, विधानसभा चुनाव में अपनी शर्मनाक हार के बाद भी कांग्रेस आगे की लड़ाई के लिए तैयार नहीं दिख रही है. प्रदेश के सभी प्रमुख दलों ने जहां चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी को चुस्त दुरूस्त करना शुरू कर दिया है, वहीं प्रदेश कांग्रेस का संगठन चुनाव के बाद और भी पीछे चला गया है. ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी हताश दिखी. चुनाव संपन्न होने के क़रीब दो माह बाद 30 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी पहुंचे, तो उनके चेहरे से तेज और उत्साह दोनों ग़ायब थे, उनकी बातों में वह दम नहीं दिख रहा था जो चुनाव के समय था. आज भी वह पार्टी के लिए युवराज से अधिक कुछ नहीं हैं. यही वजह थी कि राहुल के तीन दिवसीय अमेठी दौरे की जानकारी पार्टी मुख्यालय में पहुंची ही नहीं, अगर पंहुची भी तो बहुत देर से. हाल यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की हार से उबरकर निकाय चुनाव से लेकर आगे की रणनीति के बारे में पार्टी के दिशा निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया है. जब सेनापति ही तय नहीं है तो सेना किस तरफ जाएगी यह समझा जा सकता है. ऐसे माहौल में हार निश्चित होती है. पार्टी के मीडिया प्रभारी सिराज मेहंदी से जब पूछा गया तो उन्होंने दबी जुबान से कहा कि हम लोग पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं में उत्साह हैं और सभी पूरी ताक़त से निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं. बात कांग्रेस आलाकमान के लचीलेपन की कि जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी आलाकमान ने एके एंटनी के नेतृत्व में शीला दीक्षित, सुशील कुमार शिंदे के साथ जो कमेटी बनाई थी, वह भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. जबकि प्रदेश कांग्रेस के नेता कमेटी को संगठन और चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी दे चुके हैं. पर अभी तक प्रदेश में कोई ठोस पहल नहीं की गई है. इससे पार्टी अलाकमान कि इच्छाशक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार की मुख्य वजह कमजोर संगठन और नेतृत्व दोनों रहा था. सामंजस्य के अभाव ने रही सही कसर पूरी कर दी. संगठन, नेतृत्व और सामंजस्य के अभाव जैसी खामियां जगजाहिर थीं. दूसरे चुनाव में कांग्रेसी नेता तत्कालीन बसपा सरकार की मुखिया मायावती से कम सपा प्रमुख मुलायम सिंह से ज़्यादा लड़े. रणनीति बनाते समय यह भी ध्यान रख गया कि जनता का आक्रोश माया सरकार के ख़िलाफ़ उबाल ले रहा था. कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी वास्तविक पहचान को छिपा और राजनीतिक संस्कृति को छोड़ बेवजह गुस्सा दिखाते रहे. शायद, वह बिहार वाली अपनी छवि को धोना चाहते थे. इसका कांग्रेस को फ़ायदा कम नुक़सान ज़्यादा हुआ. राहुल की यह छवि किसने गढ़ी पता नहीं? पर दाढ़ी बढ़ाकर कुर्ते की बाहें मोड़ते हुए आक्रामक अंदाज़ में उतर आना प्रदेश की उस नौजवान पीढ़ी के लिए आसानी से गले उतरने वाला नहीं था, जिसने राहुल गांधी को हमेशा बहुत ही सौम्य और सहज अंदाज़ में देखा था. मामला यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि राहुल गांधी ने नेहरू-गांधी परिवार के राजनीतिक संस्कृति की सीमा तोड़कर मायावती और मुलायम पर हमला किया. एक को भ्रष्ट तो दूसरे को गुंडा बताना कम से कम उन लोगों को रास नहीं आया, जिनके ये दोनों नेता नायक रहे हैं. केंद्र में कांग्रेस जिस तरह घोटालों से घिरी उसको देखते हुए राहुल गांधी के ये मुद्दे भोथरे साबित हुए. इसके अलावा कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए बहुत देर में और कमजोर नेतृत्व के साथ मैदान में उतरी थी. दावा सरकार बनाने का था. पर पार्टी संगठन ज़मीन पर कम मीडिया में ज़्यादा था. आज भी कमोबेश वही स्थिति है. राहुल की राजनीतिक रणनीति और प्रदेश नेतृत्व के सवाल पर कुछ भी साफ़ नहीं है. पार्टी के एक नेता ने नाम न लेने की शर्त पर कहा राहुल गांधी जब तक लखनऊ में अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे, पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी. दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है. उन्हें इस मामले में अखिलेश यादव के संगठनिक कौशल से सबक लेना चाहिए, जिसने डिंपल यादव की हार से सबक लिया और ज़मीनी लड़ाई लड़ी. सपा को फर्श से उठा कर अर्श पर पहुंचा दिया, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को लोग बूढ़ा कह रहे थे, उसने साबित कर दिया कि शेर, शेर ही रहता है चाहें वह कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए. ■

भाजपा और कांग्रेस आलाकमान को पार्टी को आगे ले जाने की चिंता थी तो दोनों दलों के उन नेताओं को जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे आया था, इस बात का डर था कि निकाय चुनाव में भी पार्टी का विधान सभा चुनाव जैसा हश्र हुआ तो उनका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाएगा. नेताओं की इसी सोच ने दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को संकट में डाल दिया. खैर, भाजपा आलाकमान ने तो किसी तरह से एक गुमनाम चेहरे को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली, लेकिन कांग्रेस के लिए नये अध्यक्ष की तलाश मुसीबत बनी हुई है. रीता बहुगुणा जोशी जो अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और केयरटेकर अध्यक्ष के रूप में कुर्सी पर विराजमान हैं निकाय चुनाव से पहले किसी भी तरह से वो इस दायित्व से छुटकारा पा लेना चाहती हैं.

तहज़ीब के शहर में इमाम-ए-हरम

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों मेहमाननवाज़ी में भी पीछे नहीं दिख रहे हैं. वह देश के सबसे बड़े सूबे के ऐसे मुख्यमंत्री बन गये हैं, जिन्हें चंद ही दिनों में दुनिया के लोग जानने-पहचानने लगे हैं. चाहे कोई देश का हो या विदेश का अखिलेश सभी से तहेदिल से मिलते हैं. और गंभीरता से उनके साथ गुफ्तगूं करते हैं. हाल ही में तहज़ीब के शहर लखनऊ में एक जलसे में शिरकत करने सऊदी अरब के इमाम-ए-हरम मौलाना शेख खालिद बिन अली अल गागद पंहुचे तो वजीरे आला ने उनके आगे पलक पावड़े बिछा दिये. उनके आने की खबर पाते ही अखिलेश खुद अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे और इमाम ए हरम की अगवानी की. मुख्यमंत्री साथ अगवानी करने प्रोटोकाल मंत्री अभिषेक मिश्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन, नदवा के प्रधानाचार्य मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, मोलाना खलिद रशीद फरंगी महली भी एयरपोर्ट पहुंचे.

इमाम ए हरम लखनऊ के ताज होटल में ठहरे .वहां उनसे मुलाकात करने काशीपीठ के स्वामी ज्ञान चैतन्य, स्वामी रवीन्द्र सरन, सिराज मेहंदी सहित शहर के कई गणमान्य प्रतिनिधि पहुंचे. सुबह मौलाना गामदी नदवा गये, जहां उनका स्वागत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष व नदवा प्रमुख मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने किया. इमाम ए हरम ने नदवा के छात्रों को पुरस्कृत किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि माफ करने का मतलब है कि दूसरों में कमियां मत खोजो, बल्कि अच्छाइयों पर नज़र रखो, क्योंकि कोई भी शख्स संपूर्ण नहीं है. अच्छा बर्ताव इस्लाम की शिक्षाओं की रूह है. ग़लती करने वालों को नरमी से समझाना हमारा फर्ज़ है. अमल बिन मारूफ यानि भलाई का हुक्म इस्लाम का सबसे पसंदीदा काम है. दूसरों की भलाई का जज्बा दिल में हमेशा रहना चाहिए. समारोह की अध्यक्षता करते हुए मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने कहा कि अच्छा बर्ताव आज की ज़रूरत हैं. इस्लाम पूरी दुनिया में अच्छे अख़लाक की वजह से फैला है. नदवा के प्रधानाचार्य मौलाना सइदुर्रहमान आजमी नदवी ने इमामे हरम की बातों पर अमल करने की अपील की. मौलाना सलमान नदवी ने इमामे हरम को नदवा के कार्यो के बारे में बताया. इमामे हरम ने नदवा में जोहर की नमाज भी अदा कराई. वहीं सायंकाल को इमामे हरम ने पुनः नदवा जाकर मगरिब व ईशा की नमाज अदा कराई. बहरहाल अदब के शहर में आकर गामदी बेहद खुश हुए. उन्होंने लखनऊ को इल्म-ओ-अदब का शहर बताते हुए कहा कि यह अल्लाह का शुक्र है कि उसने उन्हें यह शरफ बख्शा है. उन्होंने शहर के उलेमा और अन्य बुद्धिजीवियों का शुक्रिया अदा किया. ■

बदहाल अयोध्या

राकेश कुमार यादव
feedback@chauthiduniya.com

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्म भूमि अयोध्या को लेकर देश वासियों के मन में जो छवि बनी हुई है, वह छवि अयोध्या आने के बाद चूर-चूर हो जाती है. अयोध्या के नाम पर की जा रही राजनीति ही इसके लिए जिम्मेदार है. कई वर्षों से रेल मंत्रालय अयोध्या रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने की घोषणा अमूमन हर रेल बजट में करता रहा है, परन्तु इस स्टेशन पर वर्षों से आने वाले लोगों को कहीं से यह नहीं लगता कि रंग रोगन, कुर्सियों के अतिरिक्त इस स्टेशन पर कुछ और विकास कार्य हुए हैं? रेल विभाग ने कुछ नई गाड़ियां जरूर चलायी हैं मग़र उनमें से अधिकांश अयोध्या में न रूक कर यहां से 10 किमी दूर फैज़ाबाद में रूकती हैं. जब लोकपति त्रिपाठी रेल मंत्री थे तो उन्होंने स्टेशन की दुर्दशा को संवारने के नाम पर एक मंदिर नुमा गुम्बद वाला भवन बनवा दिया था. इसे रेलवे यात्री निवास पंचवटी के नाम से जाना जाता है आज यह कूड़े-करकट का ढेर बनकर रह गया है. अधिकांश समय यहां पीएसी के जवान डेरा डाले रहते हैं. लाखों की लागत से निर्मित इस आवास का उपयोग यात्रियों ने कब किया यहां रहने वालों को याद भी नहीं है. विकास का ढ़िढ़ोरा पीटने वाला रेल विभाग स्टेशन से निकलने वाले द्वार या सड़क का निर्माण आज तक नहीं करा सका है. यह सड़क आज भी गड्ढेदार ही नजर आती है. इस सड़क से बरसात के दिनों में गुजरना मुश्किल हो जाता है. रेल विभाग के उच्चाधिकारी बार-बार अयोध्या का भ्रमण करके इसके प्लेट फार्म की सफाई रंग रोगन व्यवस्था की बात करते हैं पर यहां से जाते ही भूल जाते हैं. आज भी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सुदूर दक्षिण या पश्चिम से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए साफ-सुथरी व्यवस्था का अभाव है. मेले के दौरान अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रेल विभाग द्वारा अतिरिक्त ट्रेन तक नहीं चलायी जाती. लोगों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ता है. अयोध्या में सर्वसुविधा युक्त बस स्टैंड के निर्माण की बात अयोध्या आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी परिवहन मंत्री करते रहे हैं पर यहां से जाने के बाद अयोध्या बस स्टेशन के निर्माण की बात दब कर रह जाती है. यही वजह है कि आज तक अयोध्या आने वाले यात्रियों को फैज़ाबाद से बस पकड़नी पड़ती है. ऐसी समस्याओं की वजह से अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों,श्रद्धालुओं को ऑटो टैक्सी चालकों के आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है. अयोध्या में कुछ पंडे तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं से हर तरह से फायदा उठाते हैं क्योंकि ये पंडे यात्रियों को धर्मशाला में रुकवाने के एवज में धर्मशाला के प्रबन्धकों से भारी भरकम कमीशन तो पाते ही हैं साथ ही ऑटो टैक्सी चालकों से भी कमीशन पाते हैं. इसके बावजूद यात्रियों को तीर्थयात्रा के नाम पर पंडों को दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है. ऐसा न करने पर यात्रियों को बदइंतजामियों का शिकार होना पड़ता है. इसमें यात्रियों की मदद स्थानीय पुलिस भी नहीं करती है. अयोध्या की ऐतिहासिकता एवं पौराणिकता का बखान करने में प्रदेश का पर्यटन विभाग बेहद उदासीन है. कहने को यहां क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का कार्यालय है. लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहर यात्री सुविधा के लिये स्थापित पर्यटन केंद्र अक्सर बन्द रहता है. यहां अयोध्या के नाम पर कोई प्रचार साहित्य उपलब्ध नहीं है. अयोध्या में पर्यटन विकास के नाम पर बने यात्री निवास सूने पड़े रहते हैं, जबकि यहां की निजी धर्मशालाओं और होटलों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है.

अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने के लिये आज तक पर्यटन विभाग टूरिस्ट गाइड की योजना पर अमल नहीं कर सका है. इसका परिणाम यह है कि लोगों को अयोध्या के संबंध में अधूरी और त्रुटिपूर्ण जानकारी मिल पाती है. यहां गाइड काम भी पंड़े ही करते हैं. ये गाइड पंडे श्रद्धालुओं को मन गढन्त इतिहास बताकर मंदिरों में दर्शन कराने ले जाते हैं. इन्हें अयोध्या के मन्दिरों के वास्तविक इतिहास की जानकारी नहीं होती है. अयोध्या की साफ-सफाई, सड़कें, प्रकाश व्यवस्था के लिये जिम्मेदार विभागों में नगर पालिका अयोध्या, विद्युत विभाग तथा अयोध्या-फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका प्रमुख है. करोड़ों खर्च होने के बाद भी अयोध्या में सबसे बड़ी लूट का शिकार यहां की राम की पैड़ी हुई है. जो आये दिन सफाई को लेकर ही चर्चा में रहती है. वहीं अयोध्या विकास के नाम पर आने वाले करोड़ों की धनराशि की बंदरबांट हो जाती है, अयोध्या को मिलता है घटिया निर्माण, गन्दगी, कूड़े के ढेर, टूटी सड़कों का जाल. मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सरकार का अयोध्या पैकेज या मायावती सरकार का अयोध्या पैकेज सभी में लूट हुई, लेकिन यहां की योजनाएं आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं. स्थानीय प्रशासन की कृपा से अयोध्या के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण गंदगी व दुकानों के नाम पर झोपडियां दिखायी देती हैं जिसे देखकर यात्री आश्चर्य चकित रह जाते हैं. ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या में यात्रियों के देखने के लिए रामलला के अलावा और कुछ नहीं है. आज भी यहां हनुमानगढ़ी, लक्ष्मण किला, दिगम्बर जैन मंदिर, राजघाट पार्क, नागेश्वरनाथ मंदिर, श्वेताम्बर जैन दिगम्बर जैन मंदिर, मणि पर्वत, सूर्यकुंड, हनुमानबाग, राम हर्षण कथा मंडप, चित्रगुप्त मंदिर, छोटी देवकाली, गुप्तारघाट, कोरिया पार्क, राज सदन, शिरडी सांई मंदिर, बिडला मंदिर, जैसे मंदिर पार्क और कुंड हैं. इन्हें दिखाने के लिए न तो यहां के पंडों के पास समय होता है न ही सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास करती दिख रही है. ■

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आगरा महत्वपूर्ण

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामसकल गुर्जर विधानपरिषद् सद्स्य के रूप में निर्वाचित किये गये हैं. उन्हें प्रदेश में सपा सुप्रीमों के सबसे करीबी और विश्वसनीय व्यक्तियों में माना जाता है. बीस वर्ष तक पार्टी और जनता की सेवा का प्रतिफल उन्हें एमएलसी बनाकर दिया गया है. सपा सुप्रीमों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टीम में उन्हें युवा गुर्जर नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. उनसे श्रीनिवास ठाकुर ने बातचीत की प्रस्तुत है प्रमुख अंश-

विधान परिषद् सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है, इस जिम्मेदारी का निर्वाहन आप कैसे करेगें ?

नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने उत्तर प्रदेश की कमान युवा अखिलेश यादव को सौंपी तो प्रदेश में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया, ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है. उन्होनें जनता दरबार लगाकर सरकारी योजनाओं को अमल में लाने का काम शुरू कर दिया है. आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विशेष दर्जा दिलाने के लिये मुख्यमंत्री जी उत्सुक हैं. इसके अलावा तमाम विकास योजनायें लागू की जा रही हैं. सभी योजनाओं का लाभ आगरा को भी मिले, इसके लिये मैं जी जान से जुटा हुआ हूं.

आगरा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नौ में से मात्र एक सीट पर विजय मिली,इस विषय में आपका क्या मत है?

मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, आप कह सकते है कि हमें सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन यदि आप मतदाताओं की बात करें तो हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ा है. दूसरी पार्टियों का प्रतिशत घटा है. फतेहाबाद सीट पर हम केवल पांच सौ मत से हार गये. बसपा ने विधानसभा सूचियों मे गड़बड़ी करके फर्जी वोट डलवाये. जनता ने सपा को भरपूर सहयोग दिया, इसके लिये हम पूरे प्रदेश की जनता के आभारी है. हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे.

सभी राजनीतिक दलों ने ताजनगरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और विकास के नाम पर कई और वायदे तो किये,लेकिन क्या हुआ?

अभी उत्तर प्रदेश की सरकार को बने दो माह भी नहीं हुये हैं. मुख्यमंत्री जी को आगरा की जनता की मांगों का ध्यान है, वह इस पर ध्यान दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिये मुख्यमंत्री जी ने सर्वे रिपोर्ट तलब की है, चूंकि इसका संबंध केन्द्र सरकार से है, इसलिये रिपोर्ट आने के बाद ही केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी.

विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रत्याशियों ने टोरंट कंपनी का मुद्दा उठाया था. अब आप की सरकार बन गयी है तो जनता के उत्पीड़न को रोकने के लिये टोरंट के विरूद्ध क्या कदम उठाए जायेंगे ?

पार्टी के घोषणापत्र में ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया है. आगरा के प्रत्याशियों ने निजी तौर पर ऐसा वायदा किया था. लेकिन फिर भी टोरंट कंपनी द्वारा किया गया किसी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. मुझे जब इसकी जानकारी हुयी तो मैंने टोरंट अधिकारियों को बुलाकर कह दिया कि सुधार न होने पर वो अंजाम भुगतने के लिये तैयार रहें. मुख्यमंत्री जी ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिये कॉल सेंटर की स्थापना की है. अब जनता की समस्यायें सीधे सरकार तक पहुंच सकेंगी.

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या-क्या योजना हैं?

उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनते हुये देखना चाहती है. हम सभी का भी यही प्रयास है इसके लिये सभी पार्टी अधिकारी, जनप्रतिनिधि एंव कार्यकर्ता जी जान से पार्टी के लिये काम कर रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आगरा में टोरंट की लूट

श्रीनिवास ठाकुर
feedback@chauthiduniya.com

टोरंट पॉवर की कारगुजारियों से ताजनगरी के वाशिंदों का हाल बेहाल है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगरा को 24 घटें विद्युत सप्लाई का आदेश दिये जाने के कई साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. आगरा में विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा दो वर्ष पूर्व एक अप्रैल 2010 को टोरंट पॉवर को फ्रैंचाइजी दी गई थी. गौरतलब है कि कंपनी को चार साल तक ट्रायल पर काम करने की अनुमति दी गयी है, इसे अभी तक विधिवत लाइसेंस भी नहीं दिया गया है. दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्व वसूली में असमर्थ साबित हो रहा था. सुस्त और बीमार सरकारी तंत्र से तंग आकर बसपा सरकार ने बेहतर विद्युत व्यवस्था और राजस्व वसूली के लिये निजी क्षेत्र के हांथों में विद्युत वितरण देने का फैसला किया था. उत्तर प्रदेश में इसकी शुरूआत आगरा से की गयी. बसपा सरकार के फैसले का विरोध सरकारी विद्युत कर्मचारियों ने किया था. शहर की जनता भी निजी क्षेत्र के हाथों में विद्युत वितरण दिये जाने के पक्ष में नहीं थी. भारी विरोध के बावजूद टोंरट पॉवर को आगरा का कांन्टेक्ट दिया गया. कहा जा रहा था कि इसके पीछे अरबों रूपयों का खेल हुआ. टोरंट ने आगरा की कमान संभालते हुये घोषणा की थी कि दो साल में विद्युत व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिये जायेंगे. 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के साथ जगह-जगह अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर लगाये जायेंगे. अधिक लोड के कारण बार-बार ट्रांसफार्मर खराब न हों और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो. अंडरग्राउड विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करके आंधी-तूफान, बरसात के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा न हो. कंपनी के काम शुरु करने के दो साल बाद इंफ्रास्टक्चर मजबूत हुआ, साथ ही राजस्व वसूली में 33 फीसदी का भी इजाफा भी हुआ. लेकिन,उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं हो पायी है. जब शहर की जिम्मेदारी डीवीएनएल के हाथों में थी तब भी आगरावासियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी. आश्चर्यजनक रूप से डीवीएनएल के रिकार्ड में 24 घंटे विद्युत दी जा रही थी. उच्चतम न्यायालय के आदेश को किस तरह सरकारी संस्था द्वारा साफतौर पर अनदेखा किया जा रहा था, वो किसी से छुपा नहीं है. इस बावत शिकायत भी की गयी थी लेकिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी जानकारी संभवतः किसी को नहीं है. लेकिन,सरकारी फाइलों में सब कुछ ठीक चल रहा था. विद्युत आपूर्ति न होने के कई कारण गिनाकर जबाव तैयार किये जा रहे थे. मसलन,अधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर का खराब हो जाना, आंधी के कारण विद्युत तार का टूटना अथवा मेंटेनेंस की आड़ में आपूर्ति में बाधा होना दर्शाकर डीवीएनएल किसी तरह आदेश की अवहेलना से कागजी तौर पर बचने का इंतजाम करने में सफल रहा था.

पिछले दो साल में टोंरट कंपनी के विरूद्ध जनाक्रोष बढ़ता ही जा रहा है. कर्मचारियों ने चैकिंग के नाम पर पॉश कालोनियों में महिलाओं, बच्चों और बुर्जुगों को परेशान किया और उनसे अवैध वसूली भी की. महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, बदनामी के डर से उन्होनें शिकायत तक नहीं की. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में टोंरट कर्मियों की हरकतों के कारण कई बार मार-पीट की घटनाएं भी हुई. सामान्यत: बिजली चोरी उपभोक्ताओं के घरों में लगे विद्युत मीटर से की जाती है, यदि मीटर से कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो इसे चोरी नहीं माना जाता. लेकिन,कंपनी घरों में लगे बल्ब, पंखे, खराब उपकरण, बच्चों के खिलौनों आदि के आधार पर लोड तयकर विद्युत चोरी का मामला बनाये जाने की शिकायतें मिल रही है. यह विद्युत अधिनियम के सभी नियमों के विपरित है. कंपनी कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तलाशी वांरट के बग़ैर लोगों के घरों में जबरन घुसकर नागरिकों की निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कर्मचारी अचानक घरों के बेडरूम तक चले आते है, इस संबध में लोगों द्वारा समय समय पर शिकायत की जाती रही है. कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है. वसूली के लिये फर्जी पुलिस अधिकारियों द्वारा डराने-धमकाने की भी सूचना मिली है. शहर के लगभग तीन हजार उपभोक्ताओं पर एक लाख से दस लाख तक का जुर्माना थोप दिया गया है. इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा लोड बढ़वाने के लिये कंपनी में पैसे जमा कर दिए गए हैं, लेकिन उन पर भी जुर्माना लगा दिया गया है. कनेक्शन काटने, एफआईआर दर्ज कराने, मीटर सील करने का डर दिखाकर कई कागजों पर हस्ताक्षर कराके धन की उगाही भी कंपनी कर रही है. बढ़े हुये बिल की शिकायत करने पर लोगों के बिल में पचास से साठ फीसदी तक की कटौती की गयी. इसी तरह के एक मामले में उपभोकता फोरम ने टोरंट को विभव नगर आगरा के निवासी रहीसुद्दीन के नाम दिए गए 64923 रुपये के बिल को अवैध करार दिया और कंपनी को 22 दिन का नियत दर पर देय बिल का भुगतान लेने के लिए अधिकृत किया. इस तरह के कई मामले आगरा में सामने आए हैं. कंपनी ने अवैध रुप से लोगों से वसूली की कई मामलों में तो रसीद की जगह कागज पर सामान्य रुप से लिखकर दे दिया गया और यह कहा गया कि कंपनी द्वारा जो मीटर रीडिंग की गयी, वो सही है. आगरा में लगभग दो लाख अस्सी हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से एक लाख इक्तालीस हजार उपभोक्ताओं के पास एक किलोवॉट लोड के कनेक्शन हैं. पूरे शहर में 40 सब स्टेशन हैं. जिनकी कुल क्षमता 720 एमवीए है. लगभग आठ सौ से एक हजार शिकायतें रोज दर्ज हो रही हैं. विद्युत चोरी के चार हजार से भी ज्यादा मामले प्रकाश में आये है. कंपनी के अनुसार पचास फीसदी विद्युत चोरी की जा रही है. जबकि शहर को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिये 450 एमवीए की और आवश्यकता है. सबसे ज्यादा परेशानियां काजीपाड़ा फीडर, मंटोला फीडर, अजीजपुर फीडर, बैरक रोड फीडर और ग्वालियर रोड फीडर से आती है. मंटोला, काजीपाड़ा, मोहनपुरा के आसपास के क्षेत्र, प्रकाश नगर, बोदला क्षेत्र की बस्तियों, गोकुलपुरा, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, गढ़ीभदौरिया, देवरिया रोड, औलिया रोड, गोपालपुरा, बुन्दुकटरा आदि स्थानों पर जनप्रतिरोध के कारण टोरंट विद्युत किराया वसूलने में नाकाम रही है, जिसका खामियाजा दूसरे शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है. कंपनी अपने घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों से अनाप-शनाप बिल वसूल रही है, जो अवैध है. ■

एनआरएचएम नियुक्तियों में धांधली

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत उत्तराखंड में संविदा पर हो रही नियुक्तियों में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उत्तरप्रदेश में घोटाले के लिए चर्चित हो चुकी यह योजना उत्तराखण्ड में भी इन दिनों चर्चा में है. इस मामले में शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जांच करने के निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के तहत संचालित भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तीन पद कार्यक्रम अधिकारी-शहरी स्वास्थ्य, कार्यक्रम अधिकारी-विद्यालयी स्वास्थ्य और कार्यक्रम अधिकारी-आरसीएच पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी. इन पदों के लिए महानिदेशालय में 4 नवम्बर 2011 को आठ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लिया गया था. परिणाम में संदेह होने पर एक अभ्यर्थी देवेंद्र कुमार बुड़ाकोटी ने सूचना के अधिकार के जरिए साक्षात्कार के पूरे दस्तावेज मांग लिए. दस्तावेजों की पड़ताल से पता चला कि साक्षात्कार में मूल्यांकन प्रपत्र पर जो अंकन किया गया उसमें मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं. बुड़ाकोटी को अनुभव के 20 में से केवल तीन अंक दिए गए जबकि साक्षात्कार में 25 में से दो अंक दिए गए. दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र कुमार बुड़ाकोटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए व एमफिल हैं और उनके शोधों का उल्लेख जाने-माने नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तकों में किया है. वह सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में शोध प्रबंधक, उप्र के परिवार नियोजन कार्यक्रम में अधिकारी, मलेशिया की पैन एशिया पैसिफिक संस्था में कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखंड स्वास्थ्य व परिवार कल्याण समिति में वरिष्ठ प्रबंधक, उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति में एनजीओ सलाहकार, हिमालयन अस्पताल में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के कार्यक्रमों के समन्वयक व सामाजिक संस्था हाईफीड के शहरी विकास कार्यक्रम के समन्वयक रह चुके हैं. देवेंद्र बुड़ाकोटी का कहना है कि उनके कई लेख देश के जाने-माने शोध जर्नलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं, इन सभी उपलब्धियों के बावजूद कम्यूनिकेशन स्किल में उन्हें 25 में से दो नम्बर दिए गए. इस सब से रुष्ट होकर देवेंद्र बुड़ाकोटी ने 16 जनवरी 2012 को तत्कालीन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के अलावा मिशन निदेशक एनआरएचएम और महानिदेशक स्वास्थ्य से चयन में धांधली की लिखित शिकायत की.

मिशन निदेशक और प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें प्रकरण से अवगत कराया. जब इससे कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने 13 मार्च को मुख्य सचिव से शिकायत की. तब भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने दो अप्रैल को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी को शिकायती पत्र दिया. देवेंद्र बुड़ाकोटी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पत्र लिखकर बताया है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जांच के लिए कहा गया है. नियुक्ति में हो रही धांधली का खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोग से हुआ है, यह कानून जनता के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अचूक हथियार सिद्ध हो रहा है. ■

दस्तावेजों की पड़ताल से पता चला कि साक्षात्कार में मूल्यांकन प्रपत्र पर जो अंकन किया गया उसमें मानकों की धज्जियां उड़ाई गईं हैं. बुड़ाकोटी को अनुभव के 20 में से केवल तीन अंक दिए गए जबकि साक्षात्कार में 25 में से दो अंक दिए गए.

केदारनाथ में कपाट खुलने के तीसरे दिन सोमवार को भी भारी बर्फबारी जारी रही इस कारण प्रशासन ने यात्रा गौरीकुंड में ही रोक दी.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

अव्यवस्था की शिकार होती

चारधाम यात्रा

केदारनाथ में मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया है. भारी बर्फबारी के बीच तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है. इस स्थिति में निजी कंपनियों के हेलीकाप्टर के लिए लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही है. खराब मौसम के कारण वहां खाद्यान्न के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है. जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि सेना की पांच सिख रेजीमेंट के कमान अधिकारी से वार्ता की गई है. उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत करा दिया है.

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

सरकारी बेरूखी और मौसम के कहर के कारण चारधाम यात्रा शुरुआत में ही अव्यवस्था का शिकार हो गई है. इन वजहों से अब तक आधा दर्जन तीर्थयात्री काल के गाल में समा गये हैं. देवभूमि के हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद नवगठित कांग्रेसी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसके ऐजेंडे में चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देना शुमार नहीं है.

सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनदेखी के कारण चारों धाम में बदइंतजामी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है. केदारनाथ में कपाट खुलने के तीसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी रही इस कारण प्रशासन ने यात्रा गौरीकुंड में ही रोक दी. खराब मौसम के कारण हेलीकाप्टर की लैडिंग भी संभव नहीं हो पा रही है. इस कारण वहां खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की आशंका पैदा हो गई है. हालात की गंभीरता को भांपते हुए प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है, ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारु रुप से की जा सके. उम्मीद जताई जा रही है कि सेना के हेलीकाप्टर जल्दी कार्य शुरू कर देंगे.केदारनाथ में मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया है. भारी बर्फबारी के बीच तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है. इस स्थिति में निजी कंपनियों के हेलीकाप्टर के लिए लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही है. खराब मौसम के कारण वहां खाद्यान्न के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है. जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि सेना की पांच सिख रेजीमेंट के कमान अधिकारी से वार्ता की गई है.

उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत करा दिया है.ऐसी स्थिति में राज्य सरकार राहत कार्य में की गई देरी लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है. सरकार ने गंगोत्री–यमुनोत्री और बद्रीनाथ मार्ग को अभी तक दुरूस्त नहीं किया है. यह कभी भी गम्भीर हादसे का कारण बन सकता है. साथ ही बद्रीनाथ में अधूरे निर्मित हैलीपैड में लैंडिंग की इज़ाजत देकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है. चारधाम यात्रा में फंसे यात्रियों से दुकानदार चीजों की मनमानी कीमत वसूल रहे हैं. प्रशासन ने अलाव जलाने की भी उचित व्यवस्था नहीं की है, जबकि प्रशासन को मौसम के खराब हो सकने की जानकारी पहले से थी. इसके बावजूद प्रशासन ने खराब मौसम से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं की है. ■

गंगा में राफ्टिंग कर प्रदूषण नापेंगे हिमवीर

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में शुरू हुए अभियान के तहत हिमवीर राफ्टिंग के मध्यम से एडवेंचर स्पोर्टस को बढ़ावा देंगे, साथ ही गंगा के प्रदूषण को भी नापेंगे. गोमुख से गंगानहर तक चलने वाले इस अभियान में हिमवीर लहरों को चीरते हुए एक जून को ऋषिकेश पहुंचेंगे जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. 1962 में गठित हुई आईटीबीपी अपने गठन के 50 वें वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इसकी शुरुआत रिवर राफ्टिंग अभियान से हो चुकी है. गंगा पुनर्दर्शन नाम से शुरू हुए इस अभियान में हिमवीर गोमुख से लेकर गंगानहर तक 2225 मील की दूरी तय करेंगे. इस अभियान के दौरान हर पांच किमी की दूरी पर गंगा के पानी और मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे. इसका उद्देश्य गंगा के प्रदूषण को जांचना है. इन सैंपलों का वैज्ञानिक परीक्षण होगा. आईटीबीपी के एक अधिकारी ने बताया कि एक मई को डीआईजी एसएस मिश्रा के नेतृत्व में राफ्टिंग टीम ऋषिकेश पहुंचेंगी. यहां अभियान समारोह में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे. इस दौरान गंगा संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित हुई चित्रकला प्रतियोगिता की चुनिंदा पेंटिगों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. 24 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले समारोह में अभियान की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी. ■

विकास के नाम पर अब नहीं उजड़ेगें जंगल

प्रदेश की नई सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों और एलीफेंट कोरिडॉरों पर बढ़ते अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है. हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने 700 एकड़ भूमि सेना को देने से मना कर दिया है. वन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि वह एलीफेंट और टाइगर कॉरीडोरों की जमीन अब विकास कार्य के लिए नहीं देगा. वन विभाग ने अब अपने फैसले पर अमल भी कर दिया है और इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र भी लिखा है. वन भूमि से जुड़े ऐसे ही एक मामले में सेना ने भी केंद्र सरकार से भारत–नेपाल सीमा पर निर्माण कार्य की इजाजत मांगी थी. सेना हल्द्वानी के करीब 700 एकड़ वन भूमि पर स्थायी निर्माण करना चाहती थी, लेकिन यह क्षेत्र बूम गलियारे के तहत आता है. इस मामले में वन विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से साफ कह दिया है कि यह क्षेत्र बहुमूल्य साल के पेड़ों का जंगल है.इन वनों का क्षेत्रफल प्रदेश में लगातार सिकुड रहा है. यही नहीं इस क्षेत्र को हाथी अपने आवागमन के लिए सदियों से इस्तेमाल करते रहे हैं. ऐसे में वन भूमि का आवंटन ठीक नहीं होगा. वन विभाग के केंद्र को दिए जवाब के बाद सेना ने एक अन्य विकास खंड में 700 एकड़ भूमि की मांग की लेकिन वन विभाग ने इसके लिए भी यह कहते हुए मना कर दिया कि यह क्षेत्र भी वनों का हिस्सा है और जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है. वन्यजीव प्रेमी राज्य के वन विभाग के नए रुख से खुश हैं, उनका कहना है आखिर वन विभाग को देर से ही सही वनों और जैव विविधता की याद तो आयी. उनका कहना है कि ऋषिकेश में आईपीपीएल और रायवाला में सेना की बसाहट व निर्माण, हरिद्वार की सिंचाई की नहरें और हरिद्वार व कोटद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास ने वनों के एलीफेंट और टाइगर कॉरिडोरों को लगभग खत्म कर दिया है. एक जमाने में राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जुड़े हुए थे और हाथी उसमें विचरण किया करते थे. लेकिन वनों के कम होने की वजह से हाथियों की आवा–जाही पर फर्क पड़ा है, और वह मानव बस्तियों में घुस रहे हैं. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के वनों में बिखराव उत्तर प्रदेश के जमाने से शुरू हुआ, क्योंकि वनों को तब बहुत महत्व नहीं दिया गया. वन भूमि क्षेत्र का विकास कार्य के लिए अंधाधुंध आवंटन के सभी फैसले तभी लिए गए थे जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था. उप्र की सरकार ने ही इन विकास कार्य के लिए वन भूमि देने का फैसला किया था. उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद भी वन भूमि की बंदरबाट जारी रही, सूबे के नये मुख्यमंत्री के वन, वन्यजीव प्रेम का साफ असर वनाधिकारीयों के फैसलों के रुप में दिखने लगा है.■

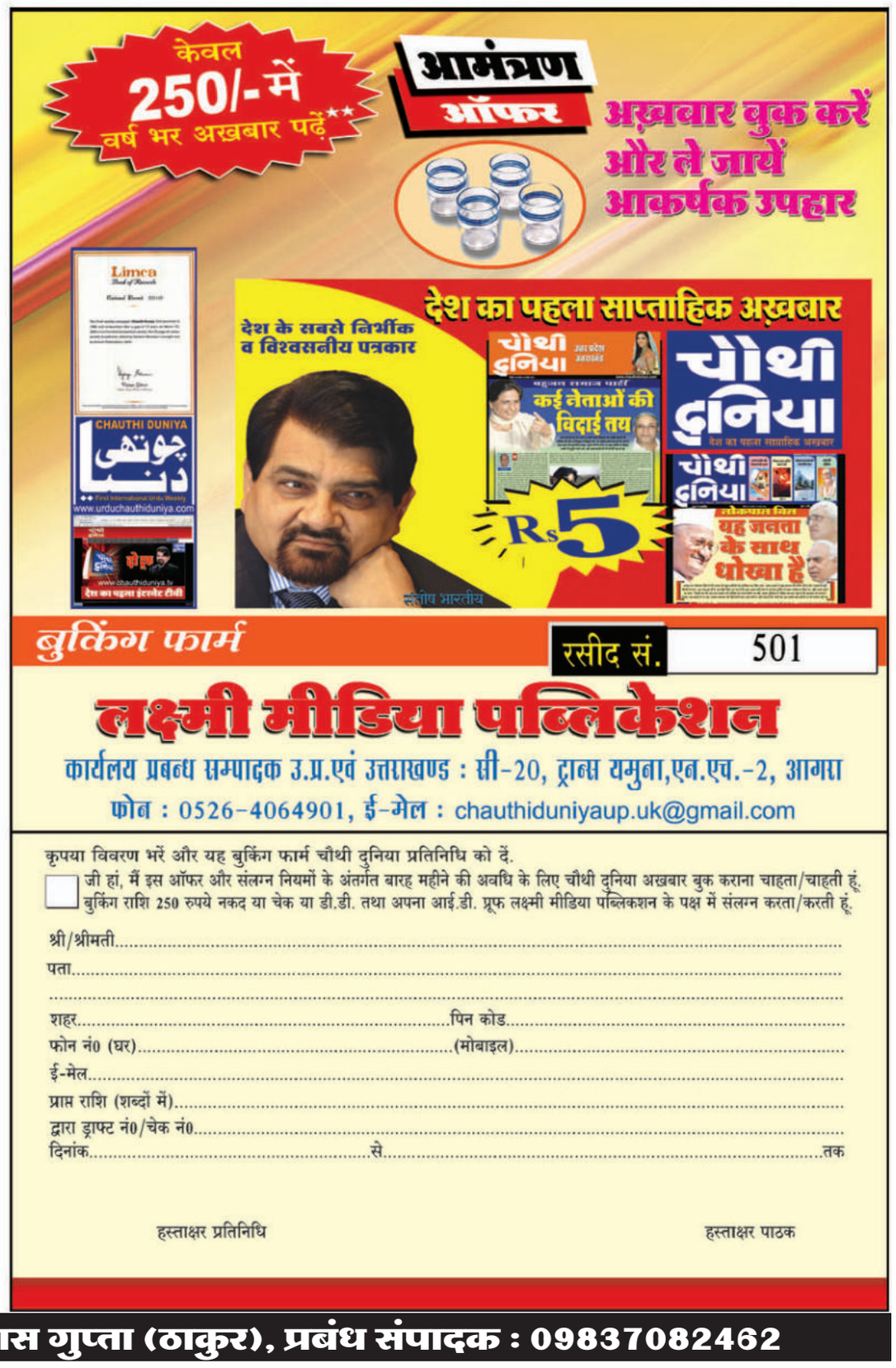

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर), प्रबंध संपादक : 09837082462